चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

10 नवंबर–16 नवंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

मेरठ दंगा

सरकारी जांच का सबसे शर्मनाक अध्याय है

मेरठ दंगा आज़ाद भारत में पुलिस की बर्बरता का सबसे घिनौना अध्याय है. लेकिन, इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इसके 26 साल बीत जाने के बाद भी किसी एक गुनहगार को सजा नहीं मिली. इससे भी ज़्यादा शर्मनाक यह है कि इस बात का भी पता नहीं चला कि पीएसी के जवानों ने मलियाना और हाशिमपुरा में मौत का जो तांडव किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया? किस अधिकारी या नेता ने इसकी मंजूरी दी थी? उन अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या यह संभव है, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार को 26 साल बाद भी हक़ीक़त का पता न चले? जब मेरठ में यह मौत का तांडव हुआ, तब देश का तमाम मीडिया चुप था. उस वक्त भी चौथी दुनिया अख़बार ने हाशिमपुरा की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई थी और आज भी यह अख़बार इस दंगे से जुड़ी नई जानकारियां लगातार अपने पाठकों तक पहुंचाता रहा है. इस रिपोर्ट में हम सीआईडी जांच की पोल खोल रहे हैं. इस रिपोर्ट से यह उजागर होता है कि किस तरह यह मामला पुलिसिया जांच का सबसे शर्मनाक अध्याय है.

मनीष कुमार

सरकार जिस तरह से मेरठ दंगों के मामले में न्याय दिलाने में विफल रही है, वह न सिर्फ़ शर्मनाक है, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए कहीं ज़्यादा दु:खदायी भी है. सरकार ने हाशिमपुरा दंगे में जो सीआईडी की जांच बैठाई, उसने अपना काम सही ढंग से नहीं किया. सच्चाई तो यह है कि जांच के नाम पर ही यह एक कलंक है. यह जांच किसने की, जांच सही ढंग से क्यों नहीं हो पाई, जांच का निष्कर्ष क्या निकला और क्यों बड़े-बड़े अपराधी छूट गए? इसके बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि उस मनहूस दिन यानी 22 मई, 1987 को हाशिमपुरा में क्या हुआ था.

शहर में दंगा हो रहा था. कर्फ्यू लगा था. लोग अपने घरों में ही थे. दोपहर क़रीब दो बजे सेना और पीएसी तलाशी के बहाने मुहल्ले में दाखिल हुई. पीएसी के जवान घर-घर में घुसे और जितने भी मर्द थे, उन्हें घर से बाहर आने को कहा. लोगों को बाहर निकालने के बाद पीएसी सबको मुजरिमों की तरह हाथ ऊपर कराकर सड़क पर ले आई. ऐसा लग रहा था कि पूरे मुहल्ले को ही गिरफ्तार कर लिया गया है. पीएसी ने बूढ़ों-बच्चों को अलग बैठाया और हट्टे-कट्टे नौजवानों को अलग. थोड़ी देर बाद बूढ़ों-बच्चों को छोड़ दिया गया. रात क़रीब आठ-साढ़े आठ बजे पीएसी का एक ट्रक आया. ट्रक के पीछे का दरवाजा खुला और वहां मौजूद लोगों को भेड़-बकरियों की तरह ट्रक के अंदर भर दिया गया. पीएसी वाले राइफलें लेकर पीछे खड़े हो गए और फिर उन्हें ट्रक के अंदर बैठा दिया गया. इसके बाद ट्रक चल पड़ा. जो भी पीछे मुड़कर देखना चाहता कि कहां जा रहे हैं, तो उस पर डंडे बरसाए जाते. ट्रक चलता रहा, काफ़ी देर तक चलता रहा.

ट्रक मुरादनगर के पास गंगनहर पर जाकर रुका. यहां बिल्कुल सन्नाटा था. पीएसी के जवान नीचे उतर गए. ट्रक की लाइट बंद कर दी गई और एक-एक करके लोगों को ट्रक से नीचे उतारा जाने लगा. जिसे नीचे उतारा जाता, उसे पीएसी के जवान गोली मार देते और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया जाता. एक के बाद एक को मौत के घाट उतारा जाने लगा. ट्रक में बैठे लोगों को जब यह समझ में आ गया कि इसी तरह सब मारे जाएंगे, तो उनमें भगदड़ मच गई. यह देख पीएसी के जवानों ने ट्रक के अंदर ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं. कुछ लोग कूद कर भागने लगे, तो पीएसी ने उन्हें खदेड़ कर गोलियां मारीं. पीएसी का मकसद साफ़ था कि एक भी व्यक्ति ज़िंदा न बचने पाए. वह गोली मारने के बाद लोगों को नहर में फेंक रही थी. पीएसी के जवानों ने तो अपने हिसाब से सबको मार दिया था. जब उन्हें यह यकीन हो गया कि अब कोई ज़िंदा नहीं बचा है, तो वे ट्रक में बैठकर वहां से चले गए. पीएसी को यह पता नहीं था कि भगदड़ के दौरान तीन लोग ज़िंदा बच गए. उन्हीं तीन लोगों यानी जुल्फिकार, नईम एवं बाबा ने ही दुनिया को इस घटना की पूरी हक़ीक़त बताई.

वैसे मेरठ में माहौल तनावपूर्ण रहना आम बात है. उस समय भी कुछ छोटी-मोटी घटनाओं की वजह से माहौल तनावपूर्ण था. इस दौरान पीएसी के एक वाहन से एक-दो लोग घायल हो गए. यह मेरठ दंगे का तात्कालिक कारण बन गया. दो दिनों के भीतर मेरठ के अलग-अलग इलाकों में हिंसा भड़क गई. चूंकि यह मामला पीएसी के वाहन से शुरू हुआ, तो मेरठ दंगे में पीएसी का रोल दंगा रोकने से ज़्यादा मुसलमानों को सबक सिखाने का हो गया. यह भी ख़बर आई कि हाशिमपुरा में किसी भाजपा नेता के भतीजे की मौत हो गई. वह अपनी छत पर खड़ा था और उसे गोली लग गई. लोगों का मानना था कि गोली दूसरे समुदाय की तरफ़ से चली. उसी के अगले दिन हाशिमपुरा में पीएसी ने नरसंहार को अंजाम दिया. भाजपा नेता के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मलियाना

अब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं

1983 के मेरठ दंगे के दौरान मलियाना शांत रहा. यहां हिंदू-मुसलमान हमेशा से साथ-साथ रहे हैं, लेकिन 1987 में अचानक यह अफवाह फैली कि मलियाना में गिरफ्तारियां होंगी. अफवाह उस वक्त सच साबित हो गई, जब पुलिस-पीएसी ने क़रीब ग्यारह बजे पूरे गांव को घेर लिया और तलाशी के नाम पर उसने लोगों को घरों से बाहर निकालना शुरू किया. पीएसी के जवान गोलियां चलाने लगे. तीन घंटे तक लगातार गोलियां चलती रहीं. पुलिस-पीएसी और दंगाइयों ने सबसे पहले सत्तार वल्द मोहम्मद अली के घर को लूटा. यहां पुलिस ने दहशत फैलाने के लिए एक घर को जला दिया. घर के साथ-साथ उसमें रहने वाले परिवार के छह सदस्य भी जलकर खाक हो गए. देखते ही देखते मलियाना गांव के सौ-सवा सौ घरों में आग लगा दी गई. क़रीब 73 लोग मारे गए. जबकि सरकारी आंकड़े यह संख्या बहुत ही कम बताते हैं. दंगाइयों में आसपास के अलावा बाहर के भी कई लोग थे. घटना के तुरंत बाद मोहम्मद याकूब ने थाने में एफआईआर की. सोचा कि कम से कम दंगाइयों को क़ानून से सज़ा मिल जाए. जिन पुलिस-पीएसी वालों ने बेगुनाहों की जान ली है, उन्हें सज़ा मिल जाए, लेकिन यह पता नहीं था कि इस दंगे से ज़्यादा गहरा घाव न्याय दिलाने वाले संघर्ष से मिलने वाला है. मलियाना के दंगे में 93 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई और 75 लोग गवाह बनाए गए थे. आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. घटना के बीस साल बाद कोर्ट से सम्मन आया कि मामले की सुनवाई होने वाली है. मलियाना के लोग अदालत पहुंचे, अपना वकील किया. जो कुछ कर सके, वह उन्होंने किया.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मांझी को डर लगता है

पेज-03

अगली सरकार पीडीपी-भाजपा की होगी!

पेज-05

सपा की बेचैनी बढ़ा रहा एमआईएम

पेज-07

साई की महिमा

पेज-12

मेरठ दंगा

सरकारी जांच का सबसे शर्मनाक अध्याय है

पृष्ठ एक का शेष

भतीजे की मौत और पीएसी की कार्रवाई में क्या कोई रिश्ता था, यह जांच रिपोर्ट में शामिल नहीं है. तफ्तीश में ये सारी बातें नहीं पहुंचीं.

सरकार ने जो जांच कराई, उसमें सिर्फ़ उन्हीं लोगों के नाम सामने आए, जो पीएसी की उस टुकड़ी में शामिल थे. उनमें से कई लोगों की मौत हो गई है. ज़्यादातर रिटायर हो गए हैं. उन पर मुकदमा चल रहा है. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1987 से लेकर आज तक लगभग 26 साल हो गए हैं, लेकिन मुकदमा किसी तार्किक नतीजे तक नहीं पहुंचा है. जो लोग इसमें शामिल थे, उन्हें सजा नहीं मिली. कुछ समय के लिए उन्हें सस्पेंड ज़रूर किया गया, लेकिन फिर से बहाल भी कर दिया गया. दरअसल, सीआईडी ने जो तफ्तीश की, वह जांच का सबसे बुरा नमूना है. बहुत ही खराब तरीके से इस दंगे की जांच हुई. कांग्रेस सरकार ने बहुत हल्के- फुल्के तरीके से इस मामले को डील किया. यह आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि किसके आदेश से और किस योजना के तहत आज़ाद भारत के इस सबसे जघन्य ज़ेरे हिरासत हत्याकांड (कस्टोडियल किलिंग) को अंजाम दिया गया. दंगे पर काबू पाने के लिए तैनात सुरक्षा बल किसी बस्ती में घुस जाए, मर्दों को घरों से बाहर निकाले, ट्रक में बैठाकर तक़रीबन 50 किलोमीटर दूर लेकर आ जाए, एक-एक करके सबको गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दे, इसके बाद उनकी लाशें नहर में फेंक दे और किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी भनक तक न लगे! यह विश्वास करने वाली बात नहीं है.

इतने सारे लोगों की हत्या की योजना बनाना और फ़ैसला करना सड़क पर तैनात सुरक्षाबल के किसी छोटे अधिकारी का काम नहीं हो

सकता. इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की हिमाकत कोई छोटा अधिकारी नहीं कर सकता. एक सब-इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी चालीस-पचास लोगों की हत्या की योजना बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता. इसका मतलब यही है कि हाशिमपुरा में तैनात पीएसी की टुकड़ी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन कर रही थी. वे अधिकारी, जो मौक़ा-ए-वारदात पर स्वयं मौजूद नहीं थे. इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि उन वरिष्ठ अधिकारियों ने इतनी बड़ी घटना की योजना किसी राजनीतिक संरक्षण के तहत बनाई और इसे अंजाम दिया. अगर यह योजना वरिष्ठ अधिकारियों ने बनाई थी, तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें सजा क्यों नहीं दी? इस घटना के बाद तो पीएसी और सेना का पूरा महकमा गिरफ्तार किया जाना चाहिए था. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सरकार ने सीआईडी को जांच की ज़िम्मेदारी दे दी और सीआईडी ने बड़ी आसानी से छोटे अधिकारियों को निशाना बनाया. उसने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि इस घटना के पीछे कौन था, किस बड़े अधिकारी या राजनेता का हाथ था?

हैरानी की बात यह है कि हाशिमपुरा नरसंहार की जांच कर रही सीआईडी टीम का नेतृत्व एक वरिष्ठ मुस्लिम पुलिस अधिकारी कर रहे थे. बताया जाता है कि वह जिन बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब करते, वे नहीं आते. इस घटना में सेना की भी भूमिका रही है, लेकिन एक भी सैन्य अधिकारी जांच टीम के सामने उपस्थित नहीं हुआ. दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को लाई-डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए. इससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं इस मामले की जांच की जानकारी समय-समय पर लेते रहते थे, इसके बावजूद जांच टीम ने एक हाफ-हार्टेड जांच की. बड़े और असली गुनहगार बच गए तथा सारा आरोप उन लोगों पर आ गया, जो सिर्फ़ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे थे. यह किस तरह की जांच है, जिसमें इस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों की फोरेंसिक जांच तक नहीं हो सकी. वे हथियार एक सुबूत थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के कुछ दिनों के बाद वे हथियार वापस पीएसी को दे दिए गए और उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई.

उस वक्त गाजियाबाद में तैनात आरक्षी अधीक्षक वी एन राय के मुताबिक, हाशिमपुरा के असल गुनहगारों की पहचान और इस मामले में किसी को सजा इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार में इच्छाशक्ति की कमी थी. अगर उसमें इच्छाशक्ति होती, तो सब पता चल जाता. वी एन राय ने हाशिमपुरा नरसंहार पर काफी रिसर्च की है और वह इसके हर पहलू से वाकिफ हैं. वह हाशिमपुरा पर एक किताब भी लिख रहे हैं. वह कहते हैं कि तब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और शीर्ष नेताओं में कोई सांप्रदायिक दुर्भाव भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक तबका इस पूरी घटना की लीपापोती करना चाहता था. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की प्राथमिकताएं कुछ और थीं, जिसकी वजह से गुनहगार छूट गए. राय उस दंगे की याद करते हुए कहते हैं कि वह दौर ऐसा था, जिसमें मीडिया का भी सांप्रदायिक चेहरा दिखाई दिया. हाशिमपुरा की ख़बर सबसे पहले एक राष्ट्रीय अख़बार को मिली. उस अख़बार में बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी हासिल करने के बाद भी ख़बर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई. वह कहते हैं कि सबसे पहले चौथी दुनिया ने हिम्मत दिखाई और इस दंगे की पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी. उसके बाद एशियन एज नामक अख़बार ने चौथी दुनिया से यह ख़बर उठाकर अपने यहां छापी.

हाशिमपुरा का मामला सबसे पहले गाज़ियाबाद की अदालत में पहुंचा. यहां यह मामला घिसट-घिसट कर चलता रहा. फिर इकबाल अंसारी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और इसका दिल्ली स्थानांतरण कराने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से कुछ तेजी आई. लेकिन, यहां भी तरह-तरह की रुकावटें आईं. जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर था, उसकी नियुक्ति में विवाद हुआ. कई लोग कहते हैं कि उसकी नियुक्ति ग़लत तरीके से हुई. जिन गवाहों को अदालत आना था, वे नहीं आए. सेना के गवाह तो अंत तक अदालत नहीं पहुंचे. किसी तरह से अदालत की कार्रवाई चलती रही. वर्तमान में हाशिमपुरा का मामला आख़िरी दौर में है. ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले का फ़ैसला तीन-चार महीने में आ जाएगा.

अगर न्याय में देरी का मतलब न्याय से वंचित होना है, तो हम कह सकते हैं कि मेरठ के मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है. इस दंगे की सबसे दर्दनाक दास्तां मलियाना और हाशिमपुरा में लिखी गई. खाकी वर्दी वालों का जुर्म हिटलर की नाजी आर्मी की याद दिलाता है. मलियाना और हाशिमपुरा की सच्चाई सुनकर रूह कांप जाती है. देश की क़ानून व्यवस्था पर यह एक ऐसा काला धब्बा है, जिस पर सहज विश्वास नहीं होता है. निहत्थे और मासूम लोगों को गोली मारने वाले गुनहगार आज़ाद घूम रहे हैं और जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को खो दिया, वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. ■

manishbph244@gmail.com

मलियाना

अब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

पहले ही दिन विपक्ष के वकील ने कहा कि इसमें एफआईआर नहीं है. जब तक एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं होगी, तब तक मुक़दमा नहीं चलेगा. उसके बाद जज ने पूछताछ की कि एफआईआर कहां है. वैसे तो यह ज़िम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए. फिर मलियाना के लोग थाने गए और उन्होंने 23 मई, 1987 को दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी. थानेदार ने कहा कि हमारे पास नहीं है. हम सिर्फ़ पांच साल का ही रिकॉर्ड रखते हैं. हम सारे काग़ज़ात अदालत में जमा करके साइन करा लेते हैं. अब तो हमारे पास न रिकॉर्ड है और न हम कुछ बता सकते हैं. यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक उस एफआईआर का पता नहीं चल सका. बिना एफआईआर के ही जज ने गवाही की इजाजत दे दी. फास्ट ट्रैक कोर्ट था, तो हर हफ्ते तारीख़ लगती थी, लेकिन एक साल तक एक ही आदमी की गवाही होती रही. फिर एक साल बाद दूसरी गवाही पेश की गई. अगर इसी तरह से गवाही चलती रही, तो फ़ैसला आते-आते पचहत्तर साल लग जाएंगे. पच्चीस साल ऐसे भी बीत चुके हैं. तब तक न तो कोई मुजरिम बचेगा और न कोई गवाह. इस मामले को फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. यहां फिर वही सवाल उठा कि एफआईआर कहां है? और, जज ने साफ़-साफ़ कह दिया कि बिना एफआईआर के सुनवाई नहीं होगी. इस मामले को पेंडिंग में डाल दिया गया. न तो नक़ल मिली है और न मुक़दमे की कोई सुनवाई हो रही है. मेरठ दंगे की यह हक़ीक़त देश का मीडिया जानता है, मुस्लिम वोटों के लिए सेकुलर बने राजनीतिक दल जानते हैं, दंगों के लिए लड़ने का दम्भ भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं, पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, राज्य सरकार जानती है, केंद्र सरकार जानती है, लेकिन सब चुप हैं. मलियाना के मुसलमानों को न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है. हाशिमपुरा के मामले में तो कम से कम सुनवाई हुई और कुछ महीने में फ़ैसला आने की उम्मीद भी है, लेकिन मलियाना के लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 36
दिल्ली, 10 नवंबर–16 नवंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सीबीआई निदेशक को लेकर ऊहापोह

विवाद में फंसे सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा का करियर गोधूलि बेला में प्रवेश कर चुका है. सरकार ने कथित तौर पर उनकी जगह भरने के लिए नया अधिकारी खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभयानंद, शरद कुमार, कृष्णा चौधरी, अनिल सिन्हा, अरूप पटनायक एवं केपी रघुवंशी की एक छह सदस्यीय चयन समिति गठित की गई है. लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है. यह सरकार के लिए दुविधा का विषय है. मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त या लोकपाल के सदस्यों के चयन के लिए ज़रूरी प्रावधानों के विपरीत, सीबीआई निदेशक के चयन पैनल में विपक्ष के नेता का भी होना ज़रूरी है. सूत्रों का कहना है कि आगामी दो दिसंबर को सिन्हा के रिटायरमेंट से पहले उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए सरकार को दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेबलिशमेंट एक्ट में संशोधन करना होगा. निश्चित रूप से, जब तक ऐसा नहीं होता है और यह पद रिक्त रहता है, तो इसके लिए सीबीआई के विशेष निदेशक एके सिन्हा को सीबीआई प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति देना ही बेहतर होगा. ■

सूचना आयुक्त की खोज

केंद्रीय सूचना आयुक्त के तीन रिक्त पदों के लिए कुछ ही लोगों ने आवेदन किया है. यह पद पूर्व बाबुओं को हमेशा अपनी ओर खींचता रहा है, लेकिन इस बार एक ही पूर्व बाबू यानी पूर्व विधि सचिव ब्रह्मदत्त अवतार अग्रवाल का नाम इस पद के लिए सुनने में आ रहा है.

सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य अग्रवाल भी केंद्रीय सूचना आयुक्त पद की दौड़ में हैं. यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जब वह विधि सचिव थे, तब वह री-एंप्लॉयमेंट को लेकर खासे उत्सुक थे और उन्होंने हर रिक्त पद के लिए आवेदन किया. अब देखना यह है कि वह अपने इस नए प्रयास में सफल होते हैं या नहीं. ■

दुर्गा दिल्ली जाएंगी

ईमानदार एवं दिलेर आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, जो पिछले साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार से उलझ गई थीं, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जा सकती हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह उन्हें अपने यहां ओएसडी के रूप में लाने के लिए उत्सुक हैं और इसके लिए उन्होंने कैडर एवं सतर्कता मंजूरी की मांग की है. हालांकि, पर्यवेक्षक कहते हैं कि यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी प्रतिनियुक्ति का रास्ता साफ़ करती है या नहीं. राज्य की वर्तमान सरकार के साथ नागपाल का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है. उन्हें जुलाई 2013 में निलंबित कर दिया गया था और एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक हंगामे के बाद ही उन्हें बहाल किया गया था. अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके केंद्र में जाने के रास्ते में बाधा बनते हैं या अतीत को भुलाकर आगे बढ़ते हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

ललित पर्यटन सचिव बने

1979 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी ललित कुमार पनवार को पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है. वह अरविंद मायाराम का स्थान लेंगे. इससे पहले ललित अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में काम कर रहे थे. वह एक साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

दुर्गा प्रसाद की वापसी

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा करने के बाद एसपीजी के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे दुर्गा प्रसाद अपने मूल कैडर में वापस चले गए हैं. वह तेलंगाना कैडर एवं 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.

ओम प्रकाश निदेशक बनेंगे

1983 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह एसपीजी के नए निदेशक बन सकते हैं. वह वर्तमान में सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

वट्टल वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त

वित्त मंत्रालय में हो रहे बड़े फेरबदल के क्रम में आरपी वट्टल को वित्तीय सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे. विट्टल 1978 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वट्टल ने 1980 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जीएस संधू का स्थान लिया है.

अरविंद अल्पसंख्यक मंत्रालय पहुंचे

1978 बैच एवं राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी और पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम को अल्पसंख्यक मंत्रालय में पदस्थ किया गया है. इससे पहले उन्हें पर्यटन सचिव के रूप में पदस्थ किया था, लेकिन अचानक उन्हें वहां से हटाकर अल्पसंख्यक मंत्रालय भेज दिया गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री ने जन–भागीदारी पर फोकस करते हुए कहा कि सही लोगों के चयन के लिए इस योजना की शुरुआत ऑनलाइन कंपटीशन द्वारा की गई है. इसके तहत ग्रामवासी स्वयं अपने कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का लक्ष्य तय करेंगे. खैर, यह तो आने वाला समयबताएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस प्रकार जनता से जुड़ती है और ज़मीनी सतह पर फ़ायदा पहुंचा पाती है? उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने छतरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली–रोहतक सीमा पर स्थित भट्टी गांव को गोद लेने की घोषणा की है, जो यहां का सबसे पिछड़ा गांव है.

सांसद आदर्श ग्राम योजना

बहुत कठिन है डगर पनघट की

ए.यू. आसिफ

बीते 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर की गई अपनी घोषणा के अनुसार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) लॉन्च की, जो निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण एवं असाधारण है. भारत के तमाम गांव आदर्श बनें, यह वह सपना है, जो स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था. गांव की हैसियत एवं अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि संविधान में भी इसे मान्यता दी गई है. इसी लिहाज से पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित है, जिसमें ग्राम पंचायत को बुनियादी हैसियत हासिल है. 1992 में भारतीय संविधान के तहत 73वें संशोधन द्वारा देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना शुरू हुई, ग्राम सभा उसका एक महत्वपूर्ण भाग है. ग्राम सभा का मतलब है कि व्यक्तियों के एक ऐसा समूह, जो गांव की सतह पर पंचायत क्षेत्र के अंदर गांव से संबंधित चुनावी सूची में पंजीकृत हो. एक ग्राम सभा किसी राज्य की विधायिका की तरह गांव के स्तर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है और अपना काम अंजाम दे सकती है. नए प्रावधानों के अनुसार, ग्राम सभा के अलावा महिला सभा एवं बाल सभा भी अस्तित्व में आ गई हैं. आइए, अब देखते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना आख़िर है क्या और यह कितनी व्यवहारिक है?

सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ऐसा मंसूबा है, जिसके अंतर्गत देश के हर सांसद को 2016 तक एक तथा 2019 तक दो और गांवों को गोद लेना है और उन्हें पूर्ण रूप से इसी अवधि में विकसित भी करना है. मतलब यह कि 2019 तक 2500 गांव लोकसभा एवं राज्यसभा के तमाम सदस्यों द्वारा उनकी सांसद निधि के इस्तेमाल से विकसित किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के तहत एक सांसद को यह आज़ादी है कि वह अपने क्षेत्र में अपनी पसंद के किसी गांव को गोद लेने के लिए चुने. लेकिन विडंबना तो यह है कि उक्त सांसद निधि का मतलब हमेशा यह समझा जाता है कि उससे निर्वाचित सांसद के क्षेत्र का ही विकास किया जाएगा. इस कार्यक्रम की मांग यह है कि योजना के क्रियान्वयन पर प्रगति की हमेशा निगरानी की जाए. प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में हो रहे विकास और वह किस प्रकार अपनी सांसद निधि प्रत्येक वर्ष खर्च कर रहा है, आदि जानकारियां राइट टू इंफॉर्मेशन (आरटीआई) से संबंधित नए नियमों की रोशनी में आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र संबंधी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी.

ग़ौरतलब है कि अभी हाल में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति सभी केंद्रीय

मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि सभी आरटीआई के उत्तरों एवं प्रथम अपीलें संबंधित मंत्रालय एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएं. एक सांसद जिस गांव को गोद लेने जा रहा है, वह पंचायती गांव होना चाहिए. यानी वह ऐसा गांव हो, जिस पर पंचायत का नाम रखा गया हो, जो आम तौर पर वहां का सबसे बड़ा गांव होता है. इस शर्त का कारण यह है कि इससे गांव एवं पंचायत दोनों स्तरों पर दो प्रकार का विकास दिखाई पड़ेगा. जाहिर–सी बात है कि इस प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं आरटीआई के नए नियमों से संबंधित सरकारी विज्ञप्ति की रोशनी में पूरे पंचायती गांव को वाई–फाई जोन बनाना पड़ेगा और इसके लिए पूरे पंचायती गांव को नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन (एनडीएमएल) के तहत पूरी तरह से डिजिटलाइज़ करना होगा.

इस पूरे मंसूबे को व्यवहारिक रूप देने के लिए अभी हाल में घोषित डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (डीआईपी) को सांसद आदर्श ग्राम योजना से भी जोड़ना होगा. इसी के साथ–साथ आरटीआई योजना को मतदाताओं के पास सकारात्मक जवाबदेही के दिशानिर्देश के सिद्धांतों के तौर पर ले जाना पड़ेगा. यह मानते हुए कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना एक–दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर हमारे देश में 2500 डिजिटल गांव अस्तित्व में आ जाएंगे, जहां ऐसे विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र होंगे, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टेड भी होंगे. इसके अलावा साइबर स्पेस पर तमाम संसदीय क्षेत्र मौजूद होंगे, जिससे इंफॉर्मेशन हाईवे पर भारत की मौजूदगी संभव हो सकेगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हाईटेक आदर्श गांव भारत जैसे देश में, जहां गांव अभी वर्तमान हाईफाई टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं, व्यवहारिक रूप ले पाएंगे? इसके साथ–साथ यह कटु सत्य भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि डिजिटल ढांचे के विभागों में फंड देने के लिए सांसद निधि के दिशानिर्देशों में गुंजाइश बहुत कम है. जब तक केंद्र सांसदों को दी जा रही धनराशि फिर से सुनियोजित नहीं करता, तब तक सांसद निधि बहुत ज़्यादा लाभदायक या उपयोगी नहीं हो सकती. ज़रूरत इस बात की है कि दिशानिर्देशों में पर्याप्त गुंजाइश हो, ताकि सांसद अपने क्षेत्रों में इस बावत बजट सुनिश्चित कर सकें. इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि देश की कुल दो लाख पचास हज़ार पंचायतों में इस समय हमारे लक्ष्य में शामिल 2500 गांव मात्र एक प्रतिशत के बराबर हैं. मतलब यह कि अगर हम 2500 पंचायती गांवों को पांच वर्षों में आदर्श गांव बनाने जा रहे हैं, तो देश के सभी दो लाख पचास हज़ार पंचायती गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श गांव बनाने में कई दशक लग जाएंगे. वैसे भी किसी मंसूबे पर जब सांसद से जुड़कर देखा जाता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि ये सांसद तो वही हैं, इनकी सांसद निधि भी वही है और गांव के विकास के लिए सरकारी योजनाएं भी कमोबेश वहीं हैं, तो फिर अचानक कोई जादू कहां से हो जाएगा? यह मंसूबा तभी व्यवहारिक रूप ले सकता है, जब इसे व्यवहारिक बनाया जाए, ज़मीनी सतह से जोड़ा जाए और वे लोग सांसद निर्वाचित हों, जिनमें समाज सेवा की सच्ची भावना हो. ग़ौरतलब है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन (11 अक्टूबर) के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने तीन विकसित गांवों का उदाहरण दिया, जिनमें एक स्वयं उनके अपने राज्य गुजरात में है पंसारी, जिसे देश का नंबर वन गांव कहा जाता है. दूसरा तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली और तीसरा महाराष्ट्र में हिवारे बाज़ार है. जाहिर–सी बात है कि ये तीनों एवं अन्य गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना से पहले स्थानीय निवासियों की मेहनत एवं लगन के परिणाम हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे गांवों ने अपने ग्रामीण इलाके हर तरह से विकसित कर दिए हैं और रोज़गार के लिए शहरों की ओर पलायन वहां बड़ी हद तक रुक गया है, लेकिन छात्रों–नौजवानों का करियर में बेहतरी और महारथ के लिए गांव से बाहर जाने का सिलसिला जारी है और आगे रहेगा भी.

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जन–भागीदारी पर फोकस करते हुए कहा कि सही लोगों के चयन के लिए इस योजना की शुरुआत ऑनलाइन कंपटीशन द्वारा की गई है. इसके तहत ग्रामवासी स्वयं अपने कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का लक्ष्य तय करेंगे. खैर, यह तो आने वाला समयबताएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस प्रकार जनता से जुड़ती है और ज़मीनी सतह पर फ़ायदा पहुंचा पाती है? उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने छतरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली–रोहतक सीमा पर स्थित भट्टी गांव को गोद लेने की घोषणा की है, जो यहां का सबसे पिछड़ा गांव है. सच तो यह है कि दिल्ली में इस प्रथम गांव का विकास इस योजना की प्रथम परीक्षा होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

मांझी को डर लगता है

सरोज सिंह

यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि निर्णय लेने में मुझे डर लगता है. कोई आम आदमी या फिर अधिकारी ऐसी बात कहे, तो कुछ देर के लिए समझ में आती है, पर खुद मुख्यमंत्री ऐसा कहें, तो लगता है, बात काफी गंभीर है. आख़िर मांझी के इस बयान के बाद सत्ता और सरकार का रास्ता जाता किधर है. क्या यह माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सत्ता की कोई ऐसी दूसरी ताकत है, जो मुख्यमंत्री को फ़ैसले लेने से रोक रही है? या फिर यह मान लिया जाए कि बिहार में सत्ता की गाड़ी बेपटरी हो गई है, हर कोई अपने–अपने हिसाब से फ़ैसले ले रहा है और यही बात मुख्यमंत्री को डरा रही है. सभी जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए आंकड़े चाहे कितने भी पक्ष में क्यों न हों, पर सत्ता हनक से चलती है. और, जब सरकार में हनक ही न हो, तो फिर कोई भी सरकार नहीं चल सकती. दरअसल, लगता है, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ तो ज़रूर गए हैं, पर यह कुर्सी खुद मांझी से कई सवाल रोज कर रही है. उन्हीं सवालों के जवाब देने में मांझी कुछ–न–कुछ बोले जा रहे हैं. मांझी खुद अपने बयान को अगले दिन काट देते हैं और जैसे ही उनका खंडन आता है, उनकी कुर्सी फिर उनसे दूसरा सवाल कर देती है और फिर वह उसका जवाब देते हैं, तो हंगामा मच जाता है.

मुख्यमंत्री के कुछ चर्चित बयानों पर ग़ौर करें. मांझी ने कहा कि अगली सरकार के नेता नीतीश कुमार होंगे. राजद ने इस बयान पर कड़ा विरोध जताया, तो उन्होंने अगले दिन कहा कि महा–गठबंधन के नेता मिलकर तय करेंगे कि अगला नेता कौन होगा. मांझी कहते हैं कि महादलित 22 फ़ीसद हैं, अगर वे एकजुट हो जाएं और ग़लत आदतें छोड़ दें, तो अगला मुख्यमंत्री महादलितों का हो सकता है. फिर किसी दिन वह कहते हैं कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री गया ज़िले का होगा. फिर एक दिन उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें निर्णय लेने में डर लगता है. वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक एवं पूर्व विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि यह बड़ी भयावह स्थिति है. जब एक महादलित मुख्यमंत्री को फ़ैसले लेने में डर लगता है, तो सूबे के आम महादलितों की स्थिति की कल्पना करने में ही डर लगता है. यह कोई साधारण बात नहीं है. सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा महादलित अगर डर रहा है, तो यह मान लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं है. मणि कहते हैं कि दरअसल, दिक्कत यह है कि मांझी को विधायकों ने अपना नेता नहीं चुना. विधायकों ने पहले नीतीश कुमार को अधिकृत किया और फिर नीतीश ने मांझी को नामांकित कर दिया. नीतीश अच्छी तरह जानते थे कि विधायक किसी भी हालत में मांझी के नाम पर तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने यह सुरक्षित रास्ता निकाला. पार्टी के अंदर चुनाव जीतने को लेकर बेहद बेचैनी है.

जदयू के हालात वैसे ही हैं, जैसे 1942 के बाद अंग्रेजी हुकूमत के थे. सभी जान रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत अब जाने वाली है, बस केवल प्रकिया तय होनी है. ठीक उसी तरह जदयू विधायकों में यह बात बैठ गई है कि मांझी सरकार की वापसी मुश्किल है. खुद मांझी को भी इसका एहसास होगा, इसलिए वह रिमोट कंट्रोल की सरकार का धब्बा स्वयं पर नहीं लगने देना चाहते. मांझी कई बार कह चुके हैं कि उनके पास वक्त कम है, पर कम वक्त में ही वह नीतीश के विकास से कहीं बड़ी विकास की लाइन खींचना चाहते हैं. लेकिन, उनके बार-बार बदलते बयानों से उनकी बेचैनी साफ़ झलक जाती है.

मणि कहते हैं कि जदयू के हालात वैसे ही हैं, जैसे 1942 के बाद अंग्रेजी हुकूमत के थे. सभी जान रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत अब जाने वाली है, बस केवल प्रकिया तय होनी है. ठीक उसी तरह जदयू विधायकों में यह बात बैठ गई है कि मांझी सरकार की वापसी मुश्किल है. खुद मांझी को भी इसका एहसास होगा, इसलिए वह रिमोट कंट्रोल की सरकार का धब्बा स्वयं पर नहीं लगने देना चाहते. मांझी कई बार कह चुके हैं कि उनके पास वक्त कम है, पर कम वक्त में ही वह नीतीश के विकास से कहीं बड़ी विकास की लाइन खींचना चाहते हैं. लेकिन, उनके बार–बार बदलते बयानों से उनकी बेचैनी साफ़ झलक जाती है. जदयू के प्रमुख नेता एवं मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि आप लोग डरने वाली बात को ग़लत संदर्भ में देख रहे हैं. दरअसल, उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की हालत पर यह टिप्पणी की थी. जदयू समाज के कमजोर वर्गों को शक्ति देने की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा. महादलित समाज से आने वाले मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर नीतीश ने त्याग और सामाजिक समरसता का बेजोड़ उदाहरण पेश किया है. अफवाह फैलाकर समाज को तोड़ने वाले राजनीतिक दलों को इससे करारा जवाब मिला है.

जानकार सूत्र बताते हैं कि बात इतनी आसान भी नहीं है. मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश ने महादलितों के बीच एक ठोस संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन मांझी के हालिया बयानों एवं फ़ैसलों ने जदयू खेमे को निराश कर दिया. उनका पहला बयान यह था कि नीतीश के शासन में विकास तो हुआ, पर साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ा. गांधी मैदान में भगदड़ की घटना के बाद जिस तरह कुछ डॉक्टरों एवं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी, उससे भी नीतीश खेमा खुश नहीं है. बताया जा रहा है कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय का घोर अभाव है और दोनों के संदेश एक–दूसरे तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं. अभी हाल में नीतीश के घर विधायक दल की बैठक हुई, पर मांझी उसमें नहीं गए. दरअसल, उस बैठक में न जाना मांझी की मजबूरी थी, क्योंकि उसमें विधायकों से मांझी के कामकाज पर फीडबैक भी लिया जा रहा था. ऐसी बैठक में जाकर मांझी अपनी भद्द नहीं पिटवाना चाहते थे. लेकिन, सवाल उठा कि विधायक दल की बैठक में अगर उसका नेता ही न आए, तो फिर सत्ता और सरकार का रास्ता जाता किधर है. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी इसे कुछ अलग नज़रिये से देखते हैं. मोदी कहते हैं कि नीतीश का रिमोट खराब हो गया है, इसलिए वह जो तस्वीर देखना चाहते हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं. महादलित–महादलित का ढोल पीटते हैं और जब एक महादलित मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो उसे काम नहीं करने दे रहे. इससे साफ़ है कि नीतीश ने हमेशा महादलितों को ठगने का काम किया. जदयू के भीतर भारी बेचैनी है, चुनावी हार के डर से विधायक सहमे हुए हैं. उन्हें नीतीश पर भरोसा नहीं रह गया है और इसी डर से मांझी भी ग्रसित हैं. मांझी जानते हैं कि चुनावी हार का ठीकरा नीतीश उनके ही सिर फोड़ेंगे, इसलिए वह कुछ स्वतंत्र निर्णय करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. मांझी को बताना चाहिए कि आख़िर उन्हें कौन डरा रहा है. अगर मुख्यमंत्री डर रहे हैं, तो यह वाकई बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है.

दरअसल, जीतन राम मांझी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए वह चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर याद किया जाए, जिसने कम समय में ही बिहार के विकास में जोरदार योगदान किया. यह इसलिए भी ज़रूरी है कि बार–बार जो सवाल कुर्सी मांझी से पूछ रही है, उसका जवाब इसी रास्ते से निकलेगा. इसलिए यह मानकर चलिए कि अभी हैरतअंगेज बयानबाजी का सिलसिला थमने वाला नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली का वह क्षेत्र है, जहां हिंदुओं एवं मुसलमानों की मिश्रित आबादी है. 1984 में हुए सिख नरसंहार को छोड़ दिया जाए, तो सभी समुदायों के लोग यहां अमन-चैन के साथ वर्षों से रहते चले आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि त्रिलोकपुरी वही जगह है, जहां 1984 के दंगों में सबसे ज़्यादा सिखों को मौत के घाट उतारा गया था. त्रिलोकपुरी के कुछ ब्लॉकों में मुसलमानों की घनी आबादी है, जबकि हिंदू यहां बड़ी संख्या में हैं, जिनमें ज़्यादातर वाल्मिकी समुदाय के लोग हैं. इस हिंसा के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि हिंदू-मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक माता की चौकी के नज़दीक ही बैठकर शराब पी रहे थे.

दिल्ली

चुनाव ही बेहतर विकल्प है

शशि शेखर

लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा की रिक्त हुईं तीन सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. 23 नवंबर को चुनाव होना है और क़रीब एक महीने बाद झारखंड एवं कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणामों के साथ ही इन तीनों सीटों के परिणाम भी आएंगे. दिल्ली की तुगलकाबाद, महरौली एवं कृष्णा नगर सीट पर उपचुनाव होना है. मई में खाली हुई इन सीटों पर छह महीने के भीतर चुनाव कराना ज़रूरी था. इसीलिए इन तीनों सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई. दिल्ली की ये तीनों सीटें भाजपा के पास थीं. इन तीन सीटों के विधायक भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंच चुके हैं. इसलिए कोई विशेष राजनीतिक माथापच्ची करते हुए यह मान भी लें कि ये तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, तो इसमें कुछ विशेष ग़लत नहीं होगा. लेकिन असली सवाल इसके बाद है. क्या ये तीनों सीटें जीत लेने के बाद भी भाजपा दिल्ली में अपने दम पर सरकार बना पाएगी? क्या उसके पास इतनी सीटें (बहुमत के लिए ज़रूरी 36) आ जाएंगी? ग़ैर राजनीतिक रूप से ऐसा होता नहीं दिखता, लेकिन राजनीति के अपने सिद्धांत होते हैं, अपने नियम होते हैं और अपनी सुविधा भी होती है. आम आदमी पार्टी जब 28 सीटों के साथ और कांग्रेस के सहारे दिल्ली में सरकार बना सकती है, तो फिर 32 सीटों के साथ भाजपा (अगर उपचुनाव की तीन सीटें जीत जाती है) सरकार बनाने के बारे में सोच तो सकती ही है.

सवाल यह है कि जिस भाजपा ने 32 सीटें मिलने के बाद भी दिसंबर 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि जनता ने उसे विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, क्या अब वही भाजपा इन सारे तिकड़मों के सहारे सरकार बनाना पसंद करेगी? हाल में हरियाणा एवं महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज करने वाली भाजपा क्या सिर्फ़ सत्ता के लालच में अपने ही बनाए उच्च मानदंडों को तोड़ देगी? हालांकि, यही सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, जिसने कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव लड़कर फिर कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई थी.

लेकिन यह सब लिखना जितना आसान है, धरातल पर इस सबका घट पाना उतना ही मुश्किल है. एक तरफ़ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट बार-बार दिल्ली के उप-राज्यपाल से यह पूछ रहा है कि आख़िर दिल्ली में कब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? भाजपा सरकार कैसे बनाएगी, आदि. बहरहाल, विधानसभा चुनाव पर अभी तक कोई निश्चित फ़ैसला नहीं हो पाया है. वैसे राष्ट्रपति ने अपना सुझाव एलजी को भेज दिया है और उसके मुताबिक यदि एलजी चाहें, तो वह बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता दे सकते हैं. उधर तीन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद यह लगभग साफ़ हो गया है कि फिलहाल दिल्ली में चुनाव कराने की स्थिति बनती नहीं दिख रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आख़िरी फ़ैसला क्या होता है, यह देखना बाकी है.

लेकिन, इस बीच अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं, तो क्या स्थिति होगी? क्या भाजपा सरकार बनाएगी और अगर बनाएगी, तो कैसे बनाएगी? अभी उसके पास 29 सीटें हैं और मौजूदा स्थिति के हिसाब से (तीन सीटें हटा दें, जिनके परिणाम दिसंबर में आएंगे) भाजपा को बहुमत के लिए 67 में से 34 सीटें चाहिए. कांग्रेस के पास 8 और आम आदमी पार्टी के पास 27 सीटें हैं. एक निर्दलीय, एक जद (यू) और आप के एक बागी विधायक का समर्थन भी अगर भाजपा को मिल जाता है, तो उसके पास कुल संख्या होती है 32. यानी अभी भी बहुमत से 2 कम. अब सवाल है कि ऐसे में भाजपा के पास सरकार बनाने के क्या रास्ते बचते हैं? आइए, ऐसे ही कुछ विकल्पों पर ग़ौर करें. पहला, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के विधायक तोड़ लिए जाएं, दूसरा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के विधायक सीक्रेट बैलेट वोटिंग में क्रास वोटिंग कर दें और तीसरा यह कि अल्पमत की सरकार बन जाए, कोई एक दल मतदान का बहिष्कार कर दे. अब होने को इनमें से कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है.

लेकिन सवाल यह है कि जिस भाजपा ने 32 सीटें मिलने के बाद भी दिसंबर 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि जनता ने उसे विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, क्या अब वही भाजपा इन सारे तिकड़मों के सहारे सरकार बनाना पसंद करेगी? हाल में हरियाणा एवं महाराष्ट्र में शानदार जीत दर्ज करने वाली भाजपा क्या सिर्फ़ सत्ता के लालच में अपने ही बनाए उच्च मानदंडों को तोड़ देगी? हालांकि, यही सवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, जिसने कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव लड़कर फिर कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई थी. लेकिन, लोकसभा से लेकर हाल के विधानसभा चुनावों तक शानदार जीत हासिल करती आ रही भाजपा मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कम गंदी वाली राजनीति करेगी, इसकी उम्मीद कम है. वैसे, अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फ़ैसला भी इस मुद्दे पर आना बाकी है. इधर भाजपा के शीर्ष नेताओं, जिनमें वैंकैया नायडू एवं राजनाथ सिंह आदि शामिल हैं, ने भी यह साफ़ कर दिया है कि हम जोड़-तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे. बहरहाल, एक स्वस्थ लोकतंत्र और दिल्ली के लिए अब बेहतर विकल्प सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव है. एक बार चुनाव हो जाए, तो फिर यह भी साबित हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है और अगर भाजपा को बहुमत मिल जाता है, तो उसे कम से कम जोड़-तोड़ करके सरकार बनाने के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा. कुल मिलाकर चुनाव ही हमारे लोकतंत्र, दिल्ली, दिल्ली की जनता एवं भाजपा के लिए आख़िरी और बेहतर विकल्प है. ■

feedback@chauthiduniya.com

त्रिलोकपुरी

क्यों इतनी लाचार हो गई पुलिस

सलमान अली

पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की बहुत-सी घटनाएं हो चुकी हैं. एक छोटी से छोटी क़ानून व्यवस्था की समस्या भी सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है. आख़िर क्यों दो संप्रदाय विशेष के लोगों के बीच एक छोटी-सी कहासुनी भी सांप्रदायिक रंग में रंग जाती है? क्या केवल इसलिए कि दोनों अलग-अलग धर्मों से संबंध रखते हैं? या फिर इसके लिए पुलिस-प्रशासन की खोटी नीयत अथवा उसकी अक्षमता ज़िम्मेदार है? देश की राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दीवाली की रात से चल रहा सांप्रदायिक तनाव आख़िर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? साफ़ तौर पर पुलिस की अकर्मण्यता और अक्षमता इस सबके लिए ज़िम्मेदार मानी जा रही है. दिल्ली पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस के रूप में शुमार किया जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जब देश की राजधानी में ही पुलिस-प्रशासन अपने नाकारेपन का सुबूत दे, तो उससे साफ़ जाहिर होता है कि मेरठ एवं मुजफ्फरनगर जैसी सांप्रदायिक हिंसा में क्या हुआ होगा?

अगर त्रिलोकपुरी की बात करें, तो यहां होने वाली हिंसा नियंत्रित करने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए और थक-हार कर प्रशासन को रैपिड एक्शन फोर्स एवं सीआरपीएफ तैनात करनी पड़ी. हालांकि इस हिंसा में अभी तक किसी के जान से मारे जाने की ख़बर नहीं है, लेकिन दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों समुदायों के पचास से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 23 अक्टूबर को दीवाली की रात क़रीब 8 बजे जब चारों ओर से पटाखे फूटने की आवाज़ें आ रही थीं और लोग दीवाली मनाने में व्यस्त थे, तभी दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र के 20 ब्लॉक में दो समुदायों के बीच अचानक तनाव पैदा हो गया. कुछ ही देर में पथराव शुरू हो जाता है, जो तक़रीबन आधे घंटे तक जारी रहता है और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी मौक़ा-ए-वारदात पर पहुंच कर पथराव कर रहे लोगों को तितर-बितर करते हैं. उस समय तो मामला किसी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन 24 अक्टूबर को यह तनाव एक बार फिर हिंसा में बदल जाता है और दोनों समुदायों के बीच भारी झड़पें शुरू हो जाती हैं, जो देर रात तक जारी रहीं. मामला जब पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गया, तो रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी ने मौके पर पहुंच कर स्थिति संभाली. उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले दागे गए.

त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली का वह क्षेत्र है, जहां हिंदुओं एवं मुसलमानों की मिश्रित आबादी है. 1984 में हुए सिख नरसंहार को छोड़ दिया जाए, तो सभी समुदायों के लोग यहां अमन-चैन के साथ वर्षों से रहते चले आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि त्रिलोकपुरी वही जगह है, जहां 1984 के दंगों में सबसे ज़्यादा सिखों को मौत के घाट उतारा गया था. त्रिलोकपुरी के कुछ ब्लॉकों में मुसलमानों की घनी आबादी है, जबकि हिंदू यहां बड़ी संख्या में हैं, जिनमें ज़्यादातर वाल्मिकी समुदाय के लोग हैं. इस हिंसा के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि हिंदू-मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक माता की चौकी के नज़दीक ही बैठकर शराब पी रहे थे, जिनमें पहले आपस में कुछ कहासुनी हुई और कुछ ही देर में उनके बीच मारपीट होने लगी. उसके बाद पथराव शुरू हो गया. बताते हैं कि क़रीब एक महीने पहले यानी नवरात्र से अस्थायी रूप से ब्लॉक 20 में माता की चौकी लगाई गई थी, जहां कई दिनों से जागरण के साथ-साथ पूजा-अर्चना चल रही थी.

दरअसल, त्रिलोकपुरी के 20 ब्लॉक में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ लोगों ने एक कूड़ाघर को साफ़ करके वहां माता की चौकी स्थापना कर दी और फिर जागरण शुरू हो गया. तबसे वहां प्रतिदिन पूजा-अर्चना हो रही थी. माता की चौकी से कुछ ही क़दम की दूरी पर 20 ब्लॉक की मस्जिद स्थित है. मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने महीने भर से चल रही माता की यह अस्थायी चौकी हटाने की मांग की, तो वहां कुछ लोगों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि अब चौकी नहीं हटाई जाएगी. कुछ ही दिनों पहले दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों के बीच इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ कि मस्जिद में नमाज़ एवं जागरण में पूजा का समय बदला जाए और वह बदला भी गया, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि कुछ ही दूरी पर मस्जिद होने के कारण उन्हें नमाज़ पढ़ने में परेशानी होती है, क्योंकि माता की चौकी में बड़े-बड़े स्पीकर और लाउड स्पीकर लगे हैं, जिससे तेज़ आवाज़ आती है.

बहरहाल, घटना के एक सप्ताह के बाद भी दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स, दोनों मिलकर भी इलाके में पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं कर पाईं. क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी पड़ी. पुलिस ने उपद्रवियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन सिस्टम का सहारा लिया. बावजूद इसके इलाकाई लोगों को कई दिनों तक अपने घर में कैद रहना पड़ा. खाने-पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए. दूध 70-80 रुपये लीटर तक बिका. इलाके के आम नागरिक शांति चाहते रहे, लेकिन चंद स्वार्थी एवं उपद्रवी लोगों की वजह से दिल्ली का यह इलाका एक सप्ताह से भी अधिक समय तक हिंसा-उपद्रव के चंगुल में फंसा रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस चुनाव में कांग्रेस की साख एक बार फिर दांव पर होगी. अभी झारखंड में उसके समर्थन से सरकार चल रही है. नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए बिहार उपचुनाव की तर्ज पर झारखंड में भी महा–गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद एवं जदयू शामिल होंगे. बिहार उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित दल झारखंड में भी इसे अमल में लाना चाहते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है.

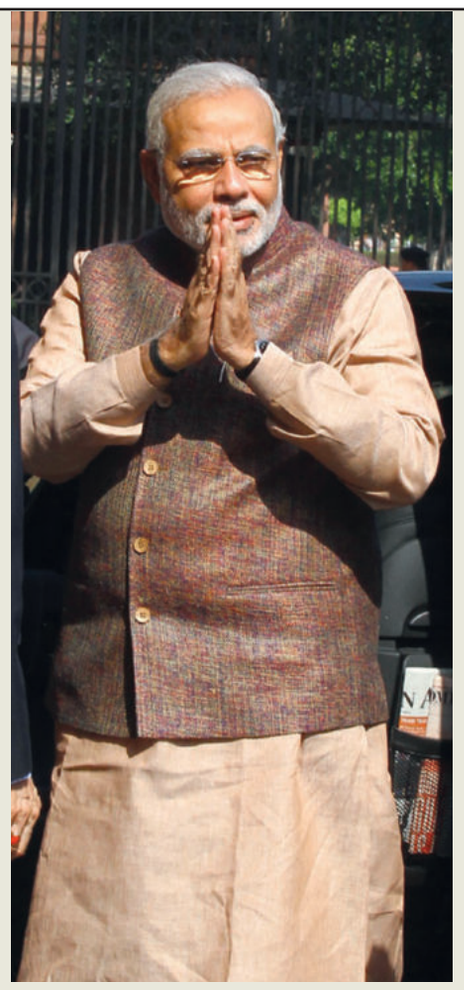

जम्मू–कश्मीर

अगली सरकार पीडीपी-भाजपा की होगी!

सरकार किस पार्टी की बनेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार राज्य विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या में इज़ाफ़ा होने वाला है. फिलहाल विधानसभा में भाजपा के 11 विधायक हैं, लेकिन पिछले एक वर्ष से देश भर में जो मोदी लहर देखने को मिली है, उसका फ़ायदा जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में भाजपा को ज़रूर मिलेगा. अगर ऐसा हुआ, तो इसका साफ़ मतलब होगा कि राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों में भाजपा और पीडीपी का ही भविष्य उज्ज्वल नज़र आ रहा है. पीडीपी ने अपनी चुनावी मुहिम का केंद्र बिंदु नेशनल कांफ्रेंस सरकार की असफलताओं को उछालने तक ही सीमित रखा है.

मोहम्मद हारून रेशी

राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीति दल चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं. पांच चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं. चुनाव आयोग की ओर से घोषणा होते ही राज्य के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों की मिली–जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कहा गया कि ऐसे समय में, जबकि घाटी, ख़ासकर श्रीनगर के बाशिंदें हाल में आई बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं, चुनाव कराना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है. अभी यहां चुनाव की नहीं, पुनर्वास की आवश्यकता है. चुनाव की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में सरकारी स्तर पर राहत कार्य जारी रखना संभव नहीं होगा. चुनाव कराने की घोषणा पर न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई. सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने भी ऐसे मौक़े पर चुनाव कराने का विरोध किया है. नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉ. मुस्तुफ़ा कमाल, जो मुख्यमंत्री के चाचा भी हैं, ने कहा कि इस समय तो कश्मीरी जनता, जो बाढ़ से तबाह हो गई है और जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, के लिए राहत कार्यों का समय है, न कि वोट मांगने का. चुनाव कराने के लिए इतनी जल्दबाज़ी से काम क्यों लिया गया?

बहरहाल, चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक पार्टियां, ख़ासकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा उत्साहित नज़र आ रही हैं. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस के रुचि न लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके नेतृत्व वाली राज्य सरकार बाढ़ के दौरान और उसके बाद पुनर्वास को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. पत्रकार रियाज़ मलिक कहते हैं कि बाढ़ आए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन सरकार अभी उससे होने वाले नुक़सान का भी अनुमान नहीं लगा सकी. सरकारी अमला अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर रहा है कि किसका कितना नुक़सान हुआ. सरकार की इस कछुआ चाल के कारण लोग बेहद आक्रोशित हैं. परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार प्रभावित लोगों के लिए छत की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकी. ऐसे में नेशनल कांफ्रेंस कौन–सा मुंह लेकर मतदाताओं के बीच जाएगी? उसे सारी स्थिति मालूम है, इसीलिए उसने चुनाव कराने के निर्णय का विरोध किया है. दिलचस्प बात यह है कि राज्य की गठबंधन सरकार में नेशनल कांफ्रेंस की सहयोगी पार्टी कांग्रेस में भी उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है. रियाज़ कहते हैं कि राज्य कांग्रेस पर भी लोकसभा चुनाव जैसी हार का ख़तरा मंडराने लगा है. सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित विपक्षी दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा हैं. इन दोनों ने अपनी चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी हैं. भाजपा के राज्य प्रवक्ता ख़ालिद जहांगीर इन दिनों बहुत उत्साहित हैं. उनका कहना है कि भाजपा ने जम्मू–कश्मीर में मिशन–44 का ख्वाब देखा है, जिसके पूरा होने की प्रबल संभावना है.

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने जम्मू– कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए यहां 87 सदस्यों वाली विधानसभा में कम से कम 55 ज़रूरी सीटें जीतने का लक्ष्य बहुत पहले ही तय कर लिया था. बीते आम चुनाव के दौरान भाजपा ने जम्मू एवं लद्दाख़ में वोट प्रतिशत में भारी बढ़त हासिल की थी. इस बार भाजपा की नज़र घाटी के उन चुनाव क्षेत्रों पर भी है, जहां पलायन करके आए कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि अलगाववादी दलों ने पहले ही चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है, इसलिए संभव है कि साधारण मतदाता मतदान न करें और इस प्रकार भाजपा कश्मीरी पंडितों के बल पर इन सीटों पर जीत जाए. ख़ालिद जहांगीर बताते हैं कि हम मिशन–44 की सफलता के लिए भरपूर मेहनत करेंगे. संभव है कि नरेंद्र मोदी स्वयं घाटी आकर चुनावी सभाओं को संबोधित करें. ख़ालिद को विश्वास है कि जम्मू–कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की बनेगी.

सरकार किस पार्टी की बनेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार राज्य विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या में इज़ाफ़ा होने वाला है. फिलहाल विधानसभा में भाजपा के 11 विधायक हैं, लेकिन पिछले एक वर्ष से देश भर में जो मोदी लहर देखने को मिली है, उसका फ़ायदा जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में भाजपा को ज़रूर मिलेगा. अगर ऐसा हुआ, तो इसका साफ़ मतलब होगा कि राज्य में महत्व–पूर्ण राजनीतिक पार्टियों में भाजपा और पीडीपी का ही भविष्य उज्ज्वल नज़र आ रहा है. पीडीपी ने अपनी चुनावी मुहिम का केंद्र बिंदु नेशनल कांफ्रेंस सरकार की असफलताओं को उछालने तक ही सीमित रखा है. लगता है कि पीडीपी नेशनल कांफ्रेंस की उन ख़ामियों को उछालने का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहती, जिनकी वजह से जनता नाराज़ है. पीडीपी यूथ विंग के नेता मोहम्मद ताहिर सईद ने बताया कि उनका सारा फोकस इस बात पर है कि वह जनता को नेशनल कांफ्रेंस के वे जनविरोधी कार्य याद दिलाते रहें, जिनके कारण उसे मुसीबतें झेलनी पड़ीं. उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस की सरकार में कम से कम पांच हज़ार कश्मीरी नौजवानों के ख़िलाफ़ पथराव के आरोप में केस दर्ज किए गए. हज़ारों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई. 2010 में सड़कों और गली–कूचों में 110 लोगों, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे, को मौत के घाट उतार दिया गया. नेशनल कांफ्रेंस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, लेकिन वे सारे मामले दबा दिए गए. किसी एक मामले में भी दोषियों को दंडित करने की कोशिश नहीं की गई.

ज़ाहिर है, विधानसभा चुनाव के दौरान पीडीपी के लिए नेशनल कांफ्रेंस की ख़ामियां उछालना ही काफ़ी है. ऐसे में नेशनल कांफ्रेंस को क़दम–क़दम पर सफ़ाई देनी होगी, अपना बचाव करना होगा. नतीजतन, पीडीपी का पलड़ा भारी रहेगा. विधानसभा चुनाव के हवाले से जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, उनके अनुसार जम्मू एवं लद्दाख़ में सीटों की एक बड़ी संख्या भाजपा के खाते में और घाटी में पीडीपी के खाते में जाती नज़र आ रही हैं. अगर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के हक़ में कोई करिश्मा न हुआ, तो यह लगभग तय समझा जाना चाहिए कि राज्य में अगली सरकार भाजपा और पीडीपी के गठबंधन वाली होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

स्थायी सरकार सबसे बड़ा मुद्दा

महाराष्ट्र एवं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद शुरू हुई राजनीतिक गहमागहमी थमी भी नहीं थी कि 25 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने झारखंड एवं जम्मू–कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी. इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हमें दोनों राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का शासनादेश मिला था. झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 03 जनवरी, 2015 को समाप्त हो रहा है. झारखंड में पांच चरणों में 25 नवंबर, 02 दिसंबर, 09 दिसंबर, 14 दिसंबर एवं 20 दिसंबर को मतदान होगा और 23 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी.

जिस तरह दीपावली से पहले महाराष्ट्र एवं हरियाणा के चुनाव परिणाम आए थे, ठीक उसी तरह क्रिसमस एवं नए साल के ठीक पहले झारखंड के लोगों और जीत दर्ज करने वाली पार्टी को दोहरी खुशी मनाने का मौक़ा मिलेगा. क़ानून व्यवस्था के लिहाज से झारखंड बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए चुनावों में सुरक्षा के प्रभावी उपाय किए गए हैं. झारखंड के 2.07 करोड़ मतदाता 81 विधानसभा सीटों पर नई सरकार के भाग्य का फ़ैसला करेंगे. चुनाव के लिए राज्य में 24,648 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. झारखंड चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा स्थायी सरकार है. 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होकर पृथक राज्य बनने के बाद झारखंड में तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इस दौरान राज्य 9 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन देख चुका है. झारखंड के साथ गठित हुए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्य इससे कहीं आगे निकल गए हैं. यहां प्राकृतिक संपदाओं का बहुत बड़ा भंडार होने के साथ ही राजधानी रांची एवं जमशेदपुर औद्योगिक रूप से विकसित शहर हैं. पिछले 14 सालों से यह राज्य भ्रष्टाचार का लगातार शिकार होता रहा है. इस वजह से विकास यहां रफ़्तार नहीं पकड़ सका. साथ ही नक्सल समस्या लगातार विकराल रूप लेती चली गई. इस वजह से राज्य में निवेश में भी कमी आई और विकास का चक्का थम–सा गया.

मोदी रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित नज़र आ रही है. उसने सभी 81 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फ़ैसला किया है. इसके लिए पार्टी पंचायत स्तर पर बूथ सम्मेलन करा रही है. भाजपा ने राज्य में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहली गठबंधन सरकार बनाई थी. इसके अलावा भाजपा अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भी तीन बार सरकार बना चुकी है. ख़बर यह भी है कि भाजपा राज्य में दो गुटों में बंटी हुई है. एक गुट ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के साथ गठबंधन का पक्षधर है, तो दूसरा गुट अकेले चुनाव लड़ना चाहता है. भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा भी गठबंधन के ख़िलाफ़ हैं. सिन्हा ने हाल में कहा था कि जब जनता हमारे साथ है, तो फिर हम कोई गठबंधन क्यों करें? मोदी फैक्टर पर्याप्त है. फिलहाल भाजपा राज्य में 81 में से 55 सीटों पर जीत हासिल करने के मिशन के तहत काम कर रही है. हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां की 14 में से 12 सीटें हासिल की थीं. इस चुनाव में वह 58 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी. वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 18 विधानसभा सीटें हैं. बीते 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आए थे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों से बहुमत वाली सरकार देने की अपील की थी, ताकि झारखंड को विकसित राज्य में बदला जा सके.

2009 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति

झारखंड मुक्ति मोर्चा	–18
भारतीय जनता पार्टी	–18
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–13
झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)	–11
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन	–06
राष्ट्रीय जनता दल	–05
जनता दल (यूनाइटेड)	–02
स्वतंत्र	–02
अन्य	–06

इस चुनाव में कांग्रेस की साख एक बार फिर दांव पर होगी. अभी झारखंड में उसके समर्थन से सरकार चल रही है. नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए बिहार उपचुनाव की तर्ज पर झारखंड में भी महा–गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद एवं जदयू शामिल होंगे. बिहार उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित दल झारखंड में भी इसे अमल में लाना चाहते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है. हेमंत सोरेन का कहना है कि भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना ज़रूरी है. उन्होंने अपनी पार्टी की सूची कांग्रेस को सौंपी है और यह भी बताया है कि कहां कांग्रेस मजबूत है और कहां झामुमो. अब कांग्रेस बताए कि उसे क्या करना है. दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही है. कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने से इंकार कर रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश में 50 सीटों पर बेहतर स्थिति में है. प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उत्साहित हैं. ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस आलाकमान झामुमो के साथ चुनाव लड़ने का फ़ैसला करता है, तो प्रदेश कांग्रेस में विद्रोह हो सकता है. यूं भी कांग्रेस पार्टी उस डूबते हुए जहाज की तरह हो गई है, जिसे छोड़कर पंछी भागते हैं. भले ही कांग्रेस सत्तारूढ़ झामुमो के साथ सरकार में है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं. इससे गठबंधन कमजोर होता दिख रहा है. ऐसे में कांग्रेस और झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने के आसार बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं. सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने 36–36 सीटों का फॉर्मूला दिया और नौ सीटें राष्ट्रीय जनता दल को देने की बात कही गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर असहमति जताई है. झामुमो 42 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी भाजपा के ख़िलाफ़ बनने वाले महा–गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं. इस संबंध में मरांडी ने कहा कि वह झारखंड में जनता के हित में महा–गठबंधन बनाए जाने के पक्ष में हैं और निश्चित रूप से इससे धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा रोकने में सहायता मिलेगी. हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गठबंधन बनाने से पहले यह तय होना आवश्यक है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा?

राज्य में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार, आदिवासियों का विकास, रोज़गार एवं सड़क आदि इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे होंगे. झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं. प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुशासन, रोज़गार, क़ानून व्यवस्था एवं लोगों का सशक्तिकरण आदि मुद्दे मायने रखेंगे. उनका दावा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 14 महीनों में जो कर दिखाया, वह काम पहले की सरकारें 14 सालों में नहीं कर सकीं. यही मुद्दे इस चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करेंगे. खैर, विभिन्न पार्टियां कुछ भी दावा कर रही हों, लेकिन झारखंड में स्थायी सरकार ही सबसे बड़ा मुद्दा होगी. इसके अलावा विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय भी ज़रूरी है. ऐसे में झारखंड में पलड़ा हाल में संपन्न हुए चुनावों की तर्ज पर भाजपा के पक्ष में झुका नज़र आ रहा है, बाकी दल अपने अस्तित्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

> भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है. अतः हर राज्य एवं जिले और इसके विधानसभा की समस्या अलग–अलग होती है. इस जिले मे भी छह विधानसभा क्षेत्र हैं तो लाजिमी है कि यहां की समस्याएं भी अलग होंगी. अब आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सा प्रत्याशी किस मुद्दे को अपना चुनावी शस्त्र बनाकर इस चुनावी रण में आगे आता है.

फर्जी प्रमाणपत्र पर सांसद बने राम चरित्र

प्रभात रंजन दीन

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठ कर दलितों और उपेक्षितों को आगे लाने, उनका हौसला बढ़ाने और उन्हें समान धरातल पर खड़ा करने पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, लेकिन अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगा कर सांसद बन गए नेता पर सख्त कार्रवाई की अनिवार्यता संघ की विचार प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं थी. दलितों का हक मार कर सांसद बनने की नायाब घटना के बारे में संघ और भाजपा के शीर्ष नेताओं को पहले से ही पक्की जानकारी है. आम कार्यकर्ताओं को भी पता है. लेकिन नेताओं में चुप्पी सधी हुई है और कार्यकर्ताओं में नेतृत्व की कथनी और करनी के भारी फर्क पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं.

लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे के समय ही भाजपा आलाकमान को यह खबर मिल गई थी कि जौनपुर के मछलीशहर सुरक्षित सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनना चाह रहे रामचरित्र निषाद ने खुद को अनुसूचित जाति का व्यक्ति साबित करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है. लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, डॉ. हर्षवर्धन और अमित शाह सब कुछ जानते हुए भी रामचरित्र के चरित्र पर मेहरबान थे. भाजपा का प्रदेश नेतृत्व यह समझता था कि दलित होने का फर्जी दावा नामांकन पत्र के दाखिले के समय ही खारिज हो जाएगा, इसलिए एहतियात बरतते हुए दूसरे अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन भी बाक़ायदा पार्टी के सिम्बल के साथ दाखिल करा दिया गया था. लेकिन रामचरित्र ने सब कुछ मैनेज कर लिया.

इस नायाब कहानी के विस्तार में चलने से पहले रामचरित्र के अति–पिछड़े से दलित बनने का खेल समझते चलें. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कटरा बुजुर्ग गांव के रहने वाले रामचरित्र ने दिसंबर 2007 में दिल्ली से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया. रामचरित्र जन्म के आधार पर निषाद जाति के हैं, जो उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति में शुमार है. दिलचस्प यह है कि यही रामचरित्र संत कबीर नगर के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से 2007 का विधानसभा का चुनाव जनरल सीट से लड़ चुके हैं. वर्ष 2007 के अप्रैल महीने में कांग्रेस के टिकट पर राम चरित्र मेहदावल विधानसभा की जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं और उसी साल दिसम्बर महीने में दिल्ली के दलित बन जाते हैं. संत कबीर नगर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी का आधिकारिक वक्तव्य है कि मेहदवाल सीट से 2007 में लड़ने वाले राष्ट्रीय दलों के सभी प्रत्याशी सामान्य (जनरल) वर्ग के थे. राष्ट्रीय दलों का कोई प्रत्याशी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था.

सामर्थ्य वाला व्यक्ति इस देश में कानून को किस तरह मैनेज करता है, इसका यह नायाब उदाहरण है. लोकसभा चुनाव में मछलीशहर (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिला लेने वाले रिटर्निंग अफसर (उप चुनाव अधिकारी) राधेश्याम की हास्यास्पद रिपोर्ट का जायजा लेते चलें. रिटर्निंग अफसर साफ–साफ लिखते हैं कि बस्ती जिले के गणेशपुर तहसील के कटरा बुजुर्ग गांव निवासी रामचरित्र मल्लाह जाति के अंतर्गत आते हैं, जो उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग में आती है. लेकिन रामचरित्र ने दिल्ली के सीलमपुर तहसील से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है. उसके सत्यापन रिपोर्ट में भी यह माना गया है कि इस बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. रिटर्निंग अफसर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए खुद ही यह कहते हैं कि जाति के निर्धारण की तरह आरक्षण का निर्धारण भी जन्म के आधार पर होता है. यह सब कुछ मानने के बावजूद अपनी अक्षमता जताते हुए रिटर्निंग अफसर ने रामचरित्र का नामांकन मंजूर कर लिया और फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग के रामचरित्र दलित सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुन लिए गए.

> भारत सरकार की सूची के अनुसार मल्लाह जाति पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है. दिल्ली सरकार का अध्यादेश भी है कि निषाद जाति का कोई भी व्यक्ति या उसके माता-पिता अगर 1950 के पहले से दिल्ली के निवासी हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल माना जा सकता है. रामचरित्र के पिता राम नारायण बस्ती के कटरा बुजुर्ग गांव के मूल निवासी थे. रामचरित्र भी वहीं के मूल निवासी हैं. वर्ष 2000 के दिसंबर महीने में उन्होंने दिल्ली से अनुसूचित जाति का प्रमाण कैसे प्राप्त कर लिया, यह जांच का विषय है.

दलितों का हक मार कर भाजपा ने अपने उस प्रत्याशी को सांसद बनवा लिया जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अति पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति का बन गया था. उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि मल्लाह व निषाद जाति का व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा की अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है. भारत सरकार की सूची के अनुसार मल्लाह जाति पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है. दिल्ली सरकार का अध्यादेश भी है कि निषाद जाति का कोई भी व्यक्ति या उसके माता–पिता अगर 1950 के पहले से दिल्ली के निवासी हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल माना जा सकता है. रामचरित्र के पिता राम नारायण बस्ती के कटरा बुजुर्ग गांव के मूल निवासी थे. रामचरित्र भी वहीं के मूल निवासी हैं. वर्ष 2000 के दिसंबर महीने में उन्होंने दिल्ली से अनुसूचित जाति का प्रमाण कैसे प्राप्त कर लिया. यह जांच का विषय है. रामचरित्र यदि दिल्ली के निवासी थे तो उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के आठ साल बाद 26 अगस्त 2013 को वोटर लिस्ट और परिवार रजिस्टर से नाम हटाने का आवेदन क्यों दिया? 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पहले से की जा रही तमाम पेशबंदियों के तहत यह किया गया. रामचरित्र के प्रमाणपत्र पर विवाद होने के बाद दिल्ली के सीलमपुर के तहसीलदार मदनलाल ने 29 मार्च 2014 को बचकाने और हास्यास्पद तर्क देकर ऐसे महत्वपूर्ण मामले को लंबित रख दिया. जबकि इन्हीं मदनलाल ने महज आठ दिन पहले रामचरित्र के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह सख्त ताकीद की थी कि अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी फायदे के लिए नहीं किया जाए. आठ दिन बाद ही मदनलाल की सख्ती विलंबित–ताल में चली गई. इस तरह रामचरित्र का दिल्ली का अधिवास प्रमाण पत्र फिलहाल स्थगन की अवस्था में है, लेकिन इसी के आधार पर कोई व्यक्ति संविधान को ठेंगे पर रख कर सांसदी इन्जॉय तो कर रहा है! ■

ऐसे ही फर्जीवाड़े में गईं थीं अनीता सिद्धार्थ

फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के मामले में अनीता सिद्धार्थ की जौनपुर जिला पंचायत सदस्यता तो रद्द हुई ही, फर्जीवाड़े में उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ रही है. उच्च न्यायालय के आदेश पर शासन स्तर से हुई जांच में फर्जीवाड़ा कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने की शिकायत सही पाई गई.

जिला पंचायत के वार्ड संख्या 23 से अनीता सिद्धार्थ जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थीं. बाद में वे जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्वाचित हुईं. दोनों पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे. जांच में पाया गया कि बसारतपुर की रहने वाली अनीता सिद्धार्थ के पक्ष में सुल्तानपुर जिले के कादीपुर के तहसीलदार द्वारा नियम और कानून को ताक पर रख कर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दे दिया गया था. वह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. अनीता की मूल जाति बारी, पिछड़ी जाति में शामिल है. शासन ने झूठी घोषणा के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का अनीता सिद्धार्थ को दोषी पाया और इस पर अदालत से उन्हें सजा सुनाई. ■

feedback@chauthiduniya.com

औरंगाबाद

दावेदारों की भरमार

अमित मिश्र

बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे–जैसे करीब आ रहा है त्यों–त्यों औरंगाबाद जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं. जिले की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी एजेंडा तय कर लिया है जिसके बलबूते वो इस चुनामी समर को पार करने की कोशिश करेंगी. साथ ही उनका जनसंपर्क अभियान भी तेज होता हुआ दिख रहा है. इसी तैयारी के क्रम में कोई डोर टू डोर अर्जी लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा है तो कोई कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर अपनी जोर आजमाइश कर रहा है. इससे इतर जदयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर जगह–जगह महाधरना प्रदर्शन कर रही है इस वजह से उसकी केन्द्र को दोषी ठहराने की कवायद जोर पकड़ रही है.

गौरतलब है कि इस जिले के अंदर छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें वर्तमान में चार पर जदयू, एक पर भाजपा, एक निर्दलीय और एक पर राजद का झंडा लहरा रहा है. चूंकि लोकसभा चुनाव के वक्त जिले के राजनीतिक हालात काफी बदला सा लग रहा था. साथ ही भाजपा के भीतर कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है और हुआ भी यही. लोकसभा में कमल के फूल खिलते ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए और भाजपा को जीत मिलने से युवाओं के बीच नमो–नमो का जाप होने लगा. भाजपा के वर्तमान सांसद सुशील सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से एकजुटता दिखाने की बात बार–बार कही जा रही है. लगभग सभी पार्टी के प्रमुख नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं. केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार द्वारा मतदाताओं की समस्याओं को सुना जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता तत्काल करने के लिए पार्टी के अन्य नेताओं को कहा जा रहा है ताकि मतदाताओं की समस्या का समाधान तुरंत हो सके.

चुनाव से पहले विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता मोदी लहर को नकार रहे थे. लेकिन हरियाणा एवं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को देखते हुए अब कोई भी पार्टी कुछ भी स्पष्ट रूप से बोलने से कतरा रही है. यहां तक की जो दावेदारी एलायंस पार्टी के नेताओं द्वारा पहले की जा रही थी वे अब कुछ भी सरेआम बोलने से परहेज कर रही हैं. 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी–अपनी दावेदारी को प्रबल मान रही हैं. लोजपा–भाजपा–रालोसपा गठबंधन के उम्मीदवार काफी कश्मकश में हैं कि इस तिगड़ी में सीटों का औसत बंटवारा क्या होगा? मगर इन सभी में जिलों का सिरमौर कही जाने वाली औरंगाबाद विधानसभा सीट भाजपा को मिलना तय माना जा रहा है क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी रामाधार सिंह लगातार तीन बार विपक्षी पार्टियों को शिकस्त देने में सफल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ रफीगंज सीट से जदयू हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है. वहीं एक ओर इसी बैचेनी के साथ जदयू–राजद का महागठबंधन भी दिन गिन रहा है. साथ ही पार्टी गठबंधन नेताओं बीच भी यह प्रश्न, यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है कि उनके आलाकमान द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है इसलिए पार्टी में भीतर तक अपनी खास पकड़ रखने वाले रसूखदार नेता भी सीट बंटवारे को लेकर मुंह खोलने से कतरा रहे हैं. परंतु आंख मिचौली के इस खेल में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ सीटें पूर्व निर्धारित भी मानी जा रही हैं. हांलाकि, वोटरों के द्वारा वर्तमान सरकार के पूर्व कार्यों की सराहना भी की जा रही है साथ ही उनके कुछ कार्यों से मतदाताओं मे रोष भी व्याप्त है. इस कारण किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार प्रत्यक्ष बोलने से कतरा रहा है. लोकसभा में मोदी लहर को विधानसभा में नकारने वाले विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता अब हरियाणा और महाराष्ट्र के हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद चुप्पी साधने को मजबूर हैं क्योंकि राजनीतिक शतरंज की अगली चाल क्या होगी यह कहना किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के लिए उचित नहीं है. चूंकि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है. अत: हर राज्य एवं जिले और इसके विधानसभा की समस्या अलग–अलग होती है. इस जिले मे भी छह विधानसभा क्षेत्र हैं तो लाजिमी है कि यहां की समस्याएं भी अलग होंगी. अब आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सा प्रत्याशी किस मुद्दे को अपना चुनावी शस्त्र बनाकर इस चुनावी रण में आगे आता है. ■

> इन सभी में जिलों का सिरमौर कही जाने वाली औरंगाबाद विधानसभा सीट भाजपा को मिलना तय माना जा रहा है क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी रामाधार सिंह लगातार तीन बार विपक्षी पार्टियों को शिकस्त देने में सफल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ रफीगंज सीट से जदयू हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है. वहीं एक ओर इसी बैचेनी के साथ जदयू-राजद का महागठबंधन भी दिन गिन रहा है

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

सपा की बेचैनी बढ़ा रहा एमआईएम

लखनऊ में दफ्तर खोलने के साथ ही आजमगढ़ जाने और जनसभा को संबोधित करने के ओवैसी के ऐलान से सपा के शीर्ष गलियारे में बेचैनी है. एलआईयू की रिपोर्ट है कि ओवैसी की घोषणा पर आजमगढ़ में खासी चर्चा है और उनकी जनसभा सफल बनाने के लिए मुसलमानों का कट्टरपंथी तबका अभी से सक्रिय हो गया है. ओवैसी की जनसभा को न्यूट्रल करने के लिए भाजपा ने भी महंत आदित्य नाथ को जनसभाओं में वहां उतारने का मन बनाया है. सपा को एलआईयू की रिपोर्ट के जरिये एक आधार भी मिल रहा है कि ओवैसी को आजमगढ़ आने से फिर रोक दिया जाए.

दीनबंधु कबीर

हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत से सतर्क समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में बनाए रखने के साथ-साथ और अधिक मुस्लिम समर्थन जुटाने में लग गई है. मुलायम सिंह यादव के फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की तैयारियां चल ही रही थीं, तभी बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आ गया. हरियाणा में सपा ने भाजपा के ख़िलाफ़ इनेलो की खूब मदद भी की, लेकिन महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) की मौजूदगी ने सपा को बेचैन रखा. एमआईएम ने महाराष्ट्र में दो सीटें भी जीत लीं. तीन सीटों पर वह बहुत कम अंतर से हारी और नौ सीटों पर तीसरे स्थान पर रही. यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने नोटिस लिए जाने लायक अपनी शिनाख्त दर्ज करा ली. महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम की सीटवार समीक्षा करने पर आप साफ़-साफ़ देखेंगे कि एमआईएम ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एवं एनसीपी के वोट काटे. इसके बाद जब एमआईएम ने अपना अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश को बनाने का ऐलान किया, तो सपा की बेचैनी बढ़ गई. साफ़ है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट काटने ही आ रही है. एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस बारे में आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया है. साथ-साथ एमआईएम ने बिहार एवं पश्चिम बंगाल की तरफ़ भी क़दम बढ़ाने की घोषणा की है.

2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम अपनी रणनीति बना रही है. ओवैसी ने इस बार भी मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को प्रमुख रूप से अपना लक्ष्य बनाया है. इसके पहले भी ओवैसी ने कई बार आजमगढ़ जाने की कोशिश की है, लेकिन क़ानून व्यवस्था के सवाल पर ओवैसी को वहां जाने से राज्य सरकार ने कई बार रोका है. अब तो नवंबर में लखनऊ में एमआईएम का बाकायदा दफ्तर खोलने की घोषणा भी कर दी गई है. जब लखनऊ में एमआईएम का दफ्तर खुलेगा, तो पार्टी प्रमुख भी उद्घाटन के मौक़े पर मौजूद रहेंगे. ओवैसी ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम अपना आधार और प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के अनुभव के आधार पर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति बदल दी और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं. ओवैसी ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में कुछ पहले से एमआईएम को सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत होने के लिए अभी पर्याप्त समय है.

लखनऊ में दफ्तर खोलने के साथ ही आजमगढ़ जाने और जनसभा को संबोधित करने के ओवैसी के ऐलान से सपा के शीर्ष गलियारे में बेचैनी है. एलआईयू की रिपोर्ट है कि ओवैसी की घोषणा पर आजमगढ़ में खासी चर्चा है और उनकी जनसभा सफल बनाने के लिए मुसलमानों का कट्टरपंथी तबका अभी से सक्रिय हो गया है. ओवैसी की जनसभा को न्यूट्रल करने के लिए भाजपा ने भी महंत आदित्य नाथ को जनसभाओं में वहां उतारने का मन बनाया है. सपा को एलआईयू की रिपोर्ट के जरिये एक आधार भी मिल रहा है कि ओवैसी को आजमगढ़ आने से फिर रोक दिया जाए. इसके पहले भी शांति व्यवस्था में व्यवधान की आशंका बताकर ओवैसी को आजमगढ़ जाने से रोका गया है, लेकिन वह इस बार वहां जाने के लिए अडिग हैं. कहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, इस बार तो आजमगढ़ ज़रूर जाऊंगा. संसद में मुस्लिम सांसदों की आमद का ग्राफ लगातार गिरते जाने को एमआईएम ने मुद्दा बनाया है. यह मुद्दा कट्टरपंथी मुस्लिमों के कंधे से होकर मुस्लिम समुदाय में प्रभाव कायम कर रहा है. यह मुद्दा मजबूत बनाने के लिए एमआईएम ने सभी तथाकथित सेकुलर पार्टियों को निशाने पर लेना शुरू किया है और समुचित अनुपात में मुस्लिम प्रत्याशियों को मौक़ा न देने का सार्वजनिक आरोप लगाने का अभियान तेज कर दिया है. एमआईएम मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह समझा रही है कि संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व न होने की वजह से मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक मसले तो उपेक्षित हुए ही, सियासी तौर पर भी मुसलमानों के हाशिए पर चले जाने की आशंका बढ़ गई है. एमआईएम चाहती है कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट अन्य पार्टियों में न बंटें, बल्कि उसे ही समेकित रूप से मिल जाएं. मुस्लिम लीग बनने की कोशिश कर रही एमआईएम के प्रमुख ने अपनी कई सभाओं में कहा है कि भारत में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, जो केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे, उनके मसलों के साथ घालमेल न करे. अन्य पार्टियों में वोट बंटने के कारण ही मुसलमानों का संसद में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं है.

अभी हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद न चुने जाने का मसला सपा के लिए पहले से सियासत का मसला बना हुआ था, लेकिन अब एमआईएम ने भी इस मसले को पूरी ताकत से उठाना शुरू कर दिया है. मुसलमानों से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 19 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद का न होना समुदाय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. एमआईएम मानती है कि मुस्लिम वोटों के इधर-उधर बंटने के कारण ही सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल एवं मेरठ जैसे इलाकों में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई. राजनीतिक प्रेक्षकों का भी मानना है कि एमआईएम मुसलमानों के स्वाभाविक पक्षधर के रूप में अपना स्थान बना सकती है. इससे खास तौर पर सपा-कांग्रेस और आम तौर पर बसपा एवं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को मुस्लिम वोटों का नुक़सान हो सकता है. मुस्लिम पक्षधरता की राजनीति के इस सार्वजनिक ऐलान से मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत को झटका लगा है और अब सपा समेत तमाम राजनीतिक दल नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

सपा की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी, दोनों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अच्छी-खासी तादाद में बढ़ाया जा रहा है. सपा का थिंक टैंक मुसलमानों के बीच सपा को भाजपा के एकमात्र ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करने का पक्षधर है. सपा इस कैंपेन में लगी है कि मुसलमानों को आश्वस्त किया जा सके कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है. नई कार्यकारिणी में शामिल होने वाले मुस्लिम प्रतिनिधि भी सपा के इस अभियान में तेजी से लगने वाले हैं. बसपा प्रमुख मायावती का अभी जो बयान आया है, उससे भी सपा की इन कोशिशों को बल मिला है. मायावती ने कहा कि देश भर में भाजपा की लहर नहीं, बल्कि कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है. साफ़ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का रुझान बहुत जल्द लौटने वाला नहीं है और उसका फ़ायदा बसपा को भी मिलता नहीं दिख रहा. सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता अहमद हसन कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा से टक्कर लेने वाली पार्टी केवल सपा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

जाजू को शाह के खास टिप्स

सूत्रों ने बताया कि प्रदेश भाजपा द्वारा संगठन मजबूत करने के मकसद से जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, उन पर वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही उन्हें हरी झंडी दी जाएगी. अमित शाह ने जाजू से कहा है कि भविष्य में पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पैनी नज़र रखी जाए. शाह ने कहा कि हर कार्यक्रम की समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि आगामी कार्यक्रमों में आवश्यकता के मुताबिक नए एजेंडे शामिल किए जा सकें.

राजकुमार शर्मा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश के नए प्रभारी श्याम जाजू को पार्टी को सशक्त बनाने के खास टिप्स दिए हैं. जाजू जल्द ही आम कार्यकर्ताओं को खास एहसास दिलाते हुए उत्तराखंड का दौरा करेंगे. उपचुनाव में राज्य की जनता ने मोदी मैजिक को नकारते हुए जिस तरह कांग्रेस को एकमुश्त तीन सीटें जिताकर हरीश सरकार को निर्भयता प्रदान की, उसने राजनीति के माहिर खिलाड़ी अमित शाह को सोचने के लिए मजबूर कर दिया. उत्तराखंड की जनता का मिजाज समझते हुए मोदी को शाह से देवभूमि के संदर्भ में मंत्रणा करनी पड़ी, जिसमें गुटबाजी करके पार्टी को बर्बादी की राह पर धकेलने, मठाधीशी करने वाले नेताओं को किनारे लगाते हुए आम कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर मिशन 2017 की रणनीति बनाने का फ़ैसला लिया गया.

नए प्रभारी से पूरे राज्य में जनता की भावना के अनुरूप नए सिरे से संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिए कहा गया है. लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ कर राज्य की पांचों सीटें भाजपा के हवाले करने वाली जनता ने जिस तरह गुटों में बंटे नेताओं को उनका असली चेहरा दिखाया, उससे भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार हैरान हैं. उत्तराखंड में अधिकांश नेता गणेश परिक्रमा करके बड़े नेता बन गए थे. किसी को राजनाथ का वरदहस्त प्राप्त था, तो किसी को सुषमा-गडकरी का. निशंक जैसे नेता ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहारे अपनी गोटी लाल की. इन नेताओं में पार्टी-जनता के प्रति वफादारी कम, अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादारी ज़्यादा थी. कई मठाधीश नेता अपने मुख्य नेता जनरल खंडूडी को हराकर भी अपनी बादशाहत कायम रखने का खेल खेलते रहे, जिसका परिणाम रहा कि राज्य गठन के चौदह वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक भी काम ऐसा नहीं कर सकी, जिस पर जनता उसकी पीठ थपथपा सके.

सूबे के भाजपाई दिग्गजों के कलह की हांडी इस कदर चौराहे पर फूटी कि जनता ने चाहते हुए भी भाजपा को अपनी पहली पसंद नहीं बनाया. नए मुखिया शाह चाहते हैं कि मजबूत नींव रखकर नए सिरे से पार्टी का संगठन खड़ा किया जाए. उनकी यह मंशा भांपते हुए प्रदेश भाजपा की इच्छा है कि श्याम जाजू अल्मोड़ा में आयोजित होने वाले सांसदों-विधायकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों. प्रदेश प्रभारी की ओर से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है. उम्मीद लगाई जा रही है कि जाजू जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे. जाजू कोई भी क़दम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहते और न किसी स्थानीय नेता की सलाह पर चलना चाहते हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जाजू को सलाह दी है कि वह सबसे पहले प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करें और पूरी कमान अपने हाथ में लें, ताकि ज़मीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके. इसके साथ ही वह कार्यकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनें और उन्हें तुरंत हल करने की कोशिश करें.

सूत्रों ने बताया कि प्रदेश भाजपा द्वारा संगठन मजबूत करने के मकसद से जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, उन पर वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही उन्हें हरी झंडी दी जाएगी. अमित शाह ने जाजू से कहा है कि भविष्य में पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पैनी नज़र रखी जाए. शाह ने कहा कि हर कार्यक्रम की समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि आगामी कार्यक्रमों में आवश्यकता के मुताबिक नए एजेंडे शामिल किए जा सकें. शाह ने जाजू को विशेष रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तेजी के साथ बढ़ रही गुटबाजी पर भी नज़र रखने की सलाह दी है. शाह ने उनसे कहा कि वह पार्टी को नुक़सान पहुंचाने वाले तत्वों से सावधान रहें. माना जा रहा है कि शाह की गाइड लाइन के मुताबिक प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि मिशन 2017 में कामयाबी मिल सके. शाह ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत योगपीठ से भले की, लेकिन अब उनकी मंशा है कि कोई भी पार्टी का आका बनने की जुर्रत न करे. इसीलिए शाह ने बाबा को मोदी के स्वभाव के बारे में स्पष्ट बता दिया है कि जब मोदी राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज के पुत्र पंकज के पर कतर सकते हैं, तो दीगर लोगों की मठाधीशी वह भला कैसे बर्दाश्त करेंगे.

यही वजह है कि बाबा ने हरीश के सहारे कांग्रेस का हाथ थामने के खेल की शुरुआत कर दी है. बाबा रामदेव को लगा था कि उनके द्वारा हरीश रावत की खुलेआम सराहना करने से भाजपा में बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन भाजपा के कान पर जूं न रेंगने से उन्हें निराशा हाथ लगी. कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प के साथ शाह के विशेष दूत जाजू देवभूमि के जन-जन में जाकर मोदी की मंशा पूरी करेंगे. जाजू द्वारा किसी खेमे के नेताओं को घास न डालना शाह-मोदी की मंशा का साफ़ संकेत माना जा रहा है. मोदी ने आम चुनाव के पूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं सांसद सतपाल महाराज को भाजपा में शामिल किया था, जिसे लेकर पार्टी नेताओं की आपसी कलह ने इस कदर पानी फेरा कि मात्र एक सीट से पिछड़ने के कारण भाजपा अव्वल नहीं बन पाई. कांग्रेस को इसी का लाभ मिला और वह आज भी सत्ता पर काबिज है. जाजू स्वयं एक आम कार्यकर्ता से नेता बने हैं. शायद इसीलिए उनमें नेतागिरी की बू नहीं दिखती. बहरहाल, भाजपा हाईकमान की उम्मीदें साकार करने के लिए जाजू को कांटों भरे रास्ते से गुजरना होगा. जाजू को क़रीब से जानने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि वह अपने मकसद में कामयाब होंगे और पार्टी प्रमुख शाह की कसौटी पर खरे उतरेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक कराया गया. विजय उत्सव मनाना सही है, लेकिन अगर इसे जनता के लिए ही किया जाना था, तो फिर इस स्टेडियम के बजाय चौपाटी या आज़ाद मैदान बेहतर विकल्प था. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भाजपा पहले से ही अपनी सफलता का उत्सव मनाने के क्रम में नियमों की अनदेखी करने लगी है. अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में प्रशासन अच्छा काम करता है, नौकरशाही जगह पर है. मानदंडों को अगर राजनेता न तोड़ें, तो उनका भी सही ढंग से पालन होता है. नए मुख्यमंत्री, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर नियमों के हिसाब से काम करते हैं, तो महाराष्ट्र में प्रशासन बहुत अच्छा चल सकता है.

राजनीतिक दलों का अराजनीतिक व्यवहार

राजनीतिक परिदृश्य तेजी से अराजनीतिक हो रहा है. महाराष्ट्र में भाजपा ने कुल 288 में से 123 सीटों पर जीत हासिल की. हालांकि, भाजपा अभी दावा कर रही है कि मोदी लहर थी. लहर क्या होती है? लहर का अर्थ है कि कम से कम एक स्पष्ट बहुमत मिले. इससे न कम न अधिक. हालांकि, भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर खुश हो सकती है. इसमें कुछ ग़लत भी नहीं है. लहर लोकसभा चुनाव में थी, जहां उसे स्पष्ट बहुमत मिला. महाराष्ट्र के परिणाम को बहुत उत्साहजनक नहीं माना जा सकता है.

राकांपा ने वक्त की नजाकत को देखते हुए चतुराई से भाजपा को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी. आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की. वास्तव में एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी राकांपा से समर्थन लेने के सवाल पर ज़रूर प्रतिक्रिया देती और कहती कि राकांपा से समर्थन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार के आरोप को देखते हुए उससे कैसे समर्थन लिया जा सकता है. उलटे यह कहा जा सकता था कि राकांपा से समर्थन लेने की जगह हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे. सवाल है कि जब राकांपा का समर्थन लिया जा सकता है, तो कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं लिया जा सकता? पृथ्वीराज चव्हाण की छवि महाराष्ट्र में राकांपा के किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा स्वच्छ है.

व्यापारी और व्यवसायी हमेशा अंकगणित में बात करते हैं और वे 123 सीटें पाकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत मिल गया. राजनीति ऐसे नहीं की जाती. यदि केवल अंकगणित की बात हो, तो कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है. कोई भी किसी से भी समर्थन ले सकता है या दे सकता है. तब विचारधारा के लिए जगह ही नहीं होगी. महाराष्ट्र भाजपा ने भी कोई सैद्धांतिक स्टैंड नहीं लिया, यह निराशाजनक है. अफवाह यह भी है कि नितिन गडकरी और शरद पवार के रिश्ते चूंकि अच्छे हैं, इसलिए यह सब शुरू किया गया.

इसी तरह दूसरी तरफ़ कांग्रेस है. आख़िरकार, मोदी पांच साल के लिए चुने गए हैं. केवल पांच साल बाद ही कांग्रेस को यह मौक़ा मिलेगा कि वह लोगों को समझाए, लेकिन इस सबसे पहले खुद ही अगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है, तो क्या होगा? राहुल गांधी के मन में शायद यह बात है ही नहीं कि पार्टी चलाने के लिए क्या किया जाए, कैसे पार्टी चलाई जाए, कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर वह इस सबमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो उन्हें किसी और को इस काम के लिए नियुक्त करना चाहिए, जो प्रभावी रूप से पार्टी का नेतृत्व करे. 2019 में क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत तो है ही. फिलहाल कांग्रेस फिर से ग़ैर राजनीतिक व्यवहार कर रही है. चिदंबरम ने अभी एक बयान दिया, जो अन्य कांग्रेसियों को पसंद नहीं आया. एक ग़ैर राजनीतिक माहौल फिर से देखने को मिला. कोई भी गंभीरता से अगले चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने में अपना दिमाग नहीं लगा रहा है.

व्यापारी और व्यवसायी हमेशा अंकगणित में बात करते हैं और वे 123 सीटें पाकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत मिल गया. राजनीति ऐसे नहीं की जाती. यदि केवल अंकगणित की बात हो, तो कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है. कोई भी किसी से भी समर्थन ले सकता है या दे सकता है. तब विचारधारा के लिए जगह ही नहीं होगी. महाराष्ट्र भाजपा ने भी कोई सैद्धांतिक स्टैंड नहीं लिया, यह निराशाजनक है. अफवाह यह भी है कि नितिन गडकरी और शरद पवार के रिश्ते चूंकि अच्छे हैं, इसलिए यह सब शुरू किया गया.

महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक कराया गया. विजय उत्सव मनाना सही है, लेकिन अगर इसे जनता के लिए ही किया जाना था, तो फिर इस स्टेडियम के बजाय चौपाटी या आज़ाद मैदान बेहतर विकल्प था. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भाजपा पहले से ही अपनी सफलता का उत्सव मनाने के क्रम में नियमों की अनदेखी करने लगी है. अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में प्रशासन अच्छा काम करता है, नौकरशाही जगह पर है. मानदंडों को अगर राजनेता न तोड़ें, तो उनका भी सही ढंग से पालन होता है. नए मुख्यमंत्री, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अगर नियमों के हिसाब से काम करते हैं, तो महाराष्ट्र में प्रशासन बहुत अच्छा चल सकता है. महाराष्ट्र अच्छा करता रहेगा. हरियाणा में पहले कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने आ रहा था. बाद में मनोहर लाल खट्टर, एक वयोवृद्ध स्वयंसेवक, को मुख्यमंत्री चुना गया. भाजपा को इस राज्य में शासन करने का पहली बार मौक़ा मिला है.

अंततः प्रधानमंत्री ने कम से कम सरकार (गवर्नमेंट) और अधिक से अधिक गवर्नेंस की बात कही है. लोगों को यह तभी महसूस होगा, जब परिणाम सामने आएगा. भाजपा भाग्यशाली है कि पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों में गिरावट आ रही है, भुगतान संतुलन में सुधार होगा, चालू खाता घाटे में भी सुधार होगा. यह सब केंद्र सरकार के लिए अच्छा है. सवाल यह है कि अब कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में आ सकती हैं. यह इतना आसान भी नहीं है. भारत के साथ जो पहले से परिचित हैं, वही कंपनियां ज़्यादा आएंगी. नए उद्यमियों को लाना इतना आसान नहीं है. हालांकि, बुनियादी ढांचे और बिजली उत्पादन आदि पर केंद्र सरकार ध्यान दे रही है. इस सब चीजों का कितना फ़ायदा होता है, यह देखने वाली बात होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

संवाददाता का बुनियादी दायित्व

जिस तरह शरीर में रक्त प्रवाह निर्णय करता है कि शरीर कितना स्वस्थ है, उसी तरह संवाददाता भी अख़बार, पत्रिका या चैनल का स्वास्थ्य तय करता है. संवाददाता ही सप्लाई लाइन है. उसका अख़बार, चैनल या पत्रिका किस तरह का युद्ध लड़ रहे हैं, इस बात का फ़ैसला संवाददाता द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट की विषय-वस्तु द्वारा होता है. संपादक की असली परीक्षा उसके द्वारा संवाददाताओं के चुनाव में होती है, क्योंकि ये संवाददाता ही पाठकों में संपादक के बारे में राय बनाते हैं. संवाददाताओं की रिपोर्ट से ही पाठक अंदाज़ा लगाते हैं कि संपादक कितना अच्छा है, सामान्य है या फिर समझौता करने वाला है. संवाददाता का सीधा रिश्ता अपने राज्य के सत्ताधारी वर्ग, विपक्ष, नौकरशाही के साथ-साथ जनता के उन तबकों से भी होता है, जो समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं. इसीलिए यही लोग अख़बार, पत्रिका या चैनल के बारे में लोगों के बीच राय कायम करने के पीछे मुख्य कारक का काम करते हैं.

संवाददाता की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा गुण उसकी जानकारी है. यह जानकारी उसे जहां से मिले, वहां से हासिल करनी चाहिए. संवाददाता के लिए ज़रूरी है कि वह हिंदी के उपलब्ध कम से कम तीन अख़बार नियमित रूप से पढ़े और हर पत्रिका का नियमित अध्ययन करे. उसे पाठक के रूप में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषा के अख़बार पढ़ने चाहिए. उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह हिंदी के ज़िलों से निकलने वाले दैनिक या साप्ताहिक अख़बारों पर अवश्य नज़र डाले. यह हिंदी का दुर्भाग्य है कि आज हिंदी साहित्य की लघु पत्रिकाएं देखने में कम आती हैं. कभी यह संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी. पर जो भी उपलब्ध हों, उन्हें पढ़ना चाहिए. इससे संवाददाता का भाषा ज्ञान तो बढ़ता ही है, उसे विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों के सोचने और उनके विचार प्रवाह की जानकारी हो जाती है. यह जानकारी उसकी लेखन शैली को रोचक बनाने में मदद करती है. एक अच्छे पत्रकार को किताबों के साथ-साथ कुछ भी पढ़ने की नियमित आदत डालनी ही चाहिए.

संवाददाता का यह कर्तव्य है कि वह हमेशा सोचता रहे कि उसका अख़बार, पत्रिका या चैनल असली या सही ख़बर दे.

संवाददाता सारी सूचनाएं पाठकों को दे, ईमानदारी से दे. लोगों को जो कुछ चाहिए, वह उनको बताए और खुद उससे कोई बेजा लाभ न उठाए. संवाददाता को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह जिसे रिपोर्ट का विषय बनाने जा रहा है, वह है किस श्रेणी का. अक्सर संवाददाता सामान्य रिपोर्ट को खींचने की कोशिश करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए. एजेंसी की रिपोर्ट और संवाददाता की रिपोर्ट में फ़र्क़ होना चाहिए. यह फ़र्क़ केवल इस बात से आता है कि संवाददाता उस रिपोर्ट के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

आख़िर यह असली या सही ख़बर है क्या चीज? हमारे देश में न्यूज एजेंसी जो तय कर दे, वही ख़बर बन जाती है. इतिहास रचने वाले संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि ख़बरों के बारे में बड़ा सरल यार्ड स्टिक (मापदंड) है कि यदि भविष्य काल में होने वाली ख़बरों को निकाल दें और फिर देखें कि ख़बरें क्या हैं, तो हम देखेंगे कि केवल बीस प्रतिशत ख़बरें ही असली ख़बरें बनेंगी. नेता भाषण दे रहे हैं कि हम पुल बनाएंगे, हम यह काम करेंगे, हम वह काम करेंगे-इस प्रकार गा, गे, गी की ख़बरें यदि निकाल दें, तो सचमुच कुछ नहीं बचेगा ख़बरों में. हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई साहसी एक दिन ज़रूर आएगा और कुछ न कुछ करेगा, तो देश का अच्छा अख़बार निकलेगा-पहला.

सुरेंद्र प्रताप सिंह के विश्लेषण से संवाददाताओं के लिए सिद्धांत निकलता है कि असली ख़बर वह है, जो गा, गे, गी या विश्वस्त सूत्रों से या समझा जाता है या कहा जाता है, के विशेषणों से मुक्त हो. संवाददाता सारी सूचनाएं पाठकों को दे, ईमानदारी से दे. लोगों को जो कुछ चाहिए, वह उनको बताए और खुद उससे कोई बेजा लाभ न उठाए. यह सही है कि रिपोर्ट आमुख कथा बनेगी, विशेष रिपोर्ट बनेगी या सामान्य रिपोर्ट के रूप में जाएगी, इसका फ़ैसला संपादक करेगा, पर संवाददाता को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह जिसे रिपोर्ट का विषय बनाने जा रहा है, वह है किस श्रेणी का. अक्सर संवाददाता सामान्य रिपोर्ट को खींचने की कोशिश करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए. एजेंसी की रिपोर्ट और संवाददाता की रिपोर्ट में फ़र्क़ होना चाहिए. यह फ़र्क़ केवल इस बात से आता है कि संवाददाता उस रिपोर्ट के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है.

संवाददाता के लिए ज़रूरी है कि वह हिंदी के उपलब्ध कम से कम तीन अख़बार नियमित रूप से पढ़े और हर पत्रिका का नियमित अध्ययन करे. उसे पाठक के रूप में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषा के अख़बार पढ़ने चाहिए. उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह हिंदी के ज़िलों से निकलने वाले दैनिक या साप्ताहिक अख़बारों पर अवश्य नज़र डाले. संवाददाता का यह कर्तव्य है कि वह हमेशा सोचता रहे कि उसका अख़बार, पत्रिका या चैनल असली या सही ख़बर दे. आख़िर यह असली या सही ख़बर है क्या चीज?

यदि संवाददाता को रिपोर्ट के साथ खड़ा रहना है, तो उसे सबसे पहले रिपोर्ट से संबंधित सारे तथ्य इकट्ठे करने चाहिए. इसके बाद उन तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए. विश्लेषण से आए नतीजों की छानबीन करनी चाहिए और जो परिणाम आए, उसे सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए. संवाददाता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने संपादक की आंख है और उसी के द्वारा संपादक राज्य में या जहां घटना घटती है, उसे देखता है. अतः एक तरह से संवाददाता जगह विशेष पर संपादक के प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है. यह संवाददाता की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वह हर रिपोर्ट से संबंधित सारे प्रमाण संभाल कर रखे, क्योंकि इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि उसे फालोअप रिपोर्ट लिखने में उन प्रमाणों की पुनः आवश्यकता पड़े. फालोअप रिपोर्ट करना संवाददाता के लिए अति आवश्यक है. अक्सर होता है कि कोई रिपोर्ट हुई, उसके बाद लोग उस रिपोर्ट को भूल जाते हैं और संवाददाता भी उस पर ध्यान नहीं देता. पर रिपोर्ट के बाद घटनाचक्र तेजी से घूमता है. प्रशासन, पुलिस या ज़िम्मेदार लोग बाद में या तो और आतंक मचाते हैं या रिपोर्ट छपने के बाद भी ज़िम्मेदार लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ छप गया, अब क्यों करना. इसलिए फालोअप रिपोर्ट की ज़रूरत होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह सवाल देश के तीन जाने-माने नामों से पूछने की इच्छा हो रही है. हालांकि मैं जानता हूं कि इनमें से कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं देगा. सवालों का जवाब देने की परंपरा ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर कोई यही मानता है कि जो वह कर रहा है, वही सही है. अगर कोई जिज्ञासा करे, तो उस जिज्ञासा को ये अपना अपमान मान लेते हैं. लेकिन, फिर भी यह आशा करनी चाहिए कि सवालों या जिज्ञासाओं का जवाब मिलेगा. देश के ये तीन प्रमुख नाम हैं, श्री अन्ना हजारे, श्री रामदेव एवं श्री नरेंद्र भाई मोदी. इन तीनों से सवाल इसलिए पूछना है, क्योंकि इन तीनों की देशभक्ति और जनता के प्रति समर्पण पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है. पर जब किसी को वक्त या इतिहास या ईश्वर इतनी ज़्यादा साख दे कि लोग उनके कहे पर भरोसा करने लगें, तो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वे लोगों की जिज्ञासाओं का उत्तर दें.

देश के अंदर दबा पैसा कब वापस होगा

एक समय बाबा रामदेव ने काले धन पर सवाल उठाया और देश में काला धन वापस लाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की. वह देश भर में जहां-जहां गए, वहां-वहां सभाएं कीं और कहा कि देश की अगली सरकार पर काला धन वापस लाने की ज़िम्मेदारी है और मैं उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद रुपये और डॉलर का फ़र्क़ कुछ इस तरह हो जाएगा, मानो एक रुपया डेढ़ डॉलर में मिल रहा है. अब बाबा रामदेव ने यह हिसाब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जानकारों से बात करके ही लगाया होगा. उनके बाद इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी के महारथी और उस समय के लौह पुरुष कहे जाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी उठाया और आख़िर में यह सवाल श्री नरेंद्र मोदी ने उठाया. बाबा रामदेव ने इस सवाल को देश के सवाल से बदल कर राजनीतिक सवाल बना दिया. भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को लपकने की कोशिश की और जब नरेंद्र मोदी ने अपना अभियान शुरू किया, तब उनके मुख्य वक्तव्यों में एक वक्तव्य सरकार बनने पर सौ दिनों के भीतर काला धन वापस लाने के वादे का था.

इस वादे पर देश के मध्यम वर्ग ने भरोसा किया, क्योंकि मध्यम वर्ग किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहता है. ग़रीब सिर्फ़ सपना देखता है, लेकिन मध्यम वर्ग उस चीज को अपने हक़ में होता हुआ देखना चाहता है और वह इसे सपना नहीं मानता. उसने यह माना कि बाबा रामदेव और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हो गया है और दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं. उसका मानना था कि निश्चित रूप से अगर देश में भाजपा की सरकार बनी, तो वह काला धन वापस लाएगी. भले ही वह सौ दिनों में न ला पाए, लेकिन दो सौ दिनों में तो ज़रूर लेकर आएगी. मध्यम वर्ग ने अपनी सारी ताकत के साथ भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई. इतना ही नहीं, मध्यम वर्ग ने दबे-कुचले वर्गों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया.

अन्ना हजारे ने अपनी देशव्यापी यात्रा में जनतंत्र लाने के तरीके और जनतंत्र की सही व्याख्या सभाओं में बताई तथा उनके इस अभियान ने तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के प्रति लोगों में गुस्सा पैदा किया. अन्ना हजारे द्वारा पैदा किए गए उस गुस्से ने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए एक सुनिश्चित आधार दे दिया. अन्ना हजारे ने अपनी यात्रा में काले धन को लेकर भी बहुत प्रहार कांग्रेस सरकार पर किया. अन्ना हजारे द्वारा पैदा किया माहौल हो या नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दों का असर हो या फिर कुल मिलाकर प्रचार का सफल प्रभाव हो, देश ने पहली बार पिछले 30 सालों में एक पार्टी की सरकार बना दी. अब जब सरकार बन गई, तो देश के वित्त मंत्री तरह-तरह के तर्क देने लगे और मजे की बात ये वही तर्क थे, जो पिछली सरकार में उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम दे रहे थे. वित्त मंत्री के तर्कों पर प्रधानमंत्री की खामोशी समर्थन कर रही थी. बाबा रामदेव की चुप्पी लोगों में संदेह पैदा कर रही थी.

अचानक सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया और उसने काले धन से जुड़े नामों के बारे में एक सख्त रुख अपना लिया. उस सख्त रुख ने इस बहस को दोबारा केंद्रीय बहस बना दिया. ऐसा लगा, मानो जो 627 नाम आए हैं, सिर्फ़ उनके पास काले धन की चाबी है. हम उन ख़बरों में नहीं जाना चाहते, जो कहती हैं कि सरकार ने चोरी से एक सूची मंगाई और यह उस सूची से बिल्कुल अलग है, जो सचमुच काले धन के पहरेदारों, काले धन के रखवालों या काले धन के मालिकों की सूची है. यह सूची स्विट्ज़रलैंड से आई ही नहीं है. स्विट्ज़रलैंड के तीन बैंक, जिनमें यूबीएस सबसे पहले नंबर पर आता है, उसमें किन लोगों के पैसे जमा हैं, इसकी देश में किसी को चिंता नहीं है और क्षमा कीजिएगा, न इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उसने सरकार को काले धन पर अच्छा या बुरा रुख लेने के लिए मजबूर किया.

हम सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहाने यह आग्रह हम अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी और नरेंद्र मोदी जी से भी करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट से हमारा आग्रह है कि काले धन का तिलिस्म पांच सालों में टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा या बयानों में, एसआईटी की जांच में या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होते जजों की शृंखला में, इसका हल हम कब तक देख पाएंगे, पता नहीं. और, हमारी न्याय व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि जितने लोग इस कॉलम को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में तो यह पैसा नहीं आ पाएगा. तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्योंकि, हमें मालूम है कि न नरेंद्र भाई मोदी, न अन्ना हजारे और न बाबा रामदेव इस पर ध्यान देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे सकता है.

हमारे देश का हज़ारों करोड़ या शायद लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों ने कर्ज के रूप में देश के औद्योगिक घरानों को दिया है, जिन्हें हम आजकल कॉरपोरेट हाउसेज कहते हैं. यह सारा पैसा ये औद्योगिक घराने या कॉरपोरेट हाउसेज हजम करके बैठ गए हैं. वे बैंकों का पैसा वापस करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं. अगर यह पैसा ही भारत के बैंकों के पास लौट आए, ब्याज के साथ न सही, अपने मूल में ही आ जाए, तो जो बूस्ट मिलेगा या किक मिलेगी, वह अप्रत्याशित होगी. लेकिन, बैंक भारत सरकार के, बैंकों से कर्ज लेने वाले कॉरपोरेट हाउसेज देश के, उनके नाम बैंकों के पास, बैंकों का पैसा कॉरपोरेट हाउसेज के पास. तो फिर आख़िर उनके नामों की सूची बैंक क्यों नहीं देते? आप आरटीआई डालते रहिए, लेकिन बैंक उसका जवाब नहीं देते. कहते हैं, यह देशहित में नहीं है. देश का पैसा कॉरपोरेट हाउसेज लाखों करोड़ की संख्या में हजम कर जाएं और जब यह पूछा जाए कि किन लोगों ने यह पैसा हजम किया है, किन लोगों ने कितना उधार लिया है, तो उसकी जानकारी न देना देशप्रेम है. क्योंकि, अगर जानकारी देंगे, तो देशद्रोह हो जाएगा. यह कौन-सा तर्क है?

क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या भारत सरकार को यह आदेश नहीं दे सकता कि देश के बैंकों का कितना पैसा कॉरपोरेट हाउसेज पर बकाया है, उसकी जानकारी दें और अगले छह महीनों में उस पैसे को वापस करने की बात कहें? अगर सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता, तो उसके वे सारे तेवर, जो वह काले धन पर दिखा रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है. क्योंकि, तब हमें लगेगा कि उसके तेवर देश के कॉरपोरेट हाउसेज को बचाने का एक तरीका हैं.

हम देश के विकास की गति तेज करने के नरेंद्र मोदी के सपने को कमजोर नहीं होते देखना चाहते, हम उसे और मजबूत होते देखना चाहते हैं. यह तभी हो सकता है, जब देश के बैंकों के लाखों करोड़ रुपये, जो कॉरपोरेट हाउसेज के पास हैं और जिनके वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैंक भी इसमें शामिल हैं, वापस आ जाएं. दरअसल, बैंकों के चेयरमैन, निदेशक एवं शाखा प्रभारी उन कॉरपोरेट हाउसेज से, जिन्होंने पैसे दबा रखे हैं, सुविधा शुल्क लेकर पैसे दबाने में उनकी मदद कर रहे हैं. और, हम यह आरोप लगा रहे हैं, तो इसके हमारे पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं. एक ग़रीब किसान पांच हज़ार रुपये के लिए जेल चला जाता है, अगर वह पैसे वापस नहीं करता. उसकी ज़मीनें कुर्क हो जाती हैं. एक कार मालिक, अगर समय पर किस्तें नहीं दे पाता है, तो उसकी कार उठा ली जाती है. इसके लिए बैंकों ने एक तरीके से दबंग लोगों या कहें कि गुंडों को कमीशन पर रखा हुआ है, लेकिन बैंक उन लाखों करोड़ रुपयों पर खामोश हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज ने दबा रखे हैं. और, वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ मिलकर उनकी सूची बाहर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि उसे यह डर है कि सूची जैसे ही बाहर आएगी, कोई न कोई पीआईएल कर देगा. तब सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर एक रुख लेना पड़ेगा.

क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या भारत सरकार को यह आदेश नहीं दे सकता कि देश के बैंकों का कितना पैसा कॉरपोरेट हाउसेज पर बकाया है, उसकी जानकारी दें और अगले छह महीनों में उस पैसे को वापस करने की बात कहें? अगर सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता, तो उसके वे सारे तेवर, जो वह काले धन पर दिखा रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि, तब हमें लगेगा कि उसके तेवर देश के कॉरपोरेट हाउसेज को बचाने का एक तरीका हैं.

हम क्या सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करें कि आप अगर काले धन पर गंभीर हैं, तो उससे ज़्यादा गंभीरता देश के कॉरपोरेट हाउसेज द्वारा कर्ज के रूप में लिए गए लाखों करोड़ रुपये, जिन्हें सालों हो गए और जिनका वे ब्याज भी नहीं देते, उसे वापस लाने का आदेश दें. क्या हम सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश से यह आग्रह कर सकते हैं कि आप हमारे इस लेख को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करें और देश की सरकार को नोटिस भेजें कि वह कम से कम इतना तो बताए कि देश के बैंकों का कितना पैसा उनके (कॉरपोरेट हाउसेज) ऊपर डूबा हुआ है, कितना पैसा बैंकों ने माफ़ कर दिया है और कितना पैसा अभी भी उन कॉरपोरेट हाउसेज पर बकाया है. क्या देश की जनता को यह जानने का हक़ नहीं है?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से हमारा यह आग्रह है कि आप हमारी इस विनती को सुनिए और भारत सरकार को आदेश दीजिए कि वह देश की जनता का पैसा देश के विकास चक्र को घुमाने में इस्तेमाल करने के लिए उसे औद्योगिक घरानों से वापस ले और देश को सचमुच विकास के युग में ले जाए. क्या बैंकों का पैसा भारत की जनता का पैसा नहीं है? और, इसी हक़ के साथ हम यह आग्रह और आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश की सरकार और बैंकों को आदेश दे कि वे उस पैसे की सार्वजनिक जानकारी दें, जिसे कॉरपोरेट हाउसेज ने दबा रखा है. पहला क़दम अगर उठना है, तो यही उठना है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट सहित बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बहुसंख्या को झूठी आशा दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, ऐसा मानना होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

आज तक विभिन्न राजनीतिक दल यह दावा करते आए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उनके वास्तविक व्यवहार से ऐसा लगता है कि कश्मीर कोई दूसरा देश है. याद कीजिए, किस धूमधाम से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया था. दरअसल, किसी भी दल का कोई भी नेता अपनी इच्छानुसार किसी भी समय कश्मीर जा सकता है.

मोदी का सांकेतिक संदेश

लंदन में मेरे एक मित्र हैं. वह अपने बैंक मैनेजर द्वारा क़र्ज़ उगाही के तकाजे को लेकर बहुत नाराज़ थे. एक दिन वह मैनेजर के दफ्तर में गए और कहने लगे कि अगर आपने मुझे इस तरह के अभद्र पत्र लिखने बंद नहीं किए, तो मैं अपना ओवरड्राफ्ट किसी और बैंक में लेकर चला जाऊंगा. मुझे लगता है कि शिवसेना की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है. पहले तो उसने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके भाजपा-शिवसेना गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश की. उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया. अब जबकि यह साबित हो गया है कि भाजपा की तुलना में उसकी स्थिति कमज़ोर है, तब भी वह यह आशा कर रही है कि भाजपा उसका सहयोग मांगने उसके पास आए. ऐसा न केवल स्थिति के ग़लत आकलन की वजह से है, बल्कि यह उसकी खुशफहमी का भी नतीजा है. हालिया चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा. दरअसल, कांग्रेस के एक परिवार में प्रतिभा की कमी तीन पुश्तों के बाद महसूस हुई, वहीं शिवसेना के लिए बाला साहेब की याद ही सबसे बड़ी पूंजी है. राज ठाकरे की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है. ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां विलय के बारे में सोच तक नहीं रही हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो ये दोनों एक-दूसरे को ख़त्म कर देंगी.

महाराष्ट्र एवं हरियाणा की दोहरी कामयाबी हासिल करके नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि मई में हुए लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी क्षणिक नहीं थी. मतदाताओं ने उनकी महत्वाकांक्षी घोषणाएं पसंद कीं और उनके काम करने की ऊर्जा पर मुहर लगते हुए यह भरोसा जताया कि वह उनके लिए और कड़ी मेहनत करेंगे. मराठी मानुष का नारा शिवसेना का दिया हुआ है, जो समझती है कि लोगों की आकांक्षाएं पाव-भाजी की एक रेहड़ी हैं. ग़ैर मराठियों की तुलना में मराठियों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति से ग़ैर मराठियों के ख़िलाफ़ शिवसेना के प्रचार को मजबूती मिली. लेकिन, अब मराठी मानुष को लग रहा है कि भाजपा उनके लिए एक अच्छा विकल्प पेश कर रही है. वे सदा के लिए पिछड़े नहीं रहना चाहते हैं. दरअसल, जिस तरह से कांग्रेस बीपीएल परिवारों की ऐसी देखभाल कर रही थी कि वे अपनी ग़रीबी से कभी बाहर न निकल सकें, ठीक उसी तरह से शिवसेना अपने पक्षकारों को हमेशा नाकाम ही देखना चाहती थी. इस तरह की राजनीति 19 अक्टूबर को हार गई. एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा की कार्य प्रणाली में अंतर ज़ाहिर हो गया है. जहां भाजपा ने दूसरे चक्र के चुनावों के लिए तैयारियां करते हुए प्रभारियों की नियुक्ति शुरू कर दी, वहीं कांग्रेस अक्टूबर के नतीजों की कौन कहे, लोकसभा चुनाव में अपनी हार की समीक्षा नहीं कर सकी. सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ने तो पहले ही महाराष्ट्र में अपनी हार मानकर कम से कम चुनावी सभाएं कीं. उन्हें कांग्रेस की स्थिति का पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन जो चीज़ उन्हें अब दिखाई नहीं दे रही है, वह है बाहर का रास्ता. होना तो यह चाहिए कि कांग्रेस को यह परिवार सदा के लिए अलविदा कह दे. ऐसा करने से कांग्रेस को एक आधुनिक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में पुनर्गठित करने की आशा फिर भी बची रहेगी. लेकिन, शायद उनसे यह अपेक्षा करना ज़्यादती होगा. भाग्य पर भरोसा और परिवार के स्वामित्व की उनकी भावना उन्हें गरिमा पूर्ण तरीके से बाहर जाने के रास्ते में बाधक बनेंगे और वे अपने नेता के रूप में प्रियंका गांधी की परछाईं का पीछा करते हुए नज़र आएंगे.

अभी देश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, जो है भाजपा. यह एनसीपी के व्यवहार से भी ज़ाहिर होता है. प्रणब मुखर्जी के राजनीति से दूर होने के बाद कभी कांग्रेस में शामिल रहे शरद पवार सबसे वरिष्ठ एवं सक्रिय नेता हैं. उन्हें मालूम है कि कब शर्तें रखनी हैं और कब नहीं. वह यह भी जानते हैं कि कांग्रेस का जहाज डूब चुका है और अगर एनसीपी को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे भाजपा का सहारा लेना पड़ेगा.

अभी देश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, जो है भाजपा. यह एनसीपी के व्यवहार से भी ज़ाहिर होता है. प्रणब मुखर्जी के राजनीति से दूर होने के बाद कभी कांग्रेस में शामिल रहे शरद पवार सबसे वरिष्ठ एवं सक्रिय नेता हैं. उन्हें मालूम है कि कब शर्तें रखनी हैं और कब नहीं. वह यह भी जानते हैं कि कांग्रेस का जहाज डूब चुका है और अगर एनसीपी को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे भाजपा का सहारा लेना पड़ेगा. अगर अगले पांच वर्षों में कांग्रेस का एनसीपी में विलय हो जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं. पवार एक माहिर खिलाड़ी हैं. लेकिन, कहानी का असली हीरो अगली जंग जीतने की तैयारी में लग गया है. दरअसल, मोदी सांकेतिक संदेश देने में माहिर हैं. जबसे वह प्रधानमंत्री बने हैं, वह यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का वैसा ही अंग है, जैसा गुजरात या देश का कोई अन्य राज्य. वह लगातार कश्मीर जा रहे हैं. अभी हाल में उन्होंने दीपावली भी कश्मीर में मनाई है.

हालांकि आज तक विभिन्न राजनीतिक दल यह दावा करते आए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उनके वास्तविक व्यवहार से ऐसा लगता है कि कश्मीर कोई दूसरा देश है. याद कीजिए, किस धूमधाम से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया था. दरअसल, किसी भी दल का कोई भी नेता अपनी इच्छानुसार किसी भी समय कश्मीर जा सकता है. मोदी ने कश्मीर को एक सामान्य राज्य बना दिया है. इस तरह अब उनका नया निशाना जम्मू-कश्मीर के मतदाता हैं. अब उन्हें मुक्का दिखाने की बजाय उनसे हाथ मिलाया जाएगा. एक अल्पसंख्यक की बजाय उनसे आधुनिक महत्वाकांक्षी भाषा में बात की जाएगी. और, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे खुद को भारतीय कहलाना पसंद करने लगें. ■

feedback@chauthiduniya.com

केवल कुछ ही नवजात शिशुओं तथा बच्चों में टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव विकसित होते हैं. डीपीटी के इंजेक्शन के बाद, नवजात शिशु को इंजेक्शन लगाने के स्थान पर दर्द हो सकता है, संभवतः बुखार भी आ सकता है. ऐसी स्थिति में बच्चे को पैरासिटामॉल दिया जा सकता है. खसरे के इंजेक्शन के बाद खसरे जैसे घाव उत्पन्न हो सकते हैं. यह सामान्य बात है. बहुत कम मामलों में, टीकाकरण के तुरंत बाद बच्चों को एलर्जीयुक्त प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं

हिटलर की जासूस थीं माता हारी

ऐसा नहीं है कि जासूसी पूरी तरह से पुरुषों के लिए ही बनाया गया प्रोफेशन है. महिलाओं ने भी जासूसी से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है. महिला जासूसों पर निकाली जा रही सीरीज में इस बार हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसको जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में सजा दी गई थी. उसे फ्रांस में मौत की सजा के तहत सिर में गोली मार दी गई थी. आइए जानने की कोशिश करते हैं इस महिला जासूस के बारे में...

चौथी दुनिया ब्यूरो

दुनिया भर में जब भी महिला जासूसों की चर्चा की जाये और माता हारी का नाम न आए ऐसा संभव नहीं है. हिटलर के लिए जासूसी करने के आरोप में जान गंवाने वाली यह महिला सिर्फ एक जासूस ही नहीं थी बल्कि एक बेहतरीन नर्तकी भी थीं. 1876 में नीदरलैंड में जन्मीं माता हारी का असली नाम गेरत्रुद मार्गरेट जेले था और पेशे से वह एक डांसर थी. भारतीय नृत्यों में भी वह पारंगत थीं, लेकिन उसका असली पेशा अपने शरीर और अदाओं के सहारे बड़े लोगों की जासूसी करना था. कई देशों के शीर्ष सेना अधिकारियों, मंत्रियों, राजशाही के सदस्यों से उसके नज़दीकी रिश्ते थे.

अपने जलवों के लिए मशहूर माता हारी वर्ष 1905 में पेरिस पहुंची थीं. नृत्य में खास अंदाज की वजह से उन्हें बहुत जल्दी लोकप्रियता मिली. शायद उनका डांस ही वह कड़ी था जिसकी वजह से वह लोगों के बीच लोकप्रिय होती चली गईं. इसके बाद डांस की प्रस्तुतियों के लिए ही वह पूरे यूरोप में काफी यात्राएं करने लगीं. माता हारी के नृत्य के लोग कायल हुआ करते थे. पहले विश्व युद्ध के समय तक वह एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में मशहूर हो गई थीं. उनका कार्यक्रम देखने कई देशों के लोग और सेना के बड़े अधिकारी पहुंचा करते थे. इसी मेलजोल के दौरान गुप्त जानकारियां एक से दूसरे पक्ष को दी जाने लगीं. ऐसा माना जाता है कि माता हारी हिटलर और फ्रांस दोनों के लिए जासूसी किया करती थीं. हालांकि उनकी मौत के बहुत बाद सत्तर के दशक में जब जर्मनी के गोपनीय दस्तावेज बाहर आए तो इस बात से पर्दा उठ गया कि वह जर्मनी के लिए ही जासूसी करती थीं. जासूसी के आरोप में उन्हें वर्ष 1917 में फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि जब तक उन पर मुक़दमा चला तब तक उन्होंने कभी नहीं माना कि वे एक जासूस हैं. वे लगातार इस बात का विरोध करती रहीं. उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि मैं सिर्फ एक नृत्यांगना हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. लेकिन मुक़दमे में उन पर गुप्त जानकारी दुश्मन पक्ष को देने का आरोप सिद्ध हुआ. सजा के तौर पर आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें गोली मारने की सजा दी गई.

यह भी कहा जाता है कि माता हारी बनने के लिए सिर्फ खूबसूरती ही आवश्यक नहीं है. उनके बारे में कहावत है कि वैसा बना नहीं जा सकता है कि सिर्फ पैदा ही हुआ जा सकता है. जेले वास्तव में बेडौल शरीर की मल्लिका थीं, जिसे ख़ूबसूरत न होने के कारण एक डांसिंग ग्रुप में जगह नहीं मिली थी और मजबूरी में उन्हें एक सर्कस में काम करना पड़ा था. किसी ने कहा है कि जेले अपने जिस्म पर कपड़ों के साथ भी उतनी ही अच्छी दिखती थी, जितनी उनके बिना. अब यह उसकी प्रशंसा है या कुछ और, यह तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जेले को अपने जिस्म की नुमाइश के लिए मजबूर होना पड़ा था. वह अपने पति को छोड़ चुकी थीं, जो नीदरलैंड की शाही सेना में अधिकारी था और इंडोनेशिया में तैनात था, लेकिन वह अव्वल दर्जे का शराबी था. वह शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई किया करता था. लेकिन जेले के पास एक अद्भुत प्रतिभा थी, हक़ीक़त के साथ सपनों की दुनिया को जोड़ने की. जावा में रहते हुए उसने भारतीय कामकला के रहस्यपूर्ण गूढ़ार्थों को समझा (तभी उसे माता हारी का नाम मिला) और उसके इस नए अवतार का जादू लोगों के दिलोदिमाग़ पर छा गया. सच कहें तो वह कोई बहुत बड़ी जासूस नहीं थी, जासूसी से ज़्यादा वह सुख-सुविधाओं की शौक़ीन थीं. इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे. उसकी इस कमज़ोरी को जर्मन अधिकारियों ने भांप लिया.

आप इसे प्रलोभन कहिए या कुछ और लेकिन अगर आप दुनियाभर के बेहतरीन जासूसों की श्रेणी बनाते हैं तो उसमें आपको माता हारी को रखना ही होगा. क्योंकि वह एक ऐसे समय की नायिका थी जिस समय दुनिया में सिर्फ युद्ध का गुबार ही नज़र आता था. लंबे समय तक माता हारी को उनकेकाम के लिए याद रखा जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाल टीकाकरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

टीककरण क्या है और यह कैसे काम करता है?

टीकाकरण मानव शरीर को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने का एक तरीका है. टीकाकरण हमारे शरीर को रोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करता है या कहें कि शरीर में उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है. शिशु कुछ प्राकृतिक टीककरण के साथ जन्म लेते हैं, जो उन्हें उनकी माता तथा स्तनपान द्वारा प्राप्त होता है. यह धीरे-धीरे कम होने लगता है, जैसे-जैसे शिशु की स्वयं की टीकाकरण प्रणाली विकसित होना आरंभ होती है. शिशु का टीकाकरण कराना उसे प्राणघातक बीमारियों के विरुद्ध अतिरिक्त बचाव प्रदान करता है.

टीकाकरण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं?

केवल कुछ ही नवजात शिशुओं तथा बच्चों में टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव विकसित होते हैं. डीपीटी के इंजेक्शन के बाद, नवजात शिशु को इंजेक्शन लगाने के स्थान पर दर्द हो सकता है, संभवतः बुखार भी आ सकता है. ऐसी स्थिति में बच्चे को पैरासिटामॉल दिया जा सकता है. खसरे के इंजेक्शन के बाद खसरे जैसे घाव उत्पन्न हो सकते हैं. यह सामान्य बात है. बहुत कम मामलों में, टीकाकरण के तुरंत बाद बच्चों को एलर्जीयुक्त प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं. साथ ही यदि शिशु को बुखार आ जाये या वह बेहोश हो जाए तो तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श लिया जाना चाहिए. टीकाकरण करने वाले लोग एलर्जीयुक्त प्रतिक्रियाओं की स्थिति से निबटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और यदि बच्चे का तुरंत उपचार किया जाए, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है.

कभी-कभार बच्चे को दूसरे व तीसरे टीके के लिये ठीक एक महीने बाद ले जाना संभव नहीं होता है. यदि ऐसा हो, तो क्या पूरा कोर्स दोहराया जाना चाहिए?

नहीं, हल्के से विलंब से कोई फर्क नहीं पडता है. अनुसूची के अनुसार टीकाकरण जारी रखें और जितनी जल्दी हो सके, कोर्स पूरा करें. बच्चा तभी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा जब उसे 1 बीसीजी इंजेक्शन, 3 डीपीटी इंजेक्शन, 3 ओपीवी(ओरल पोलियो वेक्सीनेशन) की खुराकें तथा खसरे का एक इंजेक्शन लग जाए. अतः सही समय पर बच्चे को टीकाकरण के लिए ले जाना और यह सुनिश्चित करना कि टीकाकरण पूर्ण हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है.

क्या कोई ऐसे कारण हैं कि मेरे बच्चे का टीककरण नहीं किया जाए?

बच्चे को प्रतिरक्षित न किया जाए, इसके बहुत कम कारण हैं. सामान्यतः जुकाम या दस्त जैसी आम बीमारियां आपके बच्चे को टीके देने के लिए रुकावट नहीं होती हैं. हालांकि ऐसी कुछ स्थितियां हैं, जिनमें आपको अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को अपने बच्चे की स्थितियों के बारे में बताना चाहिए. इनमें से कुछ ये हैं: बच्चे को तेज़ बुखार हो, उसे अन्य टीककरण पर खराब प्रतिक्रिया हुई हो. उसे अंडे खाने पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई हो, या पहले कभी फिट आए हों. (सही सलाह से, जिन बच्चों को पूर्व में चक्कर आए हों, उन्हें प्रतिरक्षित किया जा सकता है), उसको कैंसर रहा हो, या उसका कैंसर के लिए इलाज चल रहा हो, उसे ऐसी कोई बीमारी हो जो टीककरण प्रणाली को प्रभावित करती हो. उदाहरण के लिए, एचआइवी या एड्स, वह ऐसी कोई दवा ले रहा हो जो टीककरण प्रणाली को प्रभावित करती है, उदाहरण के लिए,अंग प्रत्यारोपण के बाद या प्राणघातक रोग के लिए दी जाने वाली दवा.

> **सामान्यतः जुकाम या दस्त जैसी आम बीमारियां आपके बच्चे को टीके देने के लिए रुकावट नहीं होती हैं. हालांकि ऐसी कुछ स्थितियां हैं, जिनमें आपको अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को अपने बच्चे की स्थितियों के बारे में बताना चाहिए. इनमें से कुछ ये हैं: बच्चे को तेज़ बुखार हो, उसे अन्य टीककरण पर खराब प्रतिक्रिया हुई हो, उसे अंडे खाने पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई हो या पहले कभी फिट आए हों.**

बीसीजी का टीका केवल बाईं भुजा पर ऊपर क्यों लगाया जाता है?

बीसीजी का टीका एकरूपता बरकरार रखने के लिए तथा सर्वेक्षकों द्वारा टीकाकरण हो जाने की पुष्टि करने में आसानी के लिए बाईं भुजा पर ऊपर लगाया जाता है.

किस आयु तक बच्चे को ओपीवी दिया जा सकता है?

बच्चों को ओपीवी 5 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है.

यदि बगैर कोई टीका लगा 2 से 5 वर्ष आयु का बच्चा आता है, तो उसे कौन से टीके दिये जाने चाहिए?

यदि बगैर कोई टीका प्राप्त 2 से वर्ष आयु का कोई बच्चा आता है, तो न्यूनतम 4 हफ्तों (या एक महीने) के अंतर पर ओपीवी के साथ डीटी की दो खुराकें दी जा सकती हैं. डीटी की पहली खुराक के साथ खसरे के टीके की एकल खुराक देने की भी आवश्यकता होती है.

यदि किसी लड़की को उम्र के 16 साल तक एनआईएस के अनुसार डीपीटी, डीटी और टीटी की सभी खुराक प्राप्त हुई हों और वह 18 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है, तो क्या गर्भावस्था के दौरान उसे टीटी की एक खुराक दी जानी चाहिए?

अनुसूची के अनुसार गर्भावस्था के दौरान टीटी की दो खुराक दें.

यदि कोई बच्चा जिसे कभी कोई टीका नहीं लगाया गया हो, उम्र के 9 महीनों में लाया जाता है, तो सभी आवश्यक टीके क्या उसे उसी एक दिन में दिये जा सकते हैं?

हां, सभी आवश्यक टीके एक ही सत्र के दौरान दिए जा सकते हैं, लेकिन शरीर में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सीरिंज का उपयोग कर, इंजेक्शन देकर ऐसा किया जा सकता है. 9 महीने उम्र के जिस बच्चे को कभी कोई टीका नहीं लगाया गया हो, उसे एक ही समय में बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी और खसरा के टीके और विटामिन ए देना सुरक्षित व प्रभावी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

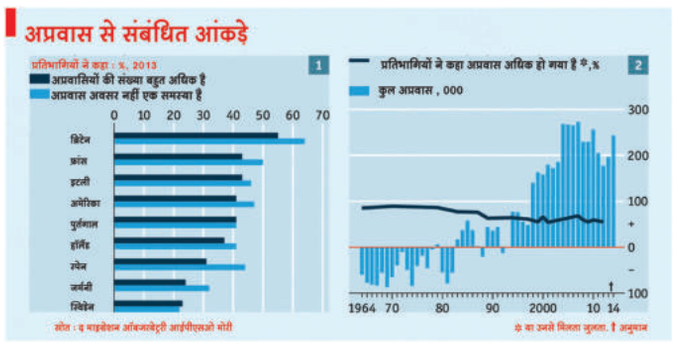

अप्रवास के मुद्दे पर टोरी पार्टी के रुख और यूकेआईपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए लेबर पार्टी ने भी अपना रुख बदल दिया है. दरअसल, आम लोगों की मांग को वह भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती. इसलिए टोरी पार्टी के सुर में सुर मिलते हुए लेबर पार्टी के नेता एड मिलिबैंड ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो वह कम कुशल मजदूरों के देश में आने पर रोक लगाएंगे.

अप्रवास क़ानून

यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन फिर आमने-सामने

शफ़ीक आलम

ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है. चाहे वो यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के शामिल होने की बात हो हो या फिर साझा यूरोपीय मुद्रा की बात, ब्रिटेन में इसको लेकर कभी आम सहमति बनाने में काफी समय लगा था. फिलहाल ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अप्रवासी राजनीति का मुद्दा बना हुआ है. देश के राजनीतिक क्षितिज पर तेज़ी से उभरते यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी (यूकेआईपी) ने यूरोपियन यूनियन से अप्रवास के मुद्दे को देश के राजनीतिक पटल पर प्रमुखता से उठाया है. उनका कहना है कि अप्रवास के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए अप्रवास के कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. लेकिन हाल ही में प्रकाशित कुछ अध्ययन में यह दिखाया गया है कि ब्रिटेन में आए अप्रवासियों ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ब्रिटेन को समृद्ध किया है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि शोध के इन आंकड़ों के बावजूद सरकार इस कानून को लेकर यूरोपियन यूनियन से दो-दो हाथ करने को तैयार है? और इन शोध पत्रों में प्रकाशित आंकड़े क्या कहते हैं?

हालिया दिनों में ब्रिटेन में अप्रवास विरोधी, यूरोपीय यूनियन विरोधी और विदेशियों को नापसंद करने वाली पार्टी यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी (यूकेआईपी) की लोकप्रियता में असाधारण बढ़ोतरी हुई है. जिस पार्टी को पहले अनुपयुक्त लोगों की जमात, विदेशी लोगों को नापसंद करने वाली पार्टी, कट्टरपंथी और फासिस्ट जैसे शब्दों से याद किया जाता था वहीं पार्टी (अगर अख़बारों में छपे चुनाव-पूर्व सवेक्षणों को सही मान लें तो) अगले वर्ष मई में होने वाले आम चुनावों में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और यह भी हो सकता है कि त्रिशंकु संदन कि स्थिति में सत्ता की चाबी इसी पार्टी के पास हो. इन सर्वेक्षणों में प्रस्तुत किये गए आंकड़ों पर एक महीने पहले संपन्न हुए उप चुनावों में एक सीट पर पार्टी की जीत ने भी मुहर लगा दी है. इन्हीं नतीजों से उत्साहित हो कर युकेआईपी ने पार्लियामेंट की सभी 650 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है. ज़ाहिर है यह ब्रिटेन की दोनों बड़ी पार्टियों कंज़र्वेटिव पार्टी (टोरी) और लेबर पार्टी के लिए खतरे का संकेत है. लेकिन टोरी पार्टी को अपने वोट आधार में सेंध की आशंका अधिक है.

अभी हाल ही में टोरी पार्टी छोड़ कर यूकेआईपी में शामिल हुए मार्क रेकलेस अप्रवास के संबंध में कहते हैं कि हम (ब्रिटिश लोग) एक द्वीप पर रहने वाले लोग लोग हैं. नवागंतुक लोग हम में घुल-मिल नहीं पाते, इसी वजह से केंट का कुछ हिस्सा विदेशियों का घेटो (पृथक बस्ती) बन गया है. और यह कि कोई आजादी से इस इलाके से होकर आ-जा नहीं सकता है. अप्रवास पर शिकंजा कसने के मुद्दे पर यूकेआईपी के विचारों से सहमति जताते हुए रेकलेस ने टोरी पार्टी छोड़ी थी. यूकेआईपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के दूसरे कारण भी हैं. चूंकि समस्त यूरोप में दक्षिणपंथी विचारधरा को समर्थन मिल रहा है, जिसका लाभ यूकेआईपी जैसी पार्टियां ले रही हैं. इस विचारधारा की लोकप्रियता में वृद्धि के कारणों में 9/11 के हमलों और और उससे पैदा स्थिति, यूरोप में हुए आतंकवादी हमले, पश्चिम एशिया में चल रही हिंसा की लहर, अर्थव्यवस्था की ख़राब हालत शामिल हैं (देखिए चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट-पश्चिमी देशों में क्यों बढ़ रही है मुस्लिम विरोधी भावना और अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों पर हमले).

इस मसले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, यूकेआईपी को न तो हलके में लेना चाहते हैं और न ही किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. अख़बारों द्वारा कराये जा रहे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में दिखाई जा रही यूकेआईपी की लोकप्रियता को भी वह नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. दी आब्जर्वर अख़बार द्वारा 26 अक्टूबर को छपे एक सर्वे के मुताबिक उन सीटों पर जहां से युकेआईपी के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना ज्यादा है, वहां कम से कम इस पार्टी को 30 प्रतिशत मत मिलेंगे. साथ में टोरी पार्टी के कई नेता दल बदल कर यूकेआईपी में शामिल हो चुके हैं. कैमरन ने यह बयान दिया था कि अप्रवास पर लगाम लगाने के लिए वह यूरोपियन यूनियन की मेम्बरशिप पर यूनियन से नए सिरे से बातचीत करेंगे. उनके मुताबिक यह वार्ता ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में बने रहने या बहार जाने को लेकर 2017 में कराये जाने वाले जनमत संग्रह से पहले होगी. यह समझना कोई मुश्किल नहीं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह बयान क्यों दिया.

ब्रिटेन में हर साल तकरीबन तीन लाख ऐसे अप्रवासी आते हैं जो यहां के नर्म कानून का फायदा उठाकर यहीं रह जाते हैं. सर्वेक्षणों के मुताबिक ब्रिटेन के तीन चौथाई लोग अप्रवास पर लगाम लगाने के पक्ष में हैं. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अप्रवास पर लगाम लगाना संभव है? टोरी पार्टी की सरकार ने तो पहले से ही यूरोपियन यूनियन के अलावा दूसरे देशों से होने वाले अप्रवास पर नियंत्रण लगा रखा है, जो कुल अप्रवास का आधा है. अब इस से अधिक नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने से एक परिवार के पति, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के अधिकारों की अवहेलना होगी, जो इस कानून की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे. दूसरी तरफ कैमरन यूरोपीय यूनियन पर पाबन्दी लगाने से पहले कई बार सोचेंगे क्योंकि उनके इस कदम से जहां एक तरफ यूरोपीय यूनियन कमज़ोर होगा, वहीं सदस्य देशों के नागरिकों के एक देश से दूसरे देश में आज़ादी से आने-जाने के अधिकार पर भी हमला होगा.

अप्रवास कानून का विरोध करने वालों के इस तर्क कि इससे देश की संप्रभुता पर खतरा है, को भी कैमरन नज़र अंदाज़ नहीं कर सकते. इसीलिए वह बीच का रास्ता निकलने की कोशिश करते हुए अप्रवास पर एक दम से प्रतिबन्ध लगाने के पक्षधर नहीं हैं. वह देश के अंदर रुकने और आज़ादी के साथ आने जाने पर यूनियन के नए सदस्य के लिए पहले से ही से ही नई शर्तों का ऐलान कर चुके हैं. मिसाल के तौर पर अगर तुर्की जैसे नए सदस्य को यूरोपीय यूनियन में शामिल होना है तो उससे किसी अन्य सदस्य देश में आने-जाने और काम करने की आज़ादी तभी मिलेगी जब तुर्की की प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपियन यूनियन के बराबर होगी. यह बहरहाल एक विवादस्पद मुद्दा है और इसकी अहमियत इस लिए भी नहीं है क्योंकि निकट भविष्य में किसी नए सदस्य के यूनियन में आने की संभावना नहीं है.

अप्रवास के मुद्दे पर टोरी पार्टी के रुख और यूकेआईपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए लेबर पार्टी ने भी अपना रुख बदल दिया है. दरअसल, आम लोगों की मांग को वह भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती. इसलिए टोरी पार्टी के सुर में सुर मिलते हुए लेबर पार्टी के नेता एड मिलिबैंड ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे कम कुशल मजदूरों के देश में आने पर रोक लगायेंगे. वह कहते हैं कि सत्ता में आने के एक साल के अन्दर एक इमीग्रेशन बिल लाया जायेगा.

दरअसल अगर दूसरे तथ्यों पर नज़र डाली जाये तो मालूम होगा कि इस विषय पर राजनीति अधिक हो रही है और ज़मीनी हकीक़त कुछ और है. पिछले दो वर्षों में प्रकशित दो रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन में अप्रवासियों ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ब्रिटेन को समृद्ध किया है. जहां तक नागरिक सुविधाओं का फायदा उठाने की संभावनाओं का सवाल है तो इस मामले में वे मूल ब्रिटिश नागरिकों से काफी पीछे हैं. मिसाल के तौर पर वर्ष 2013 में प्रकाशित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ़ माइग्रेशन के एक शोधपत्र में यह कहा गया था कि 2002 के बाद से ब्रिटेन में आए अप्रवासियों के सामाजिक सुरक्षा गृहों में रहने और फ़ायदे उठाने की संभावना ब्रिटेन में जन्मे लोगों के मुक़ाबले कम है. उसी तरह 1999 के बाद आने वाले अप्रवासियों को 2000-2001 में ब्रिटिश नागरिकों के मुक़ाबले सरकारी सुविधाएं और टैक्स क्रेडिट्स मिलने की संभावना 45 प्रतिशत कम है. इस अध्ययन के मुताबिक संसाधन निकासी की बजाय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान उल्लेखनीय रूप से अधिक है. साथ ही अप्रवासी लोगों को सामाजिक सुरक्षा गृहों में रहने की संभावना भी अन्य नागरिकों की तुलना में 3 प्रतिशत कम है.

हालांकि इस रिपोर्ट की आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है. माइग्रेशन वॉच के सर एंड्रयू ग्रीन कहते हैं रिपोर्ट उल्ट दी गई है. उनका कहना है कि पिछली सरकार के समय ब्रिटेन में यहां करीब 40 लाख अप्रवासी थे. इनमें से दो-तिहाई यूरोपीय यूनियन के बाहर के थे. और यह कि 1995 से उन्होंने कुल मिलाकर नकारात्मक योगदान ही दिया है. इसलिए गैर-यूरोपियन यूनियन का योगदान या तो बेहद कम है या नकारात्मक है. अलबत्ता वह यह मानने को तैयार हैं कि अगर पूरे यूरोपियन यूनियन को सामने रख कर देखा जाये तो फ़ायदा यकीनन सकारात्मक था. बहरहाल इस रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि सरकार के अप्रवासियों की संख्या में अगर बहुत ज्यादा कमी की तो इसके नतीजे नकारात्मक हो सकते हैं.

ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पिछले एक दशक के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता है कि ब्रिटेन की एक बहुसंख्यक आबादी यह सोचती है कि अप्रवास की संख्या ज़रूरत से अधिक है. पिछले दशक के मध्य से यूरोपियन यूनियन से काम की तलाश में ब्रिटेन आने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अप्रवास के लिए आम जनता के नकारात्मक राय में भी अचानक वृद्धि हुई थी. लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड के सर्वेक्षण के मुताबिक सांस्कृतिक चिंताएं आर्थिक चिंताओं से कम हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रवासियों से नजदीकी की वजह से ब्रिटेन के नागरिकों में सहिष्णुता बढ़ी है, और ठीक इसके उलट अप्रवासियों से दूरी के कारण अप्रवास को लेकर उनके मन में नकारात्मक सोच पैदा हुई है.

इस में कोई शक नहीं कि अप्रवासियों का मुद्दा फ़िलहाल ब्रिटेन में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है. यह अलग बात है कि कैमरन और दूसरे बड़े दल और उनके नेता सभी तर्कविहीन मुद्दों पर जनता की हाँ में हाँ नहीं मिला तो सकते, लेकिन हालिया सर्वेक्षणों से ज़ाहिर होता है कि अप्रवास के खिलाफ यहां जनता में असंतोष है. इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा कर दक्षिण पंथी पार्टी युकेआईपी ने हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में एक सीट पर जीत हासिल की थी. अगले साल मई में आम चुनाव होने वाले हैं इस लिए कोई भी दल कम से कम जानत में इस मुद्दे को लाकर फैले असंतोष को यह कह कर नज़र अंदाज़ नहीं कर सकता कि युकेआईपी बढ़ती हुई लोकप्रियता यूरोप में दक्षिणपंथी विचारधारा में आम वृद्धि की वजह से है. हालांकि आंकड़े यह साबित करते हैं कि अप्रवास की वजह से इस देश को नुकसान से ज़्यादा फायदा हुआ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

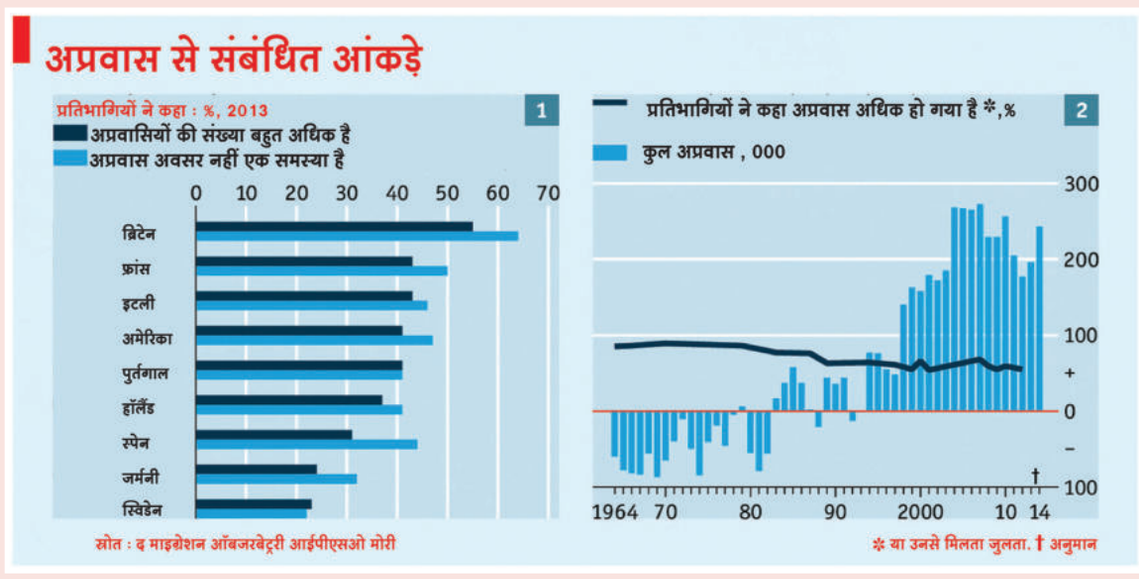

> मैंने जानबूझ कर तुम्हें अलग–अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था. मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम तीन बातों को गांठ बांध लो. पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लम्बे समय तक देखना–परखना चाहिए. दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता, जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा–भरा या फलों से लदा रहता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढाव आते रहते हैं.

निराली है साई बाबा की महिमा

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा की महिमा अपरंपार है और वह धन्य है. साई का क्षणमात्र अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं. शिरडी ही साई बाबा है और साई बाबा ही शिरडी. दरअसल, एक–दूसरे का प्रत्यक्ष पर्यायवाची होने के साथ–साथ यह आध्यात्मिक भी है. साई शब्द के उच्चारण से आशा और आदर का भाव उत्पन्न होता है. साई बाबा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. ऐसा माना जाता है कि साई बाबा 1858 में औरंगाबाद से एक शादी समारोह में शिरडी आए थे. उन्होंने सबसे पहला शिविर खंडूबा मंदिर में लगाया था. वर्तमान समय में यह मंदिर श्री साई बाबा संस्थान के सामने स्थित है. शुरू–शुरू में खंडूबा मंदिर के पुरोहित थे भगत महालसापति. उन्होंने साई बाबा का स्वागत किया, आओ साई कहकर. साई एक संत के रूप में जाने जाते हैं. पश्चिम महाराष्ट्र स्थित शिरडी भारत का प्रमुख धार्मिक स्थान है. साई बाबा ने महालसापति से कहा था कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें पाला किसी मुस्लिम फकीर ने किया था. साई लोगों के घर–घर जाकर उनसे अल्ला मालिक कहकर भिक्षा मांगा करते थे. बाबा प्रत्येक व्यक्ति से न केवल रात–दिन, बल्कि सप्ताह के सातों दिन ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा करते थे. बाबा का कहना था कि दाकूरनाथ, विट्ठल और रणछोड़ (सभी कृष्ण के नाम), ये सब भी शिरडी में निवास करते हैं.

साई बाबा ने 15 अक्टूबर, 1918 को देह त्याग किया. वर्तमान समय में शिरडी में साई बाबा की सफेद संगमरमर की समाधि और एक बड़ी सी मूर्ति है. श्री साई बाबा संस्थान एक विशाल प्रशासकीय इमारत और आध्यात्मिक मंदिर है. यहां स्थित शांति निवास में श्री साई वेंगमे कर्कशा नामक एक पुस्तकालय भी है. समाधि मंदिर में साई बाबा की समाधि है. प्रवेश स्थान से समाधि मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर है. मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है. मंदिर में चार बार आरती होती है. सुबह 5.15 पर होने वाली कक्कड़ आरती सबसे प्रमुख है. शिरडी में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी हैं. इन त्योहारों के समय 24 घंटे के लिए समाधि मंदिर खुला रहता है.

श्री साई बाबा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारकामाई में ही ठहरे थे. द्वारकामाई एक पुरानी उबड़–खाबड़ मस्जिदनुमा कोठी थी. यहां बैठकर वह लोगों की समस्याओं, बीमारियों और चिंताओं को दूर करते थे. उनका मानना था कि सबका मालिक एक है. द्वारकामाई के प्रथम तल पर बाबा की फोटो और एक बड़ा पत्थर रखा है, जिस पर बाबा बैठा करते थे. यहां दो कमरे हैं. पहले कमरे में रथ और दूसरे में पालकी रखी है. पत्थर का एक चौकोर स्टूल भी है, जिसका इस्तेमाल बाबा नहाने के लिए करते थे. द्वारकामाई मस्जिद समाधि मंदिर के प्रवेश द्वार की दाईं ओर स्थित है. गुरुस्थान एक छोटा सा मंदिर है. इसमें शिवलिंग और साई बाबा की तस्वीर है. इस मंदिर में गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं. यह वह स्थान है, जहां साई बाबा ने पहली बार शिरडी में बाल योगी के रूप में प्रवेश किया था. इसीलिए इसे गुरुस्थान के रूप में जाना जाता है. यहां एक छोटी सी मस्जिद भी है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिवलिंग और नंदी का चित्र बना हुआ है. इसके अलावा, मंदिर में बारह ज्योतिर्लिंगों के चित्र भी लगे हैं. द्वारकामाई से थोड़ी ही दूरी पर साई बाबा की चावड़ी है. इस स्थान का प्रयोग बाबा सोने के लिए करते थे. चावड़ी दो भागों में विभाजित है. चावड़ी के पहले हिस्से में बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो लगी है, वहीं दूसरे हिस्से में लकड़ी का पलंग और सफेद कुर्सी भी रखी हुई है.

इसके अलावा, यहां शिरडी शनि, गणपति और शंकर के नाम से मंदिर भी हैं. गुरुस्थान से थोड़ी सी दूरी पर लेंडी बाग है. इसे स्वयं बाबा ने बनाया था. वह हर रोज यहां स्वयं पानी दिया करते थे. बाबा ने इस बाग को नुल्लाहा नाम दिया. इस बाग में बाबा सुबह–शाम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए आते थे. इस बाग में आठ जगहों पर संगमरमर के पत्थरों से बने दीपगृह (नंदा दीप) हैं. यहां एक तरफ पीपल का पेड़ है, दूसरी ओर नीम का. खंडूबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है. इसी मंदिर में पुजारी महालसापति ने साई बाबा का स्वागत आओ साई कहकर किया था. इस मंदिर में खंडूबा और महलसाई की मूर्तियां हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

खुदरा कारोबार पर खतरा

देश में रिटेल ऑनलाइन(ई–कामर्स) खरीददारी का कारोबार बहुत तेजी से फल–फूल रहा है. कई नामी एवं बड़ी देशी–विदेशी कंपनियां इस कारोबार में लिप्त हैं. फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी ने 6 अक्टूबर को 615 करोड़ रुपये की बिक्री कर एक रिकॉर्ड बनाया. बिक्री के उपरांत बेचे गए उत्पादों की गारंटी तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिंह भी लगे. ऐसे आंकड़ो से देश के छोटे खुदरा व्यापारियों की रोजी–रोटी के भविष्य पर संकट के बादल मडराने लगे हैं. कंपनी मामलों तथा वाणिज्य मंत्रालय से विनम्र निवेदन है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रतिस्पर्धा संबंधी कानून, विदेश पूंजी प्रवाह तथा ग्राहक संबंधी इत्यादि नियमों की नए सिरे से विवेचना हो तथा एक नियामक की भी स्थापना करें. मन में यह भी यह भी संदेह होता है कि एफडीआई–रिटेल में विदेशी कंपनियों के प्रवेश की कोई बैकडोर स्थिति तो नहीं बनने जा रही है.

–रणवीर सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

पप्पू यादव का राज

राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक तरफ सांसद बनकर लोकतंत्र के पहरेदार बने फिरते हैं, दूसरी तरफ सहरसा एवं मधेपुरा में अपनी खुद की बनाई हुई व्यवस्थाओं को जनता के ऊपर थोपकर उन्हीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं. उनकी व्यवस्था के अर्न्तगत पुलिस, वकील एवं न्यायाधीश तीनों पप्पू यादव ही हैं और मुलजिम हमेशा से लाचार जनता है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से वे राज्य के विभिन्न जिलों का ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही उजागर होती है. अपने गढ़ में तो वे एक सामान्तर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को पूरे राज्य को चलाने का जिम्मा दे दिया गया, तो फिर उस राज्य का भगवान ही मालिक होगा.

चिकित्सकों के खिलाफ उनकी जो मुहिम है, उसका हम सर्मथन करते हैं, लेकिन उनके मुहिम का जो तरीका है, वो बिल्कुल गलत है. वो सांसद हैं अपने अधिकार का प्रयोग कर उन विशेषाधिकारों के तहत वे कानून में बदलाव लाने की मुहिम चला सकत हैं, लेकिन लगता है कि माननीय सांसद महोदय (नो एफ. आई. आर–नो अरेस्ट) फैसला ऑन द स्पॉट वाली पद्धति पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं. ***–संजय कुमार, समस्तीपुर, बिहार.***

लव जिहाद

लव जिहाद करने वाले को जान से मार देने की बात से मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन क्या किसी को मार देने से यह घिनौना कार्य रुक जाएगा. झारखंड, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में लव जिहाद की खबरों पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं शिया धर्मगुरू कल्वे शादिक की घोषणा की उन मुस्लिम युवकों को जान से मार देना चाहिए, जो इश्क और शादी के नाम पर धर्मपरिवर्तन का काम करवाते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम. सलीम भी इसे नाजायज कहते हैं, कि किसी तरह का झूठा वादा करके लड़कियों को बहला–फुसलाकर शारीरिक संबंध के बाद, जो धर्मपरिवर्तन का काम करते हैं. नि:संदेह यह अत्यंत घृणित कार्य निन्दनीय और दण्डनीय है. कुछ लोग इसे प्रम प्रसंग का मामला बताकर लीपा पोती करना चाहते हैं. एक धर्म के लड़के दूसरे धर्म की लड़की को गुमराह कर शादी करने के बाद उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं. इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है. अत: लवजिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है.

–विनोद कुमार तिवारी, फारबिसगंज, बिहार.

राम मंदिर विवाद

कवर स्टोरी–राम मंदिर विवाद कांग्रेस ने पैदा किया(27 अक्टूबर–02 नवंबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. शीतला सिंह के इस आलेख को पढ़कर पता चलता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार राम मंदिर विवाद पैदा किया. अपने को सेक्युलर कहने वाली कांगेस की सारी सच्चाई इस आलेख से देश के सामने आ चुकी है, वो चाहे मूर्ति रखना हो या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना इन सबमें कांग्रेस का हाथ था. अभी देश के लोगों को यही पता था कि राम मंदिर का विवाद भाजपा और आरएसएस ने पैदा किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. इस आलेख से कांग्रेस की मौकापस्ती देश के सामने आ चुकी है कि उसने किस प्रकार सत्ता के लिए देश में राम मंदिर का विवाद खड़ा किया और अपना राजनीतिक हित साधने के लिए उसे किस प्रकार सांप्रादायिक मुद्दा बनाया. यह कैसे हो सकता है कि कांग्रेस नेता 1948 में हुए फैजाबाद उपचुनाव में अयोध्या में अयोध्या की अस्मिता बचाओ के नारे लगा रहे हों और कांग्रेस नेतृत्व को पता न हो. धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़ने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है. यह बिल्कुल सही है कि राम मंदिर का मुद्दा सांप्रदायिक नहीं है वह राजनीतिक मुद्दा है. जिसका फायदा समय–समय पर राजनीतिक पार्टियों ने उठाया है.

–राजेश पाठक, पालम, नईदिल्ली.

महिला की बहादुरी

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं, इसमें प्रकाशित सभी लेख तथ्यपरक होते हैं. चौथी दुनिया (27 अक्टूबर–02 नवंबर 2014) का अंक पढ़कर काफी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इस अंक को पढ़कर बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त हुई. पृष्ठ 4 प्रकाशित आलेख एक औरत के हाथों मारा गया था ओसामा पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. इस आलेख को पढ़कर पता चलता है कि एक औरत ने किस प्रकार जान पर खेलकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने में अहम भूमिका निभाई. यह भी बिल्कुल सच है कि यदि नेवी सील सिक्स टीम के एक सदस्य मार्क ओवेन पूरी घटना पर लिखे अपने किताब में उस बहादुर महिला का जिक्र नहीं करते, तो शायद ही किसी को यह बात पता चलती कि ओसामा को मारने में अहम भूमिका एक महिला ने निभाई थी.

–वैभव मिश्रा, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

मीडिया की साख से खिलवाड़

जब तोप मुकाबिल हो–मीडिया की साख से मत खेलिए(27 अक्टूबर–02 नवंबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक है. यह बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार सुभाष चंद्रा अपने जी मीडिया और नवीन जिंदल अपने आधिपत्य वाले चैनल फोकस न्यूज के माध्यम से लड़ रहे है, उससे उनका ही नहीं बाकी मीडिया में काम करने वाले लोगों से जनता का भरोसा उठेगा. हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों चैनलों ने एक दूसरे खिलाफ जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया वह बिल्कुल गलत है. वैसे ही मीडिया से लोगों का भरोसा कम हुआ है, अगर ऐसे ही चैनलों के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती रही है, तो मीडिया लोगों का भरोसा टूटेगा. इसलिए चैनलों के माध्यम से युद्ध लड़ने के बजाय वो अपने स्तर पर लड़े.

–अवन्तिका मुखर्जी, जमशेदपुर, झारखंड.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

पुत्रों की परीक्षा

बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था. राजा के तीन पुत्र थे, एक दिन राजा ने अपनो पुत्रों को कुछ शिक्षा देने के लिए अपने पास बुलाया, जिससे वो राज–काज संभाल सकें. राजा ने पुत्रों से कहा, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है, मैं चाहता हूं तुम सब चार–चार महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है? राजा की आज्ञा पा कर तीनो पुत्र बारी–बारी से गए और वापस लौट आये. सभी को राजा ने दरबार में बुलाकर पेड़ के बारे में बताने को कहा.

पहला पुत्र बोला, पिताजी वह पेड़ तो बिलकुल टेढ़ा मेढ़ा, और सूखा हुआ था. दूसरे पुत्र ने पहले बीच में ही रोककर कहने लगा नहीं–नहीं वो तो बिलकुल हरा भरा था, लेकिन किसी कमी के कारण उस पर फल नहीं लगा था. फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आये क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा, वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था. तीनों पुत्र आपस में लड़ने लगे, तब राजा ने बोला पुत्रों, तुम आपस में बहस मत करो. दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो. मैंने जानबूझ कर तुम्हें अलग–अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था. मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम तीन बातों को गांठ बांध लो. पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लम्बे समय तक देखना–परखना चाहिए. दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता, जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा–भरा या फलों से लदा रहता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अत: अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाये रखो, समय अवश्य बदलता है.

और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मान कर उस पर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो, और दूसरों के विचारों को भी जानो. यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते. ■

शिक्षा–ज्ञानी व्यक्ति से शिक्षा लेने में कभी संकोच मत करो.

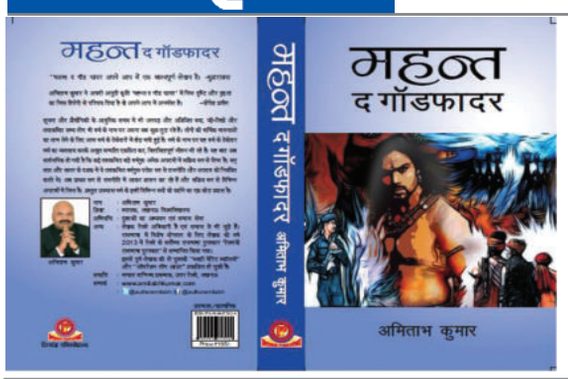

> जहां भारतीय सनातन धर्म इतना सहृदयी है कि एक चींटी की हत्या को भी पाप मानता है, गाय को मां समान मानता है. वहीं यह धर्म इतना कठोर है कि अंत्येष्टि के लिए रखे पार्थिव शरीर को मुखाग्नि तब तक नहीं दे सकते हैं, जब तक कि रोते–बिलखते परिवारीजन सभी औपचारिकताएं पूरी न कर लें. फिर अस्थि विसर्जन, पिंड दान, ब्रह्म भोज, शांति पाठ एवं तेरहवीं आदि.

पुरस्कारों का मौसम

अनंत विजय

दीवाली बीतने के बाद माना जाता है कि त्योहार का मौसम ख़त्म हो गया है, लेकिन यह अजब संयोग है कि दीवाली के बाद हिंदी साहित्य में पुरस्कारों का मौसम शुरू हो जाता है. साहित्य अकादमी समेत कई अहम पुरस्कारों की प्रक्रिया शुरू होती है. साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार के लिए नाम मांगे जा रहे हैं, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के आवेदन की तिथि बस अभी–अभी गुज़री है. इसके अलावा कई पुरस्कार, जो पहले घोषित किए जा चुके हैं, उनके अर्पण समारोह आयोजित होने शुरू होंगे. इस मौसम में धवलकेशी साहित्यकारों से लेकर बिल्कुल टटके लेखकों तक को पुरस्कृत किया जा रहा है. अशोक वाजपेयी से लेकर अर्चना राजहंस तक को पुरस्कृत किया जाएगा. पुरस्कारों के इस मौसम में देश के अलावा विदेशों में भी पुरस्कारों की बरसात हो रही है. स्थापित लेखकों को उनकी किताबें छपवाने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं.

दरअसल, हिंदी में इस वक्त पुरस्कारों की साख पर बड़ा सवालिया निशान है. ऐसे–ऐसे लेखक पुरस्कृत हो रहे हैं, जिनके लेखन से वृहद हिंदी समुदाय अब तक परिचित भी नहीं है. उन्हें निराला से लेकर प्रेमचंद तक के नाम पर स्थापित पुरस्कार दिए जा रहे हैं और उन्हें उनकी परंपरा का बताया जा रहा है. जिस लेखक को उसके मुहल्ले के लोग नहीं जानते, उन्हें मशहूर लेखक कहा जा रहा है. पुरस्कृत लेखकों की प्रशस्ति में शब्दों का भयानक अवमूल्यन देखने को मिल रहा है. कोई विचारक हुआ जा रहा है, तो कोई चिंतक. इन भारी–भरकम विशेषणों के बोझ तले दबे ये हिंदी के पुरस्कार लेखकों के लिए हितकर नहीं हैं. पिछले वर्ष लमही सम्मान को लेकर उठा अनावश्यक विवाद अब भी साहित्य प्रेमियों के ज़ेहन में है. हिंदी में पुरस्कारों की इस दयनीय स्थिति के लिए खुद हिंदी के लेखक और उनकी पुरस्कार पिपासा ज़िम्मेदार हैं. इस वक्त अगर हम देखें, तो एक अनुमान के मुताबिक, हिंदी में कहानी, कविता एवं उपन्यास आदि को मिलाकर तक़रीबन पचास छोटे–बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं. इसके अलावा अनेक राज्य सरकारें भी थोक के भाव से पुरस्कार बांटती हैं. कुछ खुदरा पुरस्कार तो ऐसे हैं, जो बाकायदा लेखकों से एक निश्चित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन मांगते हैं. हिंदी के पुरस्कार पिपासु लेखक बड़ी संख्या में इस तरह के पुरस्कारों के लिए आवेदन करते हैं. यह एक ऐसी स्थिति है, जो पुरस्कार का कारोबार करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर

मुहैया कराती है. हिंदी में ज़्यादातर पुरस्कारों की धनराशि इक्कीस सौ से लेकर इक्यावन सौ रुपये तक है. कइयों में तो सिर्फ़ शॉल–श्रीफल से भी काम चल जाता है. हिंदी में कई पुरस्कारों की आड़ में खेल भी होते हैं, जो साहित्य जगत के लिए शर्मनाक हैं. दरअसल, हिंदी के लेखकों में प्रसिद्ध होने की हड़बड़ाहट पुरस्कारों के इस कारोबार को खाद–पानी मुहैया कराती है.

नई पीढ़ी के लेखकों में एक और प्रवृत्ति रेखांकित की जा सकती है, वह है जल्दबाजी, धैर्य की कमी, कम वक्त में सारा आकाश छेक लेने की तमन्ना और वह भी किसी क़ीमत पर. सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास–मुझे चांद चाहिए की नायिका सिलबिल की तरह. इस प्रवृत्ति को भांपते हुए पुरस्कारों के कारोबारी अपनी बिसात बिछाते हैं. हिंदी में पुरस्कारों की महत्ता एवं प्रतिष्ठा लगातार कम होती जा रही है. हिंदी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य अकादमी सम्मान को माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से जिस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बंदरबांट हुई है, उससे अकादमी पुरस्कारों की साख पर बट्टा लगा है. वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए बनाई गई पुस्तकों की आधार सूची पर नज़र डालने से यह बात और साफ़ हो जाती है. 2003 में जब कमलेश्वर को उनके उपन्यास–कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो उस वक्त की आधार सूची में 31 लेखकों के नाम थे और उस सूची को मृदुला गर्ग ने तैयार किया था.

उस सूची में तेजिंदर, गौरीनाथ, हरि भटनागर, संजना कौल एवं जयनंदन आदि के नाम शामिल थे. तब अकादमी पर यह आरोप लगा था कि कमलेश्वर का नाम पहले से तय था. 2004 में जब वरिष्ठ कवि वीरेन डंगवाल को उनके कविता संग्रह–दुश्चक्र में सृष्टा पर पुरस्कार मिला, तो शक का कोहरा और घना हो गया था. उस वक्त हिंदी के संयोजक थे गिरिराज किशोर और आधार सूची तैयार की थी कहानीकार प्रियंवद ने. हद तो तब हो गई थी, जब निर्णायक मंडल के तीन सदस्यों में से दो यानी कमलेश्वर और श्रीलाल शुक्ल बैठक में उपस्थित ही नहीं हो सके थे. अपनी टिप्पणी में निर्णायक मंडल के तीसरे सदस्य से. आ. यात्री ने लिखा, दुश्चक्र में सृष्टा काव्य कृति को हम सभी निर्णायक मंडल के सदस्य एक समान प्रथम वरीयता देते हैं और साहित्य अकादमी के 2004 के पुरस्कार के लिए सहर्ष प्रस्तुत करते हैं. लेकिन, संस्तुति पत्र पर सिर्फ़ उनके ही दस्तखत थे.

उसी जगह हिंदी भाषा के तत्कालीन संयोजक गिरिराज किशोर ने लिखा, श्री श्रीलाल शुक्ल एवं कमलेश्वर जी उपस्थित नहीं हो सके. उन्होंने अपनी लिखित संस्तुति बंद लिफाफे में भेजी है. श्रीलाल जी ने ज्यूरी के उपस्थित सदस्य से. रा. यात्री से फोन पर लंबी बात करके दुश्चक्र में सृष्टा को 2004 के पुरस्कार के लिए समर्थन दिया. हालांकि, साहित्य अकादमी के दस्तावेजों में श्रीलाल जी की संस्तुति मौजूद नहीं है. कमलेश्वर का 20 दिसंबर का खत है, जो 21 दिसंबर की बैठक के पहले प्राप्त हो गया था. वीरेन डंगवाल की प्रतिष्ठा पर किसी को कोई शक नहीं है. वह साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए डिजर्व भी करते थे, लेकिन जिस अफरातफरी में पुरस्कार का ऐलान किया गया, उससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई थी. कालांतर में अकादमी पुरस्कारों के चयन को लेकर कई गंभीर आरोप लगे. नतीजा यह हुआ कि अकादमी पुरस्कार को लेकर हिंदी जगत में उस तरह का उत्साह नहीं रहा, जो नब्बे के दशक में हुआ करता था. हिंदी में पुरस्कारों के कारोबार या उस पर उठ रहे सवालों पर बड़े लेखकों की चुप्पी साहित्य जगत के लिए अच्छी नहीं है. हिंदी के हित में अच्छा यही होगा कि लेखकगण पुरस्कृत होने की जद्दोजहद में वक्त जाया न करके अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का काम करें.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

पुस्तक समीक्षा

जीवन की सच्चाई समझने का सबक

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय समाज में धर्म की स्थापना और उसकी सेवा के लिए एक वर्ग बनाया गया. यह इसलिए आवश्यक था, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें तैंतीस करोड़ देवी–देवता हैं. देवी–देवताओं की संख्या उन्हें पूजने वालों से अधिक थी. इस वर्ग का कार्य था कि वह धर्म एवं उसके ग्रंथों का अध्ययन कर समाज को शिक्षित करे, जिससे लोग धर्मानुकूल कार्य करें. ये धर्म के सेवक पहले धर्म के रक्षक बने, फिर अनुपालक, फिर दंडाधिकारी. धर्म सेवा पहले जीविका का साधन बनी, फिर शासन का माध्यम और अब अनेक लोगों के लिए यह भोग–विलास का आसान मार्ग है. भारतीय धर्म अब किसी विशेष वर्ग से नियंत्रित नहीं होता है. अब जिसे अवसर मिलता है, वही धर्म का उपयोग अपने निजी हित में कर रहा है.

जहां भारतीय सनातन धर्म इतना सहृदयी है कि एक चींटी की हत्या को भी पाप मानता है, गाय को मां समान मानता है. वहीं यह धर्म इतना कठोर है कि अंत्येष्टि के लिए रखे पार्थिव शरीर को मुखाग्नि तब तक नहीं दे सकते हैं, जब तक कि रोते–बिलखते परिवारीजन सभी औपचारिकताएं पूरी न कर लें. फिर अस्थि विसर्जन, पिंड दान, ब्रह्म भोज, शांति पाठ एवं तेरहवीं आदि. अपने प्रियजन की आत्मा को मोक्ष दिलाने का मूल्य तो देना ही पड़ेगा न! इसका कारण बताया गया, समाज का अशिक्षित होना. आज तो समाज शिक्षित हो रहा है. जैसे–जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है, प्रतीत होता है कि समाज उतना ही अंधविश्वासी होता जा रहा है. छोटे–मोटे वैज्ञानिक तरीकों को ईश्वर का चमत्कार और उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति कहकर पढ़े–लिखे समाज को मूर्ख बनाकर लोग धर्म के नाम पर अपना हित साध रहे हैं. जहां धर्म निर्धन व्यक्ति के लिए इतना कठोर है कि वह अपने परिवारीजन की अंत्येष्टि बिना धन नहीं कर सकता, चाहे उसे कर्जा या सूद पर धन लेना पड़े. कहा जाता है कि अंत्येष्टि के लिए कोई दूसरा धन खर्च नहीं कर सकता. वहीं

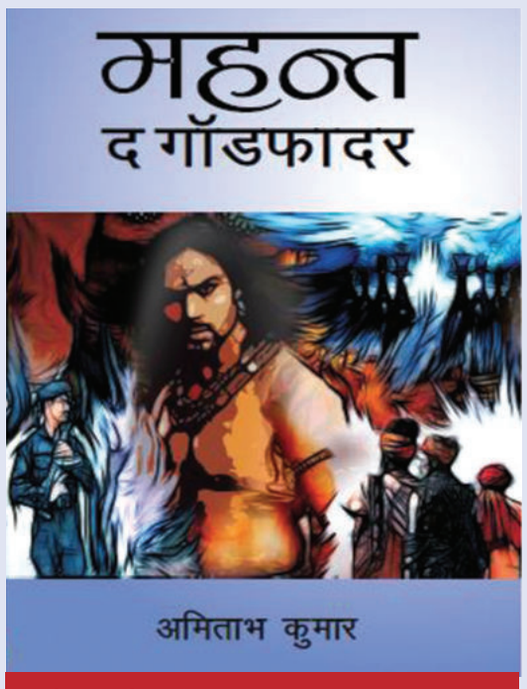

समीक्ष्य कृति: महंत: द गॉड फादर
लेखक: अमिताभ कुमार
मूल्य: 195 रुपये

धनाढ्य यानी समृद्ध लोगों के लिए यह धर्म इतना सहृदयी है कि बड़े–बड़े धर्मस्थलों एवं मठों के कपाट सामान्यजन के लिए बंद करके उन्हें घंटों पूजा–अर्चना की अनुमति देता है.

आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक समय में भी अनपढ़–अशिक्षित, क्या पढ़े–लिखे और तथाकथित सभ्य लोग भी धर्म के नाम पर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं. लोगों की धार्मिक भावनाओं का लाभ लेने के लिए आज धर्म के ठेकेदारों में होड़ मची हुई है. धर्म के नाम पर वे धर्म का व्यवसाय करके अकूत संपत्ति एकत्र कर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं. यह बात अब सार्वजनिक हो गई है कि कई तथाकथित बड़े धर्मगुरु अनेक अपराधों में सक्रिय रूप से लिप्त हैं. वे धर्म की आड़ में सभी तरह के अधर्म कर रहे हैं. सन् साठ एवं सत्तर के दशक में ये तथाकथित धर्मगुरु परोक्ष रूप से राजनीति और अपराध को नियंत्रित करते थे. अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आकर शासन कर रहे हैं और विभिन्न अपराधों में लिप्त हैं. अपनी इस पुस्तक में लेखक ने राजनीति के अपराधीकरण को देश–समाज के लिए ख़तरनाक बताया है. लेखक ने निज दृष्टि एवं दृढ़ता का दिलेरी से परिचय देकर सिद्ध कर दिया है कि उसका छात्रनेता अभी जिंदा है. महंत: द गॉड फादर में लेखक ने जीवन सहेजने, सच्चाई से अवगत होकर जीवन जीने की कला सहजता से परोसी है. लेखक अमिताभ कुमार रेलवे में सहायक परिचालन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 2013 में रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार रेल मंत्री राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ■

कविता

– महेंद्र अवधेश

बरसात

जब आती है बरसात तो
आनंदित हो उठता है संसार,
ऊंची अट्टालिकाओं पर
जब पड़ती हैं फुहारें तो
नाच उठता है मन का मयूर,
थिरकते हैं पैर
सात समंदर पार से
आयातित धुनों पर,
लेकिन–सिहर उठता है
बिरजुवा का जियरा
अपनी झोंपड़ी के अस्तित्व के प्रति,
जिसमें छिपा रखी है उसने
अपने जीवन की थाती
एक अदद मैला कंबल
एक लोटा और टाठी.

*टाठी (थाली)

शिवाशंकर को पत्रकारिता गौरव सम्मान

इलाहाबाद. पत्रकार शिवाशंकर पांडेय को बायोवेद मर्यादा पुरुषोत्तम पत्रकारिता गौरव सम्मान के लिए चुना गया है. पिछले 25 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े पांडेय दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे अख़बारों में रिपोर्टिंग एवं डेस्क पर ज़िम्मेदारी संभाल चुके हैं. स्वतंत्र चेतना, जनमोर्चा एवं प्रयागराज टाइम्स में पथिक की डायरी, दैनिक जागरण में गांव की ओर, सामर्थ्य पत्रिका में मीडियावाच आदि उनके स्तंभ खासे चर्चित रहे हैं. कथादेश, वागर्थ एवं जनसत्ता में पांडेय की कई कहानियों और उपन्यास का प्रकाशन हो चुका है. समय–समय पर राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर उनके आलेख विभिन्न अख़बारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं. ■

के–10 कार को 200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है. इसमें भारत तथा जापान दोनों देशों के इंजीनियरों ने हाथ बंटाया है. ऑटो शिफ्ट गियर होने के कारण यह कार बढ़िया माइलेज देगी और इसकी कीमत भी बजट के अनुकूल होगी.

रेटिना डिस्प्ले के साथ नया एप्पल आईमैक

एप्पल ने अपने आईमैक डेस्कटॉप कंप्यूटर का नया वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने आईमैक को 27 इंच रेटिना 5के डिस्प्ले के साथ बाजार में उतारा है, जिसका रेजोल्यूशन 5120 गुणा 2880 पिक्सल है. डिजायन के मामले में यह अब तक का सबसे सुन्दर आईमैक है. कंपनी ने इसे 3.5 गीगाहर्ट्स आई–7 प्रोसेसर से लैस किया है इस वजह से यह पहले वाले आईमैक से ज्यादा तेज है. इसक अलावा इसमें फुशन ड्राइव और थंडरबोल्ड 2 दिया गया है. एप्पल ने नए आईमैक के डिस्प्ले में 8 जीबी मेमोरी तथा 1 टेराबाइट फुशन ड्राइव दिया है. इसके अलावा इसमें अतिरिक्त 32 जीबी मेमोरी, 3 टेराबाइट फुशन ड्राइव अथवा 1 टेराबाइट पीसीआई आधारित एसएसडी स्टोरेज से लैस किया जा सकता है. एप्पल ने इसके अलावा योसमाइट ओएस 10.10 भी उतारा है. इसकी सबसे खास बात यह है इसके तहत आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैक एयरबुक तीनों को आपस में जोड़ा जा सकता है. एप्पल आईमैक की कीमत लगभग 1.53 लाख रुपये रखी गई है. ■

पानी में तस्वीर खींचने वाला कैमरा

एचटीसी ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च किया है, जो पानी अंदर की भी शानदार तस्वीरें खीच सकता है. इसमें सबसे खास बात ये है पानी में उतरकर तस्वीरें खींचने पर भी इसमें कैमरे कोई खराबी नहीं आथी है. कंपनी ने इस कैमरे को आरई नाम दिया है. एचटीसी आरई एक एक्शन कैमरा है जिसमें और भी कई सारे से फीचर्स दिए गए हैं जो इसें शानदार कैमरा बनाते हैं. मेमोरी के तौर पर इसमें माइक्रोएसडी कार्ड लगता है, जिसमें खींची गई तस्वीरें सेव होती है. एचटीसी आरई कैमरा साइज में बहुत छोटा है और दिखने में यह अस्थमा इन्हेलर पाइप की तरह लगता है. इसमें 16 मेगापिक्सल का लैंस लगा है, जो 146 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ है. इसकी स्टोरेज क्षमता 128 जीबी है. इसकी बैटरी 820 एमएएच की है और इसकी बॉडी वाटरप्रूफ है. ■

यामाहा के सेफ और सुंदर हेलमेट

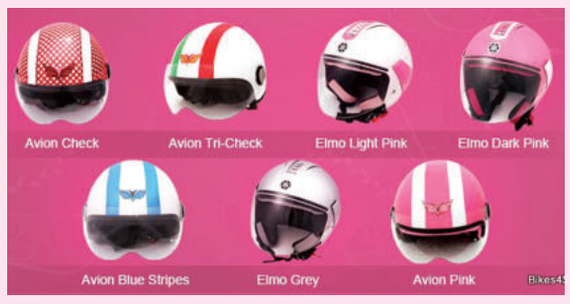

टूव्हीलर निर्माता कंपनी यामाहा ने बहुत ही खूबसूरत और सेफ्टी फीचर्स से लैस हेलमेट लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इन्हें विशेषतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए पेश किया है. सभी हेलमेट्स की कीमत 990 रुपये से 1380 रुपये के बीच है. यामाहा ने महिलाओं के लिए एलमो, एविओन और केस्मो सरीज में 12 कलर के हेलमेट उतारे हैं जबकि बच्चों के हेलमेट को ब्लैकस्टार, ब्लूकिंग और व्हाइटनाइट रेंज में उतारा है. यामाहा के इन हेलमेट्स की सबसे खास बात ये है आईएसआई सर्टिफाइड है. इसके अलावा बहुत सारे रंगों में उपलब्ध है, जिससे लोग देखर आकर्षित होंगे. वहीं बच्चों के हेलमेट्स पर कार्टून और केरेक्टर्स दिए गए हैं जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

एक किलो सीएनजी में 32 किलोमीटर

मारुति सुजुकी अपनी छोटी और सफल कार ऑल्टो का नया संस्करण लॉन्च करने जा रही है. इस कार की खासियत इसका माइलेज और इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होगा. ऑल्टो के–10 आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लैस होगी. कंपनी का कहना है कि यह कार बड़े पैमाने पर बेचे जाने के लिए होगी और उन ग्राहकों के लिए बनाई जाएगी जोवैल्यू फॉर मनी चाहते हैं. इस कार को 200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है. इसमें भारत तथा जापान दोनों देशों के इंजीनियरों ने हाथ बंटाया है. ऑटो शिफ्ट गियर होने के कारण यह कार बढ़िया माइलेज देगी और इसकी कीमत भी बजट के अनुकूल होगी. उन्होंने बताया कि इस कार का पेट्रोल संस्करण 24.07 किलोमीटर प्रति लीटर का मआलेज देगा जबकि सीएनजी संस्करण 32 किलोमीटर का. इस कार के छह वैरियंट होंगे, लेकिन ऑटोमेटिक गियर सिर्फ टॉप मॉडल में होगा. इसकी कीमत 3.15 लाख रुपये से लेकर 3.31 लाख रुपये के बीच होगी. ■

आईबॉल का एंडी उड़ान मिनी

आईबॉल ने एंडी उड़ान नाम से एक डुअल सिम स्मार्टफोन लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया पहला स्मार्टफोन है. इसमें एसओएस, आईसीई और ट्रैकिंग सेफ्टी जैसे फीचर्स हैं. आईबॉल ने एंडी उड़ान का मिनी वर्जन लॉन्च किया है. इसकी कीमत 5,699 रुपये तय की गई है. इसमें एक खास एसओएस बटन है, जिसे इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. इस बटन को दबाते ही चुनिंदा नंबरों पर अलर्ट चला जाएगा. दूसरी ओर आईसीई एप्लिकेशन में महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहते हैं. इनमें यूजर की मेडिकल हिस्ट्री, इमरजेंसी नंबर और ब्लड ग्रुप शामिल हैं. आईसीई का मतलब है इन केस ऑफ इमरजेंसी. यह आसान सा एप्लिकेशन है, जिसे कोई भी खोल सकता है. इस मोबाइल में एक और ऐप है, जिसे ट्रैकिंग का नाम दिया गया है. यह यूजर के किसी शहर में आने या जाने को भी ट्रैक करता है. यानी यूजर कब कहां से आया और गया. इसकी यह जानकारी मिलेगी. इसमें अन्य फीचर्स 1 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर, 512 एमबी रैम और 4.4 जेलीबीन एंड्रॉयड ओएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ■

बैटरी सेव करने वाला ऐप

लेटेस्ट स्मार्टफोन अपने फीचर्स और हाई–डेफिनेशन डिस्प्ले होते हैं, जिसके कारण फोन की बैटरी जल्द खत्म हो जाती है. शॉर्प डिस्प्ले और भारी ऐप्स की वजह से स्मार्टफोन की बैटरी प्रॉब्लम से जूझना आम बात है. जल्द फोन डिस्चार्ज होने के कारण आम तौर पर लोगों को परेशानी का सामना कराना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए गूगल प्ले पर कुछ ऐप्स भी मौजूद हैं. इनमें से एक है डीयू बैटरी सेवर. इस ऐप को प्ले स्टोर से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुकेहैं. इस ऐप की कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स डिवाइस के हिसाब से बदल जाती हैं. डीयू बैटरी सेवर ऐसा ऐप है, जिससे यूजर्स अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस की बैटरी को बेहतर बनाने के साथ उसे बढ़ा भी सकते हैं. इस ऐप से यूजर्स प्री–सेट मोड्स और वन टच कंट्रोल से बैटरी की समस्या को हल कर सकते हैं. वहीं बैटरी स्टेटस, हेल्थ, तापमान और अन्य चीजों को चेक किया जा सकता है. इस ऐप से बिना काम के ऐप बंद हो जाएंगे. इसी ऐप से 50 फीसदी बैटरी की लाइफ बढ़ाई जा सकती है. इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनडोल किया जा सकता है. ■

स्पाइस का दमदार स्मार्टफोन

कंपनियों में स्मार्टफोन लॉन्च करने की होड़ सी मची हुई है. इसी कड़ी में स्पाइस ने एक नया स्मार्टफोन स्पाइस स्टेलर–518 लॉन्च किया है, जिसकी बैटरी दमदार है. यह फोन 1.3 जीएचजेड क्वॉड कोर प्रोसेसर से लैस है. स्पाइस स्टेलर की स्क्रीन आईपीएस एलसीडी है, जिसका रेजोल्यूशन 854 गुणा480 पिक्सल है. इसकी रैम 1 जीबी है और इसमें 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. इसमें माइक्रो एसडी कार्ड की व्यवस्था है. यह एड्रॉयड किटकैट पर आधारित है. इसमें दो कैमरे हैं. इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जबकि फ्रंट 1.3 एमपी का है. यह डुअल सिम है और दोनों ही 3जी सपोर्ट है. इसमें अन्य सुविधाएं 2 जी, वाई–फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस भी है. इसका मुख्य आकर्षण इसकी बैटरी है, जो 4,000 एमएएच की है और यह सामान्य स्मार्टफोन से दोगुना टॉक टाइम देता है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

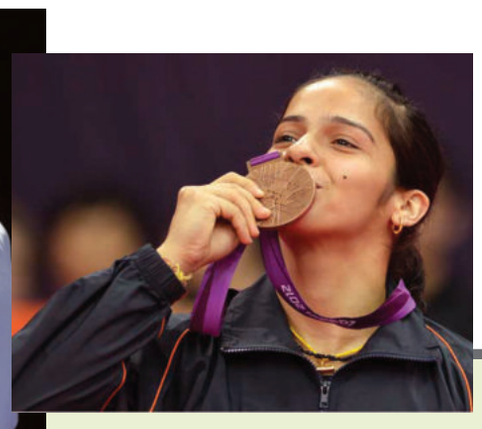

सरकार की पहल इसलिए बेहतर है क्योंकि वह एक लक्ष्य निर्धारित करके खिलाड़ियों के पूल पर काम कर रही है. बावजूद इसके यदि खिलाड़ी पदक जीतने में नाकाम रहते हैं तो इसकी समीक्षा करनी होगी और इस योजना के दायरे को बढ़ाना होगा. साथ ही खेल और खिलाड़ियों को लालफीताशाही के चंगुल से भी आजाद करना होगा जिससे कि कम से कम समय में वरीयता के आधार पर खिलाड़ियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकें.

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम

खेलों के अच्छे दिन आने वाले हैं?

भारत ओलंपिक खेलों में अब तक केवल 26 मेडल जीत सका है. जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं. 9 स्वर्ण पदकों में से आठ हॉकी में और एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जीता है. अब केंद्र सरकार पदकों की संख्या में इज़ाफे को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रही है. सरकार ने ओलंपिक और अन्य खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के ज्यादा पदक जीत सकने के लक्ष्य के साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लागू की है. क्या इस योजना से खेल और खिलाड़ियों का कोई फायदा होने वाला है...

नवीन चौहान

जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वह लगातार देश के लिए पदक या अन्य प्रतियोगिताएं जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं और उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं. इस वजह से देश के खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है. हाल ही में सिंगापुर में डब्ल्यूटीए महिला युगल का खिताब जीतने के बाद सानिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों की हौसला-अफज़ाई करने को शानदार बताया. सानिया ने कहा कि जब भी मैं जीतती हूं, वह मुझे काफी प्रोत्साहन देते हैं. यह बेहद रोमांचक हैं. मेरे खयाल से एक प्रधानमंत्री के लिए किसी खलाड़ी की उपलब्धि पर ध्यान देना और उसे प्रोत्साहित करना बहुत ही शानदार बात है. सानिया मोदी से बधाई पाने वाली अकेली भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं. मोदी देश के हर खिलाड़ी के खेल पर नज़र रखते हैं और उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई देने से नहीं चूकते हैं.

ऐसा भी नहीं है कि मोदी केवल खिलाड़ियों को सोशल नेटवर्किंस साइट्स पर केवल बधाई देने तक ही सीमित हैं. भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन में सुधार करने और उनका सहयोग करने के उद्देश्य से उनकी सराकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) शुरू की है. इस योजना में खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पूर्व खिलाड़ियों और लंबे समय से खेल प्रशासन से जुड़े लोगों को दी गई है. इस योजना को लागू करने के लिए आठ सदस्यीय पैनल का भी गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर को बनाया गया है. उनके अलावा पैनल में भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, पांच बार की विश्वचैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज़ एमसी मेरीकॉम, ऑल इंग्लैंड ओलंपिक चैंपियन पुलेला गोपीचंद, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. यह योजना साल 2020 तक आयोजित होने वाले सभी महत्वपूर्ण खेल आयोजनों तक लागू रहेगी. इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 और 2020 ओलंपिक के लिए देश भर के संभावित पदक विजेताओं की पहचान की जाएगी. टॉप्स को नेशनल स्पोर्टस डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत रखा गया है. आठ सदस्यीय पैनल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि देश भर के विभिन्न खेलों के उदयीमान और प्रतिभाशाली खिलाड़ी चिन्हित हों और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिले. उनकी सफलता के लिए आवश्यक हर जरूरत का ख्याल रखा जाए और मुहैया कराई जाए जिससे कि वह सारा ध्यान अपने प्रदर्शन पर केंद्रित कर सकें. इस योजना को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जाये? किस तरह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए? जिससे कि आने वाले समय में पदकों की संख्या में इज़ाफा हो सके?

टॉप्स के अंतर्गत आठ सदस्यीय पैनल विभिन्न खेलों के 75 से 100 खिलाड़ियों के पूल का चयन करेगा. खिलाड़ियों के चयन के लिए कमेटी के पास दो महीने का वक्त है. चयनित खिलाड़ियों को अगले दो ओलंपिक खेलों में 25 से 30 मेडल जीतने के लक्ष्य के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और निशानेबाजी के साथ-साथ उन खेलों पर भी होगा जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं. खिलाड़ियों के चयन के लिए खेल प्राधिकरणों और खिलाड़ियों से आवेदन मांगे जाएंगे. इसके बाद शार्टलिस्टेड खिलाड़ियों के आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरणों और प्रशिक्षकों के साथ करीब से काम करेगा. युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करके सेंट्रलाइज्ड लांग टर्म प्रोग्राम के अंतर्गत नव श्रृजित विशिष्ट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस योजना में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. नियमित तौर पर खिलाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके सहयोग के लिए विस्तृत सहयोगी ढांचे का भी निर्माण किया जाएगा. हर साल चुने गए खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा करके नए खिलाड़ियों को इस पूल में जोड़ा जाएगा और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे खिलाड़ियों और खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा.

खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरणों के बीच हमेशा से समन्वय की कमी देखी गई है. इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरणों के बीच के कम्युनिकेशन गैप को कम करना होगा. ऐसा करना देश में खेलों के विकास के हित में होगा. इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए खेल प्रधिकरणों, सरकारों और विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है. जिससे कि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. जिससे खिलाड़ी केवल अपने प्रदर्शन और खेल पर ध्यान दें न कि ग़ैरजरूरी गतिविधियों पर.

खिलाड़ियों के चयन और बेहतर प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई इस योजना की प्रशंसा हो रही है. सभी का मानना है कि इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निश्चित तौर पर सुधार आएगा और वे देश के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पदक जीतने में सफल होंगे. पैनल में शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि क्रिकेट के अलावा देश में दूसरे खेलों में सुधार आ रहा है. हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पदक मिल रहे हैं. इसलिए यह एक अच्छी पहल है. यह देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की मदद के लिए है. ऐसा ही दुनिया के और देशों में भी हुआ है. एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है. द्रविड ने सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय खेल सही दिशा में जा रहे हैं. सरकार की यह पहल न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि भविष्य में होने वाले ओलंपिक और अन्य स्पर्धाओं में पदकों की संख्या बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के कारण मुझे इस बात का अंदाजा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए एक एथलीट को किन चीजों की आवश्यक्ता होती है. मुझे नहीं मालूम है कि मुझे एक नॉन ओलंपियन होने के बावजूद मुझे इस पैनल में क्यों चुना गया है लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे इसी तरह के सुझाव मांगे जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि खेल-खेल होता है और शीर्ष स्तर का प्रदर्शन शीर्ष स्तर का ही होता है. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्रिकेट अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से सीख सकता है. काफी ज्ञान साझा होता है. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अन्य खेल क्रिकेट से भी सीख सकते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी अन्य खेलों से. पैनल की दूसरी सदस्य और ओलंपियन एम सी मेरीकॉम ने कहा कि इस कमेटी की सदस्य होने के नाते वह खिलाड़ियों के लिए अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण में सहयोग करेंगी जिससे कि खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिल सके. राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद भी सरकार के देश में खेलों और खिलाड़ियों के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास से खुश हैं. पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि सरकार खिलाड़ियों के ऊपर खर्च कर रही है. भारतीय खेल प्राधिकरण(साई) ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में बहुत पैसे खर्च किए हैं, यह कार्यक्रम उसी कड़ी में एक विस्तार है. जिससे कि खिलाड़ियों को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि अन्य सुविधाएं भी जल्दी मुहैया हो जाएंगी. इससे उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसे भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा और कठिन है, इसलिए हमें इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है. कई बार पैसों के अलावा भी कई चीजों की आवश्यकता होती है इसलिए उन्हें चिन्हित करना और उन्हें यह बताना बहुत जरुरी होता है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ि्यों में से एक हैं हम अच्छे परिणामों के लिए सरकार आपकी हर संभव मदद करेंगी.

राहुल द्रविड़ का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि क्रिकेट के अलावा देश में दूसरे खेलों में सुधार आ रहा है. हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पदक मिल रहे हैं. इसलिए यह एक अच्छी पहल है. यह देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की मदद के लिए है. ऐसा ही दुनिया के और देशों में भी हुआ है. एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है. द्रविड ने सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय खेल सही दिशा में जा रहे हैं. सरकार की यह पहल न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि भविष्य में होने वाले ओलंपिक और अन्य स्पर्धाओं में पदकों की संख्या बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी.

सरकार की पहल इसलिए बेहतर है क्योंकि वह एक लक्ष्य निर्धारित करके खिलाड़ियों के पूल पर काम कर रही है. बावजूद इसके यदि खिलाड़ी पदक जीतने में नाकाम रहते हैं तो इसकी समीक्षा करनी होगी और इस योजना के दायरे को बढ़ाना होगा. साथ ही खेल और खिलाड़ियों को लालफीताशाही के चंगुल से भी आजाद करना होगा जिससे कि कम से कम समय में वरीयता के आधार पर खिलाड़ियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकें. लेकिन सरकार को इस बात का भी ख्याल भी रखना होगी कि बुधिया सिंह जैसे खिलाड़ी की भी सही समय पर पहचान की जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि देश में भविष्य के खिलाड़ियों का एक बड़ा पूल जूनियर और सब जूनियर स्तर पर तैयार हो सके. ऐसा करने से सरकार के पास खिलाड़ियों के व्यापक प्रोफाइल उपलब्ध होंगे और सरकार खिलाड़ियों के ऊपर समय रहते प्रभावशाली ढंग से काम कर सकेगी. नहीं तो जिस तरह बुधिया सिंह साल 2007 के बाद से गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है, यही हाल अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का भी हो जाएगा. फिलहाल सरकार की नीयत तो साफ दिख रही है. 2016 के ओलंपिक के परिणामों से ही इस योजना के दूरगामी प्रभावों का अंदाजा हो जाएगा. फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी देश के हर इलाके में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे तो खेल राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्र सरकार को अपनी ओर से इसके लिए प्रभावकारी पहल करनी चाहिए. साथ ही ग्रामीण स्तर पर टैलेंट सर्च कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिससे कि ग्रामीण स्तर की खेल प्रतिभाएं सबके सामने आ सकें. नहीं तो यह योजना भी शहर केंद्रित हो जाएगी और ग्रामीण प्रतिभाएं की दबी रह जाएंगी. देश में सरकार कोई भी हो लेकिन इस तरह की योजनाओं के प्रभावी रूप से लागू होने पर ही खेल और खिलाड़ियों के लिए हर दिन अच्छे दिन हो पायेंगे और विश्व में देश का सिर गर्व से ऊंचा हो पाएगा. ■

navinonline2003@gmail.com

ब्रैडमैन हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए सचिन

पिछले साल नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ करियर का 200 वां टेस्ट मैच खेलकर संन्यास लेने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. उन्हें ब्रैडमैन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्तान स्टीव वॉ को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है. ब्रैडमैन फाउंडेशन के वार्षिक भोज में तेंदुलकर की उपस्थिति काफी महत्व रखती है, क्योंकि सर डॉन ब्रैडमैन ने एक बार अपनी पत्नी से कहा था कि सचिन की तकनीकि उन्हें खुद की याद दिलाती है. सचिन ब्रैडमैन से उनके 90 वें जन्मदिन पर मिले थे, इसके बाद उन्होंने अपनी सर्वकालिक एकादश में सचिन को शामिल किया था. ■

2018 फीफा विश्वकप का लोगो जारी

फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लाटर ने साल 2018 में रूस में होने वाले विश्वकप को लोगो लॉन्च कर दिया है. लोगो लॉन्च करते समय ब्लाटर ने कहा कि यह लोगो रूस के जज्बे को दिखाता है. लोगो में विश्वकप ट्रॉफी को लाल और नीले रंग में दिखाया गया है जो रूस के झंडे का रंग भी है इसके साथ ही ट्रॉफी के चारों ओर सुनहरे रंग को जगह दी गई है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ब्रैड पिट को अभिनेता से ज्यादा पिता होने पर गर्व

हॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता ब्रैड पिट पिता बनने पर गर्व महसूस करते हैं. उन्हें एक सफल अभिनेता होने से ज्यादा छह बच्चों का अभिभावक होने पर गर्व है. डिटेल्स मैगजीन को दिए गये एक साक्षात्कार में 50 वर्षीय अभिनेता ने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बातें की. उन्होंने यह भी कहा कि अभिनय की दुनिया में वह जैसे-जैसे ऊंचाई पर पहुंचते गए, वह अपनी आजादी गंवाते गए. ब्रैड पिट ने कहा कि वह अपनी बाइक की सवारी करते समय या विदेशों में यात्रा के दौरान कैमरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि आजादी की परिभाषा यह है कि आप बिना किसी की निगरानी के अपना जीवन बिंदास तरीके से जियें. बहरहाल, पिट को इस बात की खुशी ज्यादा है कि वह अपनी पत्नी एंजेलिना के साथ मिल कर छह बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि,अभिभावक की भूमिका अभिनेता की तुलना में कहीं ज्यादा गर्व का अहसास कराती है. ब्रैड और एंजलीना पिछले कई सालों से साथ में रह रहे थे. कुछ समय पहले ही दोनों ने शादी की है.■

रिकॉर्ड तोड़ ख़ान

शाहरुख ख़ान की 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह 5 वीं फिल्म है. इससे पहले शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस, रॉ -वन, जब तक है जान, डॉन-2 आदि फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी हैं.

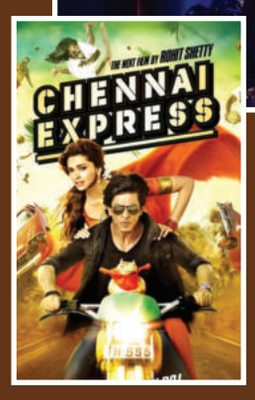

फराह खान निर्देशित शाहरुख-दीपिका स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने रिलीज के पहले दिन ही धांसू कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. फिल्म पहले दिन 45 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड कमाई कर अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई. पहले दिन 45 करोड़ कमाई कर यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है इससे पहले यह रिकॉर्ड आमिर ख़ान की धूम-3 के नाम दर्ज था. धूम-3 ने रिलीज के पहले दिन 36 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. बात यहीं नहीं रुकी, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में सबसे आगे रही. दिवाली के मौके पर 24 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म के लिए छुट्टियां बेहद फायदेमंद रहीं. इसके साथ ही इस फिल्म ने सबसे तेज 100 करोड़ रुपये की कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. आज कल शाहरुख बॉलीवुड के दूसरे ख़ानों आमिर व सलमान को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं. वह रिकॉर्ड तोड़ ख़ान बन गए हैं. हैप्पी न्यू ईयर ने महज़ ढाई दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर पहले वीकेंड में 109 करोड़ का कलेक्शन किया. इससे पहले आमिर की धूम-3 पहले 3 दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी. शाहरुख ख़ान की 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह यह 5 वीं फिल्म है. इससे पहले शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस, रॉ वन, जब तक है जान, डॉन-2 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी हैं. शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण की भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह 5वीं फिल्म है. इससे पहले दीपिका की रेस-2, ये जवानी है दीवानी, राम-लीला और चेन्नई एक्सप्रेस इस क्लब में शामिल हो चुकी हैं.■

आवारा की रीमेक नहीं बनाएंगेः रणधीर

जानेमाने अभिनेता एवं फिल्मकार रणधीर कपूर पिता राजकपूर के बैनर तले बनी फिल्म आवारा का रीमेक नहीं बनाना चाहते हैं. उनका कहना है कि आज के दौर का कोई कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राजकपूर के किरदार को कोई नहीं निभा सकता है इसलिए वे इसे दोहराना नहीं चाहते. आवारा उस दौर की सफलतम फिल्मों में से एक थी. पहले रणधीर के दिमाग में आया था कि आवारा की रीमेक बनायें, लेकिन अब उन्होंने इस इरादे को छोड़ दिया. रणधीर ने बताया कि लोग कहते हैं कि मैं रणबीर और ऋषि कपूर को लेकर इस फिल्म की रीमेक बनाउं. इस फैसले पर हम आगे बढ़े, फिर ठहर गए और डर भी गए. हमारे डरने की वजह यह थी कि हम दुबारा पृथ्वीराज कपूर और राजकपूर साहब को कहां से लाएंगे. हमें शंकर जयकिशन जैसी संगीतकार की जोड़ी कहां से मिलेगी, कहां से शैलेंद्र जैसा गीतकार मिलेगा. इसके बाद हमने रीमेक बनाने का आइडिया ड्राप कर दिया. आर.के. बैनर तले बनी आखिरी फिल्म 1999 में रिलीज हुई फिल्म आ अब लौट चलें थी. इस फिल्म में ऐश्वर्या रॉय, अक्षय खन्ना और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने खासा पसंद किया था. यह एक पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म थी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

गोविंदा बॉलीवुड के सबसे उम्दा कलाकार : सैफ

बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान का कहना है कि गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उम्दा कलाकार हैं. सैफ ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले हैप्पी एंडिंग नामक फिल्म बनाई है. इस फिल्म में सैफ मुख्य भूमिका में हैं उनके साथ गोविंदा भी नज़र आएंगे. सैफ का कहना है कि गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उम्दा कलाकार हैं क्योंकि गोविंदा बहुत ही शानदार डांसर और अभिनेता हैं. मैं उनके काम का सम्मान करता हूं. उन्हें डांस करते देखना तो आश्चर्यचकित कर डालता है. मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं. खास तौर पर जब वह डांस करते हैं तो मैं खुद को बच्चा की तरह बहुत रोमांचित महसूस करता हूं. वह असली सितारे हैं और उनके साथ डांस करके मैं बहुत खुश हूं. राज निदिमोरू और कृष्णा डीके के निर्देशन मे बनी फिल्म हैप्पी एंडिंग में सैफ और गोविन्दा के अलावा इलियाना डिक्रूज, रणवीर शौरी और कल्की कोचलीन ने काम किया है. इस फिल्म में करीना कपूर और प्रीति जिंटा ने कैमियो किया है. यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.■

फिल्म निर्माण में जुटीं अनुष्का

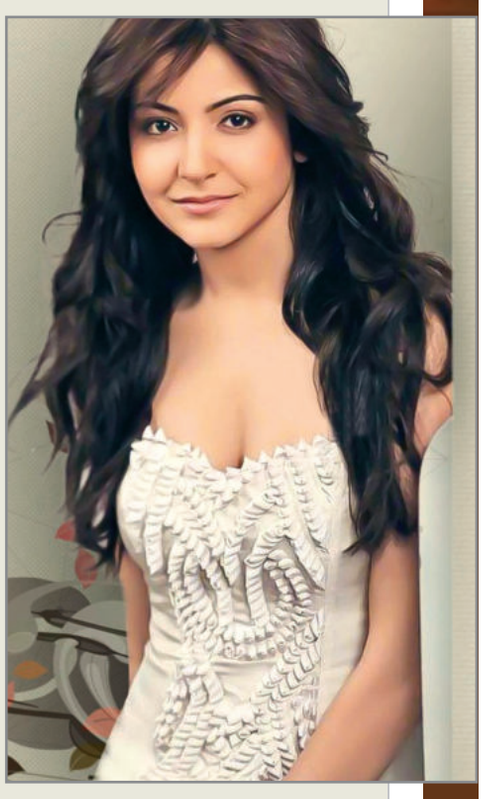

बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री और हाल ही में निर्माता बनी अनुष्का शर्मा अब दूसरी फिल्म भी बनाने जा रही हैं. अनुष्का इन दिनों फिल्म एनए-10 बना रही हैं. अपनी फिल्म में अनुष्का अभिनय भी कर रही हैं. अनुष्का ने अपनी दूसरी प्रोडक्शन फिल्म का भी एलान कर दिया है. इस फिल्म का निर्देशन नवदीप सिंह करेंगे जो पहले से एनएच 10 का निर्देशन कर रहे हैं. चर्चा इस बात की भी है कि इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट एनएच-10 के स्क्रिप्ट राइटर सुदीप शर्मा लिखेंगे. हालांकि फिल्म की कहानी और कास्ट के बारे में तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म में अनुष्का अभिनय भी कर सकती हैं.■

हैदर को पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड

विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म हैदर को नौवें रोम फिल्म महोत्सव में पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड दिया गया है. यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट पर आधारित है. कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, तब्बू, इरफ़ान खान और केके मेनन ने मुख्य किरदार निभाए हैं. विशाल के साथ महोत्सव में शामिल हुए शाहिद ने ट्विटर पर यह जानकारी दी. शाहिद कपूर ने ट्विटर पर अपनी और विशाल भारद्वाज की एक तस्वीर के साथ लिखा, पहला महोत्सव, पहली जीत. शानदार.. वाह. रोम फिल्म महोत्सव की मुख्य श्रेणी में पीपुल्स चाइस अवॉर्ड. रोम फिल्म महोत्सव में हैदर के रूप में किसी भारतीय फिल्म को मिला यह पहला पुरस्कार है. मुझे गर्व है. श्रद्धा कपूर महोत्सव का हिस्सा नहीं बन पाईं लेकिन उन्होंने भी ट्विटर पर अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की. श्रद्धा ने ट्विटर पर लिखा, हमें जीत मिली. हैदर - रोम फिल्म महोत्सव की मुख्य श्रेणी में पीपुल्स चाइस अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी. आभारी और गौरवान्वित हूं. विशाल भारद्वाज इससे पहले शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित मक़बूल और ओंकारा बना चुके हैं.■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 नवंबर–16 नवंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

फिर यात्रा, फिर वादे

नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर इन कार्यकर्ताओं का सत्यापन भी यात्रा के दौरान कर सकते हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि बहुत सारे ऐसे बूथ भी थे जहां जदयू का कोई पोलिंग एजेंट ही नहीं था जबकि भाजपा ने इसका बेहतर मैनेजमेंट किया था. यही वजह है कि इस बार नीतीश कुमार इस लाइन पर खुद होमवर्क कर रहे हैं और यात्रा के दौरान इसे अमली जाम पहनाने की कोशिश करेंगे. जदयू के सूत्र बताते हैं कि बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं का मोबाइल नंबर और इसका पता पटना कार्यालय में उपलब्ध रहेगा और समय-समय पर उनसे फीड बैक लेने का काम प्रमुखता से किया जाएगा. गौरतलब है कि हर बार यह कह तो दिया जाता है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया गया है पर जब वक्त आता है तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है.

सरोज सिंह

नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं. हर बार की तरह उनकी यह यात्रा शुरू तो चंपारण से ही हो रही है पर इस बार इसमें बहुत कुछ अलग भी है. 13 नंवबर से शुरू हो रही इस संपर्क यात्रा में नीतीश कुमार इस दफे जनता से सीधा संपर्क नहीं करेंगे. मतलब कोई जनसभा नहीं होगी केवल और केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका सामना होगा. लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने अपने पटना आवास में इस संपर्क यात्रा का ठोस होमवर्क किया है. वह लगभग सभी जिलों के खास नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं और उनके साथ इस यात्रा का खाका खींच चुके हैं. नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को बस यही समझा रहे हैं कि भाजपा ही चुनौती है और बिना भ्रम में फंसे इसका डट कर मुकाबला करना है. इस मुकाबले के लिए बूथ लेबल मैनेजमेंट पर खासा जोर दिया जा रहा है. नीतीश कुमार चाहते हैं कि वह जहां भी संपर्क यात्रा पर जाएं वहां के हर बूथ के कम से कम पांच समर्पित कार्यकर्ता जरूर आएं. बूथ पर यूथ की ताकत को नीतीश कुमार समझ चुके हैं इसलिए इस बार कोई गलती वह करना नहीं चाहते. जिलास्तर पर हर नेता को समझा दिया गया है कि बूथ स्तर की तैयारियों में किसी भी कीमत पर कमी न रह जाए.

नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर इन कार्यकर्ताओं का सत्यापन भी यात्रा के दौरान कर सकते हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि बहुत सारे ऐसे बूथ भी थे जहां जदयू का कोई पोलिंग एजेंट ही नहीं था जबकि भाजपा ने इसका बेहतर मैनेजमेंट किया था. यही वजह है कि इस बार नीतीश कुमार इस लाइन पर खुद होमवर्क कर रहे हैं और यात्रा के दौरान इसे अमली जाम पहनाने की कोशिश करेंगे. जदयू के सूत्र बताते हैं कि बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं का मोबाइल नंबर और इसका पता पटना कार्यालय में उपलब्ध रहेगा और समय-समय पर उनसे फीड बैक लेने का काम प्रमुखता से किया जाएगा. गौरतलब है कि हर बार यह कह तो दिया जाता है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया गया है पर जब वक्त आता है तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है. ऐसी नौबत दोबारा न आए इसके लिए ही इस बार फूंक-फूंक कर कदम रखा जा रहा है. 29 नवंबर तक चलने वाली संपर्क यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के गुस्से को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे. यह आम शिकायत रही है कि सत्ता में रहते नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से बेहद दूर हो गए थे. क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बात कोई नहीं सुन रहा था और उन्हें बेइज्जती उठानी पड़ रही थी. कार्यकर्ताओं का उदासीन होना लोकसभा चुनाव में जदयू की हार का एक बड़ा कारण था. इसलिए नीतीश कुमार ने तय किया कि इस बार कार्यकर्ताओं को ही फोकस किया जाए और उनके मन में जो भी बात है, उसे तसल्ली से सुना जाए.

जनसभा तय होने से कार्यकर्ताओं से ठीक से बात नहीं हो पाती है क्योंकि इस समय कार्यकर्ता जनसभा की ही तैयारी में लगे रह जाते हैं. इसलिए इस बार काफी सोच समझ कर यह तय किया गया कि केवल और केवल कार्यकर्ताओं को ही समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी बात तसल्ली से रख सकें. नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से यह बात कहेंगे कि पिछली बार आप से संपर्क टूट गया था इसलिए हम संपर्क यात्रा पर निकले हैं. कार्यकर्ताओं से यह वादा भी किया जाएगा कि पिछली बार की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा. उनके मान-सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा और अगर सत्ता में वापसी हुई तो उन्हें उचित हिस्सेदारी भी दी जाएगी. नीतीश कुमार को इस बात का पूरी तरह एहसास है कि बिना उत्साही और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम के वह भाजपा को परास्त नहीं कर पाएंगे. जनसभाओं में कितनी भी भीड़ क्यों न आ जाए पर इस भीड को बूथ तक ले जाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं. इसी का फायदा बार-बार भाजपा उठा ले जाती है और जदयू मात खा जाती है. इसलिए इस बार भाजपा को उसके ही हथियार से मारने की कोशिश की जा रही है. मजबूत संगठन ही सत्ता का रास्ता बनाता है यह बात जदयू के रणनीतिकारों को समझ आ गई है. इसलिए सारा जोर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उनमें जोश भरने पर है. अपनी यात्रा में नीतीश कुमार उन इलाकों में जा रहे हैं, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया था. यह किला नीतीश कुमार के लिए तोड़ना जरूरी है ताकि मिशन 2015 को फतेह किया जा सके. देखना दिलचस्प होगा कि संपर्क यात्रा में नीतीश कुमार अपने रूठे कार्यकर्ताओं को कितना मना पाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे नीतीश

इंतेजारुल हक

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चंपारण से शुरू हो रही संपर्क यात्रा को लेकर राजनीतिक तापमान एक बार फिर काफी गर्म हो गया है. इस यात्रा से चंपारण की राजनीति में पड़ने वाले दूरगामी असर की समीक्षा की जाने लगी है. नीतीश कुमार तेरह नवंबर को चंपारण के दोनों जिलों पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में संपर्क यात्रा करेंगे तथा जिला सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कई जिम्मेदारियां भी सौपेंगे. उनके आगमन को लेकर जदयू नेताओं ने अपनी सक्रियता काफी तेज कर दी है और सम्मेलन में पंचायतों से लेकर प्रखंडों व जिला मुख्यालय तक के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है. इसके लिए विधानसभावार कमेटी बनाई गई है और सभी विधान सभा क्षेत्रों में कार्यक्रम पदाधिकारियों की तैनाती की गई है. सभी कार्यपदाधिकारियों को हर तरह से मुस्तैद रहने व कार्यकर्ताओं नीतीश की यात्रा के बारे जानकारी देने को कहा गया है. लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकें भी हो रही हैं और नीतीश की संपर्क यात्रा के उद्देश्यों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है.

चूंकि कोई जनसभा तो होगी नहीं, केवल सम्मेलन होगा जिसमें पार्टी के नेता व कार्यकर्ता ही शिरकत करेंगे. इसलिए आम जनता का कोई खास मतलब भी इस सम्मेलन से नहीं रहेगा. हां, इस सम्मेलन में नीतीश जी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे आगामी चुनाव को लेकर उत्साहित करते हैं और इनके बीच किस तरह का संदेश देते हैं, इस बाबत सभी की नजर रहेगी. यहां बतातें चलें कि

एमएन शाही | मासूम खां | प्रमोद सिन्हा

पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 21 विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें पूर्वी चंपारण के पांच विधान सभा क्षेत्रों नरकटिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन व गोविंदगंज, तथा पश्चिमी चंपारण के चार विधान सभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, बगहा, नौतन व लौरिया पर जदयू का कब्जा है जबकि पूर्वी चंपारण के छह विधान सभा क्षेत्रों मोतिहारी, सुगौली, रक्सौल, केसरिया, हरसिद्धि पर भाजपा का कब्जा है. इसके अलावा चिरैया विधान सभा पर राजद का ढाका विधान सभा पर निर्दलीय विधायक हैं. वहीं पश्चिमी चंपारण के पांच विधान सभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है. इन सभी विधान सभा क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायतों से लेकर जिला मुख्यालय तक के कार्यकर्ताओं व नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है. इधर पार्टी के पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिन्हा बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की सभा व यात्रा को लेकर हर तरह की तैयारियां की जा रही है. जिला स्कूल के मैदान में नीतीश कुमार जिला सम्मेलन करेगें और कार्यकर्ताओं को नई दिशा देंगे. उनका मानना है कि नीतीश कुमार यह संपर्क यात्रा पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए काफी लाभदायक साबित होगी. वे बताते हैं कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और वे अपने नेता का दिशा-निर्देश लेने के लिए बेताब हैं. इधर पार्टी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मासूम खां बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है और अधिक से अधिक से युवा नेताओं व कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी. दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण जिला में भी नीतीश की यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है. पार्टी के पश्चिमी चंपारण जिलाध्यक्ष डॉ. एनएम शाही ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 को रात्रि में बेतिया में ही विश्राम करेगें. कार्यक्रम की तैयारियों की बाबत उन्होंने बताया कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने चौथी दुनिया को बताया कि प्रत्येक प्रखंडों में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही है और सम्मेलन में कार्यकर्ता के साथ-साथ समर्थक भी अधिक संख्या में पहुंचेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे. इसके अलावा तैयारी समिति भी बनाई गई है जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.अब सभी की नजर सम्मेलन है. सम्मेलन में नीतीश कुमार क्या संदेश देते हैं यह तो समय निर्धारित करेगा किन्तु उनकी यात्रा से चंपारण की राजनीति गरमा गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

समाज की खुशहाली के लिए जागरूक हो महिलाएं

जबतक महिलायें पूरी तरह से अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नही होंगी तब तक समाज व राष्ट्र की खुशहाली संभव नहीं है. उक्त बाते राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेवारी ने पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दौरे के बाद मठिया में स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. ताहेरा तब्बसुम के आवास पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति महिला आयोग गंभीर है और इस बाबत एक बेहतर कार्य योजना बनाकर अपना काम कर रही है. उन्होंने मोतिहारी जेल में बन्द महिला कैदियों की दुर्दशा को गंभीरता से लेते हुए बताया कि जेल भ्रमण के क्रम में महिला कैदियों की दास्तान कुछ अलग थी. उन्होंने कहा कि जेल में बंद महिला कैदियों का दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है और वे अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही हैं. जेल प्रशासन भी इनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहा है. सदस्या के साथ हुसना सुभानी भी मौजूद थी. मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार शुक्ला, अनवर आलम अंसारी, डॉ. नसीमुल हक, शमीमुल हक, अंजुम, जियाउल हक समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी उपस्थित थे. चिकित्सक डॉ. ताहेरा तब्बसुम ने अपने आवास पर आयोग की सदस्या का भव्य स्वागत किया.

अनिरुद्ध की मांग

पूर्वी भारत के बीएड कॉलेजों को मान्यता देने वाली भारत सरकार की संस्था नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भुवनेश्वर के सदस्य रहे और मगध विश्वविधालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉ. अनिरुद्ध सिंह ने गया में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम गौतम बुद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय रखने की मांग की है. डॉ. सिंह ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी को लिखे पत्र मे कहा कि आपने जिस प्रकार मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविधालय खोलकर इसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम रखकर सम्मानित किया है, उसी प्रकार गया मे चल रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम गौतम बुद्ध केन्द्रीय विश्वविधालय रखने की घोषणा गौतम बुद्ध को भी सम्मानित करने की कृपा करें. ऐसा करने से भारत ही नही दुनीया के तमाम बौद्ध देशों तथा बौद्ध धर्मावलम्बियों को अपार खुशी होगी.

आईपीएस का सम्मान

बोधगया के ज्ञान भारती आवासीय परिसर मे भारतीय पुलिस सेवा(आई पी एस) बने विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र आशुतोष श्शेखर को सम्मानित किया गया. विद्यालय के प्राचार्य बिनोद कुमार भारद्वाज ने बताया कि आशुतोष वर्ष 1998 में दसवीं एवं 2000 में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. विद्याालय के निदेशक रोमित कुमार एवं प्राचार्य ने अंग वस्त्र तथा पुष्प गुच्छ देकर आशुतोष शेखर को सम्मानित किया. इस अवसर पर आईपीएस आशुतोष ने बताया कि विद्यालय का अनुशासन एवं समय सारणी का मेरे जीवन मे गहरा प्रभाव डाला है. छात्रों को जीवन मे समय का सदुपयोग करना चाहिए. अनुशासन मे रह कर कार्य करने मे सफलता अवश्य मिलती है. ■

– सुनील सौरभ

सीतामढ़ी

किसके समर्थन से जीते इरशाद!

सीतामढ़ी नगर परिसद में इपसभापति के चुनाव में जो हुआ वह जिले के इतिहास में अजूबा से कम नहीं है. दो खेमों में विभक्त परिसद के सभापति सुवंस राय का समर्थन इपसभापति पद के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह को था, तो पूर्व इपसभापति युगल किशोर प्रसाद मो. इरशाद के पक्ष में गोलबंद थे. चुनाव के दिन कुल 28 में से करीब डेढ़ दर्जन पार्षद अमरेंद्र को उपसभापति बनाने का संकल्प लेकर परिसद कार्यालय पहुंचे. जब चुनाव बाद मतगणना हुई तो परिणाम बिल्कुल उल्टा आया. अमरेंद्र को कुल 12 तो इरशाद को 14 मत मिले. अब यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि आखिर मो. इरशाद को किस-किस पार्षद ने समर्थन किया...

वाल्मीकि कुमार

पिछले 17 अक्टूबर को सीतामढ़ी नगर परिसद कार्यालय में अहले सुबह से ही गहमा–गहमी रही. एक ओर पार्सद समर्थकों का हुजूम तो दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम उपसभापति पद का चुनाव कराने की तैयारी में लगे रहे. निर्धारित समय पर परिसद कार्यालय के सभागार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गयी. इस दौरान जो कुछ भी हुआ वह किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी माना जाता है. बताया जाता है कि पूर्व से सभापति खेमा के अमरेंद्र कुमार सिंह आश्वस्त थे कि साथ आए करीब डेढ़ दर्जन पार्सदों के समर्थन के बूते वे चुनाव में बाजी मार उपसभापति की कुर्सी पर काबिज हो जायेंगे. परंतु उनको इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि विरोधी खेमे के चुनावी चक्रव्यूह में उनका सपना धराशायी होने वाला है. अमरेंद्र की नजर सामने के विरोधी खेमे के इन आधा दर्जन पार्सदों पर टिकी रही जो साफ तौर पर उनका विरोध करने वाले थे. जबकि इतने ही भीतरघाती पार्षद उनके साथ बैठ कर विरोधी पूर्व उपसभापति युगल किशोर प्रसाद के पक्ष के प्रत्याशी मो. इरशाद के पक्ष में अंदर ही अंदर एकजुट थे. चुनाव बाद उस समय स्थिति अजीबो–गरीब हो गयी, जब बतौर चुनाव प्रेक्षक एडीएम विभागीय जांच पारसनाथ सिंह व निर्वाची पदाधिकारी सदर एसडीओ संजीव कुमार ने मो. इरशाद को विजयी घोषित कर दिया. चुनाव के दौरान अमरेंद्र कुमार सिंह को जहां 12 मत मिले वही इरशाद को 14 मत हासिल हुए.

हैरत की बात यह है कि चुनाव नतीजा आने के बाद भी अमरेंद्र के साथ इतने ही पार्सद सभागार में मौजूद रहे जो साथ आये थे. जब प्रमाण पत्र देकर शपथ ग्रहण के लिए सदर एसडीओ ने पार्षदों को बुलाया तो उस वक्त भी अधिकांश पार्षद खुद को उक्त कार्यक्रम में जाने से परहेज किया. अंतत: महज आधा दर्जन पार्षदों के साथ ही नवनिर्वाचित उपसभापति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी. इसके बाद एक ओर जहां नवनिर्वाचित उपसभापति मो. इरशाद के खेमा में खुशी का माहौल कायम हो गया तो दूसरी ओर भितरघात के शिकार सभापति समर्थक अमरेंद्र के खेमे में आक्रोश की चिंगारी सुलगने लगी. मो. इरशाद का गुट जैसे ही समर्थकों के साथ परिसद कार्यालय परिसर से निकले, वैसे ही अमरेंद्र खेमा में भितरघाती पार्षदों की करतूत को लेकर माहौल गरमाने लगा. इस दौरान भी मौजूद डेढ़ दर्जन पार्षदों ने खुद को अमरेंद्र के समर्थन में मतदान के जिद पर डटे रहे. जब सीतामढ़ी नगर परिसद में कुल पार्षदों की संख्या 28 है. जिसमें दो पार्षद चुनाव में भाग नहीं ले सके. बचे 26 में से 18 क्रमश: सुवंश राय, मंजू देवी, ललिता देवी, सरोज देवी, उपेंद्र प्रसाद, सुनील अकेला, अरुण राय, लक्ष्मी देवी, पप्पू मिश्रा, मनोज कुमार, राम दुलारी देवी, नगीना देवी, रानी देवी, मधुमस्करा, पंकज कुमार, सरिता देवी व विनीता देवी अमरेंद्र के साथ तो इधर मात्र 7 पार्सद क्रमश: युगल किशोर प्रसाद, इंदिरा गुप्ता, डॉ. अमरनाथ गुप्ता, धनंजय कुमार, रामानेक सिंह व ओरम खतून ही मो. इरशाद के साथ हो सकते थे. इनमें 1 पार्षद नूरजहां अंजुम तबियत खराब रहने के कारण चुनाव में भाग नही ले सकीं थीं. परंतु चुनावी नतीजे से साफ हो गया कि 12 पार्षद अमरेंद्र के पक्ष में और 14 मो. इरशाद के साथ रहे. जो किसी आश्चर्य से कम नहीं था.

चर्चा यह भी है कि बात यहां तब बढ़ गयी कि अमरेंद्र के पक्ष में जिद पर अड़े पार्षद ने एक धार्मिक स्थल पर पहुंच कर इस बात की कसम खाकर साबित करने से परहेज नही किया कि उनका मत अमरेंद्र के पक्ष में गया है.नगर परिषद का गणेश परिक्रमा करने वाले कुछ लोग शहर में यह भी चर्चा कर रहे है कि मो. इरशाद को उपाध्यक्ष पद पर काबिज कराने मेंएक पूर्व सांसद ने भी अहम भूमिका निभायी है. वैसे इसमें सच्चाई चाहे जो हो परंतु इतना तो साफ हो गया है कि अब नगर परिसद में राजनीति एक बार फिर नये अंदाज में शुरू होगी. सभापति व उप सभापति के बीच की राजनीति के कारण विकास योजनाओं का हाल क्या हो सकता है इसका आभास भी लोगों को होने लगा है.

चर्चा यह भी चल रही है कि करीब एक माह पहले पूर्व उपसभापति युगल किशोर प्रसाद का पद से इस्तीफा के बाद उन पर सभापति की ओर से लगाया गया अविश्वास और पुन: पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा लाया गया सभापति के खिलाफ अविश्वास के दौर ने नगर परिसद की राजनीति को गति देने का काम किया. सभापति के खिलाफ लाये गये अविश्वास के दौरान पूर्व उपसभापति को अपने ही समर्थक पार्सदों के भितरघात का सामना करना पड़ा था, जबकि उपसभापति के चुनाव में सभापति खेमे को भितरघात का शिकार होना पड़ा है. कुल मिलाकर अब तक परिसद की राजनीति बराबरी पर आ चुकी है. अब नगर परिसद राजनीति के पटरी पर रेस लगाती है अथवा शहर के विकास को लेकर गंभीर होती है इसका सभी को इंतजार है.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में तिनके-तिनके बिखर गया झाविमो

बाबूलाल मरांडी की नीतियों में कहां हो रही चूक

मंगलानंद

feedback@chauthiduniya.com

एक समय था जब झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के सबसे ईमानदार नेताओं में एक रहे बाबूलाल मरांडी की पार्टी में शामिल होने पर झारखंडी नेता गर्व महसूस करते थे. अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पार्टी के प्रमुख नेता सहित पार्टी के 11 में से 8 विधायकों ने झारखंड विकास मोर्चा से अपना नाता तोड़ लिया? वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में झाविमो के 11 विधायक चुन कर आये थे. इनमें से सिर्फ तीन ही विधायक पार्टी के साथ बचे हैं. पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की तानाशाही और अदूरदर्शिता के कारण पार्टी का वजूद समाप्त होने के कगार पर है. पार्टी का अंतरकलह कई बार उजागर भी हुआ लेकिन पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसे अपने अंदाज में दबा दिया. पार्टी छोड़नेवाले विधायकों में सात ने भाजपा और एक ने झामुमो का दामन थाम लिया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेताओं के पाला बदलने से पार्टी की परेशानी और बढ़ेगी. दो विधायकों के पार्टी छोड़ने से एक दिन पहले ही पार्टी के महासचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया. चुनाव से पहले विधायकों के पार्टी छोड़ने से चुनाव की तैयारी प्रभावित हो सकती है. राज्य में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू है. वहीं, दूसरी ओर गढ़वा के सिटिंग विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पार्टी छोड़ दी. वहीं, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने भी पार्टी का साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थाम लिया है. पार्टी ने जिन्हें घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी दे रखी थी, वे भी अब झाविमो के साथ नहीं है. पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया. विधायकों के एक बाद एक पार्टी छोड़ने से पार्टी के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह ने विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी के गठबंधन को लेकर भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं.

इन विधायकों ने छोड़ी पार्टी

निजामुद्दीन अंसारी (राज धनवार), निर्भय शाहबादी (गिरिडीह), समरेश सिंह (बोकारो), फूलचंद मंडल (सिंदरी), ढुल्लू महतो (बाघमारा), सत्येंद्र नाथ तिवारी (गढ़वा), चंद्रिका महथा (जमुआ), जय प्रकाश सिंह भोक्ता (सिमरिया).

प्रमुख नेता जिन्होंने छोड़ा साथ

केपी शर्मा, गौतम सागर राणा, राजीव रंजन प्रसाद, अजय नाथ शाहदेव व अन्य.

जो विधायक पार्टी के साथ हैं

प्रदीप यादव (पोड़ैयाहाट), मिस्त्री सोरेन (राज धनवार), अरविंद सिंह (ईचागढ़) ■

बेगूसराय

कौन महसूस करेगा कल्पवास मेला की पीड़ा

सुरेश चौहान

बिहार सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में कुंभ स्थल सिमरिया घाट का कल्पवास मास मेला राजकीय मेला घोषित होने के वर्षो बाद भी सुविधाओं का मोहताज है. कल्पवासियों के लिए स्नान घाट का निर्माण नहीं हो पाया है. मेला क्षेत्रा में प्रकाश, सफाई, एवं सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं है. कटाव के कारण गंगाघाट खतरनाक बना हुआ है.

बेगूसराय से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण–पश्चिम कुंभस्थल सिमरिया घाट पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एक महीने के लिए राजकीय 'कल्पवास मास मेला' लगता है. धर्मिक मान्यता है कि सिमरिया घाट में गंगा नदी के तट पर एक महीने तक कल्पवास करते हुए नित्य गंगा का पूजन करनेवाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. यों तो हिन्दू धर्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के अलावा माघ एवं वैशाख महीने में भी कल्पवास किया जा सकता है लेकिन मौसम की दृष्टि से माघ एवं वैशाख से अच्छा कार्तिक माह ही कल्पवास के लिए सर्वोत्तम होता है. सिमरिया घाट पर ही गंगा नदी के किनारे कल्पवास करने के पीछे कई धर्मिक आधार, जनश्रुति एवं किवदंतियां प्रसिद्ध हैं. वर्तमान बेगूसराय जिला प्राचीन मिथिला राज्य का अंग था. इस काल में गंगा नदी यहां उत्तरवाहिनी थी और मगध तथा मिथिला राज्य की सीमा थी. उसी काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी मिथिलांचल में जीवित है–बेटी की विदाई होने पर गांव की सीमा पर उसकी सवारी रोककर उसे जल पिलाया जाता है. जब पुरुषोत्तम रामचन्द्र की शादी जानकी से हुई और राजा जनक ने बेटी की विदाई की तो इसी परंपरा के अंतर्गत मिथिला राज्य की सीमा पर सीता की पालकी रखी गयी थी एवं उन्हें गंगा जल का पान कराकर विदा किया गया था. इसी समय से इस स्थान का नामकरण सिमरिया हो गया.

सिमरिया महादेव का मंदिर : धार्मिक ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर, जहां से गंगा नदी उत्तरवाहिनी होती थी, महादेव का एक अतिप्राचीन मंदिर था जो मिथिला राज्य में सिमरिया महादेव के नाम से जाना जाता था. मुंगेर गजेटियर के अनुसार अंग्रेज लेखक बुकानन ने भी 1903 में अपने सर्वे की रिपोर्ट में सिमरिया महादेव का उल्लेख किया है. मिथिला के राजा सिमरिया महादेव के अनन्य भक्त थे और उनका मानना था कि बाहरी शत्रुओं से मिथिला की रक्षा इस सीमा पर साक्षात महादेव करते हैं और राजा जनक ने भी पूरे कार्तिक माह यहां गंगा तट पर कल्पवास कर यज्ञ कराया था, गंगा एवं महादेव का पूजन किया था.

वेदों के ख्याति प्राप्त ज्ञाता आचार्य स्व. गंगेश मिश्र, सिद्धपीठ कालीधाम सिमरिया के पीठाधीश्वर चिदात्मन जी महाराज सहित अनेक विद्वानों ने भी सिमरिया के पास गंगा नदी के उत्तरवाहिनी होने की पुष्टि की है. उनके अनुसार गंगा नदी के किनारे के इस भूभाग को मिथिला राज्य में 'वृहदतट' के नाम से जाना जाता था जो कालान्तर में अपभ्रंश होकर बीहट कहलाने लगा. इसी वृहदतट पर पंचवदन महादेव मंदिर था. जिस स्थान पर गंगा की धारा उत्तरवाहिनी होती है उस स्थान को धर्मिक ग्रंथ में पवित्र स्थान माना गया है.

राजा परीक्षित को शाप : सिमरिया में गंगा उत्तरवाहिनी थी, महादेव का मंदिर था, मिथिला राज्य यहीं समाप्त होता था और यहां तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध होता था जिस कारण मिथिला के राजा एवं प्रजा ने इस स्थल का कल्पवास के लिए चयन किया होगा. कल्पवास की वही परंपरा आज भी यहां कायम है. धर्मिक ग्रंथ 'सुख सागर' के अनुसार अभिमन्यु पुत्र, भारत के चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने एक बार तपस्या में लीन ऋषि की गर्दन में सांप लपेट दिया. ऋषि पुत्र ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को शाप दे डाला कि तुम्हारी अकाल मृत्यु सांप के काटने से हो जाएगी. तपस्या के बाद जब ऋषि की आंखें खुली तो जनमेजय ने उन्हें सारी बातें बताई. पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को दिये गये शाप के कारण ऋषि को काफी तकलीफ हुई और उन्होंने राजा परीक्षित से कहा कि आप गंगा तट पर एक महीने तक कल्पवास करते हुए गंगा की पूजा करें जिससे अकाल मृत्यु होने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति होगी. कहा जाता है कि राजा परीक्षित ने इसी सिमरिया घाट पर एक माह तक कल्पवास किया था. इसी समय से सम्पूर्ण मिथिला राज्य में कल्पवास की प्रथा प्रारंभ हो गयी. मिथिलवासी गंगा को पवित्र मानते हैं और परिजनों की मृत्यु के बाद उनके शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उसकी भस्म का कुछ भाग अनिवार्य रूप से गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं.

कर्ण का कृष्ण से आग्रह : एक किवदंति के अनुसार अंगराज कर्ण ने महाभारत की लड़ाई के मैदान में कृष्ण से आग्रह किया था कि मरने के बाद उनकी लाश का दाह संस्कार गंगा नदी के तट पर उसी स्थान पर किया जाए जहां की भूमि कुंआरी हो अर्थात जिस स्थान पर किसी दूसरे का दाह संस्कार न किया गया हो. भगवान कृष्ण ने ध्यानमग्न होकर ऐसे स्थान की खोज की तो सिमरिया में ही एक सुई की नोंक के बराबर ऐसा स्थान मिल गया. जहां सूई की नोंक पर अपना हाथ रखकर इसपर चिता रचाकर कृष्ण ने राजा कर्ण के शव का दाह संस्कार किया था. इसी कारण इस स्थान का नाम 'हस्तदाह' हस्त–हाथ, दाह–अग्नि पड़ा जो कालान्तर में गंगा नदी के कटाव के कारण सिमरिया से विखंडित हो गई और आजकल अपभ्रंश होकर हथिदह के नाम से जाना जाता है. सिद्धपीठ कालीधाम सिमरिया के पीठाधीश्वर श्री चिदात्मन जी महाराज के अनुसार तारा–पीठ, कालीधाम, कोलकता, की तरह सिमरिया घाट भी जागृत श्मशान है. तांत्रिक विद्या की सिद्धी के लिए यह कामाख्याधाम की तरह महत्व रखता है. समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से छिटककर यहां भी अमृत की कुछ बूंदे गिरी थीं जिससे इसे जागृत स्थल के रूप में प्रसिद्धी मिली.

आज भी मिथिलांचल, उत्तरी बिहार के जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, तथा उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों एवं पड़ोसी देश नेपाल से प्रतिवर्ष कार्तिक मास में हजारों हिन्दू सिमरिया घाट आकर पर्णकुटीर बनाकर उसमें रहते हुए एक महीना कल्पवास कर गंगा का पूजन करते हैं. यद्यपि गंगा नदी का प्राचीन स्वरूप वर्तमान में कायम नहीं रह गया है फिर भी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर सिमरिया में कल्पवास मास मेला प्रतिवर्ष लग रहा है. इस अवसर पर सिमरिया में लगभग एक लाख श्रद्धालु एक महीने के लिए एकत्रित होते हैं लेकिन उनकी आस्था तब डिगने लगती है जब वे कुव्यवस्था के शिकार होने लगते हैं. एशिया प्रसिद्ध इस राजकीय कल्पवास मेला के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से इतने अधिक कल्पवासियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है. फलत: प्रतिवर्ष कुछ कल्पवासी तरह–तरह के संक्रामक रोग से ग्रसित होकर तथाकथित 'मोक्ष' की प्राप्ति करते हैं. यहां आने वाले को सर्वप्रथम स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है. यद्यपि प्रशासन की ओर से चापाकल की व्यवस्था की जाती है लेकिन कल्पवासी धर्मिक आस्था के कारण गंगाजल का ही सेवन करते हैं. विडंबना यह है कि किनारे से लगभग 50 फीट अंदर तक गंगाजल काफी प्रदूषित हो चुका है. क्योंकि राजेन्द्र पुल के कारण किनारे का जल बिल्कुल स्थिर है और सिमरिया घाट के इसी किनारे पर प्रतिदिन औसतन 50 मुर्दे जलाये जाते हैं जिसका अवशिष्ट भाग जल स्थिर रहने के कारण किनारे में रह जाता है और इसी प्रदूषित जल को कल्पवासी पीने एवं खाना पकाने के काम में लाते हैं.

दूसरी ओर बाटा का चमड़ा साफ करने का कारखाना, मैकडोवेल शराब कारखाना एवं बरौनी तेल शोधक कारखाना आदि का कचरा भी सिमरिया घाट के गंगाजल को प्रदूषित कर देता है. यों तो गंगाजल में शुद्धिकरण की अद्भुत क्षमता है. लेकिन कल कारखाने एवं स्वार्थ लोलुप मानवों के कारण क्षमता में कमी जारी है. राजकीय मेला घोषित होने का कितना लाभ कल्पवासियों को मिल पायेगा, इसका साक्षी आनेवाला वक्त बनेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

शोक सभा का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के स्वर्णकार धर्मशाला में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विजय स्वर्णकार की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया. मौके पर पार्टी कार्यकर्ता घनश्याम शर्मा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया. कार्यक्रम में नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, प्रदेश नेता सुफल झा, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, निर्मल, अमरेंद्र कुमार, शिव कुमार अग्रवाल, मो. सलीम, नीतेश भारद्वाज, अरुण ठाकुर, ओम प्रकाश, दिलीप कुमार गुप्ता, शिव शंकर प्रसाद, राधा कृष्ण प्रसाद, संजीव कुमार सिंह, जय किशोर साहू, संजय कुमार, विकास कुमार व विशाल कुमार समेत अन्य थे.

– ब्रजेश

विचार मंच ने दिया धरना

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यादव विचार मंच के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. लखनदेई नदी की उडाही को लेकर लगातार जारी आंदोलन की श्रृंखला में मंच कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी दी. मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना में चंद्रजीत प्रसाद यादव, आफताब अंजुम बिहारी, गौरी यादव, शिव शंकर यादव, मुन्ना सिंह यादव, पवन यादव, धनंजय यादव, संजय यादव, आलोक यादव, धीरज यादव व जवाहर यादव समेत अन्य थे.

चित्रगुप्त पूजनोत्सव का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में चित्रांश युवा मंच के तत्वावधान में चित्रगुप्त पुजनोत्सव का आयोजन किया गया. मौके पर स्थानीय बाल कलाकारों की टोली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वाह–वाही बटोरी. कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीओ संजीव कुमार, एएसपी संजीव कुमार सिंह, डीएसपी एमएन उपाध्याय, डीएवी स्कूल के प्राचार्य अनंत सहाय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया. मौके पर नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, व्यवसायी संघ के मीडिया प्रभारी कैलाश कुमार हिसारिया समेत अन्य थे. ■

–चौथी दुनिया ब्यूरो

अन्तत: डिप्टी मेयर से हटना पड़ा मोहन को

सुनील सौरभ

अन्तत: आखौरी ओकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद से हटना ही पड़ा. इस बार उन्हें निगम की राजनीति में बुरी तरह पराजित होना पड़ा. लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के हर फन में माहिर मोहन श्रीवास्तव को दूसरी बार डिप्टी मेयर पद से हटना पड़ा.

पिछले एक साल से गया नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षदों की गुटबाजी तथा आंतरिक राजनीति के दांव–पेच में फंसा है. शहर के सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं. नगर आयुक्त भी वार्ड पार्षदों के आपसी झगड़े का नाजायज फायदा उठाते रहें हैं. पूर्व के कई नगर आयुक्तों पर सफाई, विकास कार्यो, मिनी हाई मास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट के नाम पर ठेकेदारों को फर्जी बिल का भुगतान करने का आरोप भी लगा है. इस संबध में एक मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है. गया जैसे महत्वपूर्ण शहर के नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जिम्मा लेने वाले गया नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर(दो बार) के पक्ष–विपक्ष में विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव लाने मे ही वर्ष का अधिकांश समय बीत गया. शहर वासियों का गया नगर निगम में कार्य नहीं होने देने का सीधा आरोप डिप्टी मेयर पद से हटे मोहन श्रीवास्तव तथा उनके समर्थक पार्षदों पर है. गया नगर निगम में आपसी राजनीति और विकास कार्य ठप रहने पर वार्ड पार्षद भी इतने खफा हो गये कि मोहन श्रीवास्तव को दूसरी बार डिप्टी मेयर पद से हटाने के लिए एकजुट हो गये. वार्ड 36 के पार्षद चितरंजन प्रसाद वर्मा द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन मे 31 वार्ड पार्षदों तथा विरोध मे मात्र 11 पार्षदों ने अपना मत दिया. तीन मत अवैध घोषित किये गये. बुरी तरह पराजित मोहन श्रीवास्तव को अब शहर की राजनीति से उखाड़ फेंकने के लिए विरोधी कमर कस लिए हैं. किसी भी व्यक्ति को अपने वश मे करने मे फन मे माहिर मोहन श्रीवास्तव का कोई भी हथकंडा अब नगर निगम में नहीं चलेगा. यह बात आम गयावासियों की है. क्योंकि मेयर पद पर एक मजबूत महिला का निर्वाचन होना तथा दूसरी ओर एक ईमानदार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का नगर आयुक्त बनना बता रहा है. लोगों को उम्मीद है कि गया नगर निगम में हुए तमाम तरह के घोटाले उजागर होंगे और दोषी पर कार्रवाई होगी. जून 2014 में गया नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत से हटा दिया था. इस समय मोहन श्रीवास्तव पटना के एक होटल मे नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पकड़े जाने पर जेल मे बंद थे. इस पर मोहन श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर यह कहा था कि मेरे खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मेरा पक्ष नहीं लिया गया. इसलिए मुझे हटाना अवैध है. कोर्ट ने भी गया नगर निगम की उक्त बैठक को अवैध घोषित करते हुए मोहन श्रीवास्तव को पुन: डिप्टी मेयर पद पर काबिज होने का आदेश देते हुए कहा कि वार्ड पार्षद यदि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो इसमें डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे. इस बीच आखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने डिप्टी मेयर पद पर पुन: काबिज होने और नाबालिग लड़की से रेप मामले में साक्ष्य के अभाव मे बरी होने की खुशी मे अपने समर्थकों द्वारा जगह–जगह सम्मान समारोह में शिरकत करते रहे.

गया

इसी दौरान उत्साही मोहन श्रीवास्तव मेयर विभा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाने मे सफल हो गये. इसके बाद मेयर और नगर निगम पर अपनी पकड़ बनाने के फेर मे निगम को अस्थिर करने का आरोप मोहन श्रीवास्तव पर लगाते हुए वार्ड पार्षदों ने एकजुट होकर पहले तो मेयर पद पर राजनीतिक रूप से मजबूत परिवार से आने वाली वार्ड पार्षद सोनी कुमारी को मेयर बनाया. इसके बाद डिप्टी मेया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया. स्थिति ऐसी आ गयी कि खुद मोहन श्रीवास्तव भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर सके और बैठक मे अनुपस्थित रहे. डिप्टी मेयर को हटाने में मुख्य भूमिका वार्ड 36 के वार्ड पार्षद चितरंजन प्रसाद वर्मा ने निभाई. उनका साथ वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद एवं अन्य 32 वार्ड पार्षदो ने दिया. नगर निगम के उपयुक्त स्थिति से परेशान शहरवासियों को उम्मीद है कि अब शेष बचे समय मे वार्ड पार्षद अपने–अपने क्षेत्र मे विकास का काम करेगें.■

feedback@chauthiduniya.com

स्वतंत्र भारत में वर्ष 1963 में उक्त चीनी मिल को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया. परंतु किन्हीं कारणों से भारत सरकार महज एक दशक बाद ही मिल संचालन से अपना हाथ खींच लिया. तब राज्य सरकार ने मिल संचालन में रुचि दिखानी शुरू की. वर्ष 1972 से लेकर 77 तक राज्य सरकार किसी प्रकार मिल संचालन करती रही. बाद में मिल की स्थिति बदतर होने लगी.

मोतिहारी

वजूद बचाने में लगा ट्रांसपोर्ट निगम

बसों की संख्या कम होने की वजह से यात्री प्रतीक्षालय में दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है. यहां मौजूद कर्मचारी अपना समय ही काट रहे हैं. हालांकि ऐसी बात नहीं है कि राज्य मुख्यालय व विभाग के आलाधिकारी निगम की इस दुर्दशा से अवगत नहीं हैं. पूर्व में यहां के प्रतिष्ठान अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा चुका है और कई बार बसों की कमी को दूर करने के लिए डिमांड भी की जा चुकी है. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होना अपने-आप में एक अहम प्रश्न तो है ही, साथ ही बिहार की जदयू सरकार की यातायात व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है.

इंतेजारुल हक

यातायात व्यवस्था और सड़कों की स्थिति बेहतर करने के लाख दावे करने वाली बिहार सरकार की निगाहें राज्य ट्रांसपोर्ट निगम पर नहीं जा रही है. सरकार करोड़ों रुपये खर्च सड़क व्यवस्था पर तो खर्च करती है लेकिन राज्य परिवहन ट्रांसपोर्ट निगम की बदहाली उसे नजर नहीं आती. यही कारण है कि कारण चंपारण में स्थापित बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट निगम अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस मोतिहारी ट्रांसपोर्ट निगम के पास कभी तीस बसें हुआ करती थीं, आज उसके पास मात्र चार बसें ही रह गई हैं और वह भी पूरी तरह से खटारा हो चुकी हैं. ये जर्जर बसें कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं. इनमें से सबसे खटारा बस तो गैराज में खड़ी कर दी गई है जबकि बाकी तीन बसें सवारियों को नजदीक के जिलों तक ले जाने का काम कर रही हैं. जानकारों के अनुसार पहले यात्रियों को दिक्कतें नहीं हुआ करती थीं क्योंकि बसों की संख्या पर्याप्त थी. लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मोतिहारी से मुजफ्फरपुर व पटना तक जाने के लिए भी निगम के पास कोई बस नहीं है. इस कारण यात्रियों को मजबूर होकर निजी यात्री बसों का सहारा लेना पड़ता है. तीन बसों में दो मोतिहारी बखरी से रक्सौल जाती है जबकि एक मोतिहारी बखरी से ही वाया मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी तक जाती है. इसके अलावा निगम के पास दूसरी कोई बस नहीं है जिससे यात्रियों की यात्रा पूरी कराई जा सके.

बसों की संख्या कम होने की वजह से यात्री प्रतीक्षालय में दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है. यहां मौजूद कर्मचारी अपना समय ही काट रहे हैं. हालांकि ऐसी बात नहीं है कि राज्य मुख्यालय व विभाग के आलाधिकारी निगम की इस दुर्दशा से अवगत नहीं हैं. पूर्व में यहां के प्रतिष्ठान अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा चुका है और कई बार बसों की कमी को दूर करने के लिए डिमांड भी की जा चुकी है. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होना अपने-आप में एक अहम प्रश्न तो है ही, साथ ही बिहार की जदयू सरकार की यातायात व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है. इसी तरह की स्थिति पश्चिमी चंपारण जिले की है. जानकार बताते हैं कि निगम की सेवा इतनी कमजोर हो गई है कि यात्री निजी यात्री बसों से ही यात्रा करना अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.

निगम परिसर में जंग खा रहीं बसें, सूनसान पड़ा प्रतीक्षालय

यात्रियों में यह आम धारणा बन चुकी है कि सरकारी बसों में यात्रा करना, खतरे से खाली नहीं है. यही स्थिति अगर कायम रह गई और निगम द्वारा यात्रियों के लिए बसें नहीं मंगाई गईं तो वह दिन दूर नहीं कि निगम का नाम भी यात्री नहीं जानेंगे. इस बीच मोतिहारी निगम के प्रतिष्ठान अधीक्षक सुबोध कुमार सहाय ने इस बाबत पूछे जाने पर बताया कि अभी निगम के पास जो संसाधन हैं, उनका पूरा उपयोग हो रहा है. उन्होंने बताया कि निगम की तीन बसें अभी चल रही है और यात्री सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पटना के लिए एक प्राइवेट बस को, जो पूरी तरह से एसी है, निगम के अधीन चलाया जा रहा है. दूसरी तरफ रालोसपा नेत्री प्रतिमा कुमारी शाही सरकार पर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि केवल घोषणाओं पर टिकी जदयू की सरकार की गलत नीतियों के कारण ट्रांस्पोर्ट निगम की यह हालत हुई है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर

विद्वेष से किया बिहार केसरी का अपमान

बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 128वीं जयंती 21 अक्टूबर को समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में भी मनाया जाना था. परंतु राजनीतिक विद्वेष का आलम रहा कि निर्धारित तिथि से महज एक दिन पूर्व ऐसी चाल चली गई कि आयोजकों के होश ठिकाने लग गये. नतीजा हुआ कि आयोजन महज एक खानापूर्ति बन कर रह गया. भाजपा कार्यकर्ता राजीव रंजन कुमार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सम्मान के मौके पर यह बिहार केसरी का अपमान है ...

अमृता कुमारी

बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह वैसे लोगों में रहे हैं, जिनकी पहचान एक खास जाति, धर्म अथवा मजहब को लेकर नहीं बल्कि एक आदर्श व विचार के रूप में रही है. यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो अथवा सामाजिक कार्यकर्ता बिहार केसरी के सम्मान में बढ़कर भागीदारी देने से परहेज नहीं करता है. खास कर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर समरस समाज की स्थापना को लेकर पहल करने वाले बिहार केसरी की प्रासंगिकता कभी खत्म होने वाली नहीं है. पिछले दिनों जब प्रदेश मुख्यालय पटना में बिहार केसरी की 128 वीं जयंती की धूम मची थी, तब समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में ओछी राजनीति मुस्कान बिखेर रही थी. कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत ऐसी चाल चली कि अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह भाजपा कार्यकर्ता राजीव रंजन कुमार द्वारा आयोजित बिहार केसरी के जयंती समारोह को विफल करने का अथक प्रयास किया जाने लगा. अंतत: साजिश करने वालों की मंशा को भांप कर राजीव ने भी अपनी योजना में बदलाव कर दिया. वृहद की वजाये साधारण तरीका से ही बिहार केसरी की जयंती मनायी और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के तीन पंचायत का सर्वांगीण विकास अपने स्तर से कराने का संकल्प लिया.

बिहार केसरी के आदर्श को आत्मसात करने का संदेश समाज के लोगों को देते हुए कहा कि समस्तीपुर जिले में अब एक नया इतिहास गढ़ा जायेगा. शिक्षा के विकास को लेकर मेडिकल व पॉलीटेक्निक समेत अन्य शिक्षा की व्यवस्था कराने की मंशा भी व्यक्त की. स्थानीय राजनीति में कतिपय लोगों की हरकत को घिनौना करार देते हुए राजीव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब लोगों की आंखे खोल दी है. लोकसभा चुनाव के बाद जिनका भ्रम था कि विधानसभा चुनाव में भाजपा बेअसर साबित होगा, उनकी मंशा पर महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने पानी फेर दिया है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी विकास का दंभ भरने वाली जदयू के होश ठिकाने लगने वाले हैं.

बताया जाता है कि उक्त आयोजन पूर्व से समस्तीपुर जिले के सरायरंजन स्थित संत कबीर रामाश्रय महाविद्यालय प्रांगण में प्रस्तावित था. परंतु उक्त कॉलेज में पैक्स चुनाव का मतगणना केंद्र बनाये जाने के बाद परेशानी उत्पन्न होने लगी. चर्चा है कि मतगणना कार्य 20 अक्टूबर को ही संपन्न कराया जाना था. परंतु कतिपय कारण से स्थानीय प्रशासन ने मतगणना को अधर में लटका कर 21 अक्टूबर तक कॉलेज में कब्जा जमा लिया. नतीजतन कार्यक्रम आयोजन परेशानी का सवब बन गया. भाजपा कार्यकर्ता राजीव रंजन कहते हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासनिक तंत्र ने जानबूझ कर राजनीतिक दबाव में कार्यक्रम को विफल कर बिहार केसरी को अपमानित करने का काम किया है.■

feedback@chauthiduniya.com

हुक्मरानों की अनदेखी का नमूना बनी चीनी मिल

ब्रिटिश हुकूमत के समय में समस्तीपुर जिला मुख्यालय में एक चीनी मिल की स्थापना करायी गयी थी. तकरीबन 22 एकड़ जमीन पर स्थापित मिल में सैकड़ों लोगों को एक साथ रोजगार का अवसर मिला था. साथ ही पड़ोसी जिले दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य स्थानों के गन्ना उत्पादक किसानों को राहत मिली थी. परंतु आजाद भारत में केंद्र और राज्य सरकार की दखलंदाजी के बाद इस मिल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा. नतीजा हुआ कि अप्रैल 1997 से मिल में ताला लटका है. उसके बाद से कई कर्मचारी तो इस इंतजार में स्वर्ग सिधार गए एक बार मिल फिर खुलेगी और उनके घर में फिर से खुशहाली आएगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. बहुत से कर्मचारी अभी मिल के खुलने के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं....

अमृता कुमारी

संपूर्ण भारत की जनता जब अंग्रेजी हुकूमत की मनमानी से त्रस्त होकर उसकी गुलामी को झेलना अपनी बदनसीबी मान रही थी, ऐसे ही समय में भारत को व्यापार का केंद्र बना कर लूटने में लगी गोरी सरकार ने समस्तीपुर में एक चीनी मिल की स्थापना कर अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया था. एक ओर देशभक्तों की जमात देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का मन बनाने लगी थी, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार चीनी की मिठास में अपना उल्लू सीधा करने में लगी थी. बताया जाता है कि वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने तकरीबन 22 एकड़ जमीन पर समस्तीपुर- दरभंगा मुख्य सड़क के किनारे चीनी मिल की नींव डाली थी. जहां वर्ष 1921 से विधिवत चीनी उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो चुका था. करीब ढाई दशक तक अंग्रेजी सरकार ने उक्त मिल का संचालन कर दोनों हाथ से धन बटोरने का कार्य किया. परंतु इसी बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के सिरदर्द को बढ़ा दिया. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने ऐसा विकराल रूप लिया कि अंग्रेजी सरकार को अपना बोरिया-बिस्तर बांधने पर मजबूर होना पड़ा. बाद में भारत सरकार ने उक्त मिल के संचालन की कमान वेद सदर लैंडके और सुगर कारपोरेशन से थामी. इस बीच भारत में आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार का गठन किया गया. स्वतंत्र भारत में वर्ष 1963 में उक्त चीनी मिल को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया. परंतु किन्हीं कारणों से भारत सरकार महज एक दशक बाद ही मिल संचालन से अपना हाथ खींच लिया. तब राज्य सरकार ने मिल संचालन में रुचि दिखानी शुरू की. वर्ष 1972 से लेकर 77 तक राज्य सरकार किसी प्रकार मिल संचालन करती रही. बाद में मिल की स्थिति बदतर होने लगी.

वर्ष 1997 में सूबे बिहार में राजद सरकार का शासन था. इसी साल अप्रैल महीने में समस्तीपुर चीनी मिल अंतिम सांस लेकर तालाबंदी की शिकार हो गयी. तब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में राजद की राबड़ी देवी थीं. बताया जाता है कि इस समय मिल बंद होने के कई कारण थे, जिनमें सरकारी स्तर पर मिलने वाले अनुदान राशि का बंद हो जाना भी प्रमुख कारण था. इस बीच बिहार में चली राजनीतिक परिवर्तन हवा ने मिल के अस्तित्व को मिटाने में अहम भूमिका निभायी. शासन व सत्ता की छीना-झपटी में मस्त हुक्मरानों को चीनी मिल की दशा पर तरस नहीं आया. जब राजद शासन के खिलाफ राजनीतिक तापमान बढ़ा और एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार ने बंद चीनी मिल को चालू कराने का भरोसा दिलाया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि चीनी मिलों को नीजी हाथों में देकर बंद मिल का कायाकल्प कराया जायेगा. परंतु दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार भी इस मामले में हवा-हवाई ही साबित होकर रह गये. जानकारों की माने तो समस्तीपुर चीनी मिल का राज्य सरकार पर करीब 18 करोड़ रुपये बकाया है.

आखिरकार मार्च 2012 में समस्तीपुर चीनी मिल विंस इंटरनेशनल कंपनी के हाथ चली आयी. 28 करोड़ 77 लाख रुपये लेकर मिल को उक्त कंपनी के हवाले कर दिया गया. परंतु अब तक मिल में लटका ताला नहीं खोला जा सका है. कंपनी सूत्रों का कहना है कि अब तक मिल को हैंडओवर किया ही नहीं गया है. इस बीच मिल में कार्यरत सैकड़ों कर्मियों का जीना मुहाल होकर रह गया है. नौकरी पुन: मिलने की आस लिये कई कर्मी जहां स्वर्ग सिधार गये तो कई दुनिया से विदा होने के कगार पर हैं. वर्षो से बंद पड़ी चीनी मिल पिछले तकरीबन एक दशक से अतिक्रमणकारियों की जागीर बन कर रह गयी है. किसी को कोई कुछ कहने वाला तक नहीं है. जबकि मिल के अंदर करोड़ों रुपये मूल्य का संसाधन बर्बाद होकर रह गया है. अब बिहार में एक बार फिर राजनीति का चक्र पुराने रास्ते पर आता नजर आ रहा है. राजद शासन के खिलाफ जनता को गोलबंद कर सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने वाले पूर्व सीएम नीतीश कुमार राजद के लालू प्रसाद के साथ मिल कर पुन: बिहार में विकास का सारथी बनने का सपना देख रहे हैं. अगर सफलता मिलती है तो अपने पुराने वायदों का नीतीश कुमार कितना ख्याल रख पाते हैं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 नवंबर–16 नवंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

अनसुनी रह गईं भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई की बातें

गद्दारी के नाम पर विरोधी होंगे हलाल

उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई की बात वहीं की वहीं रह गई, लेकिन गद्दारों को ठिकाने लगाने की बात बाकायदा अपना असर भी दिखाने लगी है. यानी, आने वाले दिनों में पार्टी में ताकतवर कौन है, इसका संकेत और संदेश जहां-जहां पहुंचना चाहिए, वहां-वहां पहुंचने लगा है. पार्टी दफ्तर ने राम गोपाल के निर्देशों पर इतनी तेज़ी से काम करना शुरू किया कि 26 जिलों में पार्टी के कार्यों की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षकों को निर्धारित तिथियों से पहले ही रवाना कर दिया गया.

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपना कहा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपना कहा पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. सपा के नौवें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही चुन लिए गए, लेकिन पार्टी की बागडोर रामगोपाल अपने हाथों में ले चुके हैं. पार्टी के नवगठित संसदीय बोर्ड में भी शक्ति संतुलन रामगोपाल की तरफ ही झुकता हुआ दिखता पड़ रहा है.

आप याद करते चलें कि पिछले दिनों लखनऊ में संपन्न हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार के मंत्रियों के जन विरोधी क्रियाकलापों और उनके भ्रष्ट आचरण पर खुले तौर पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसे मंत्रियों की लिस्ट है जो बेजा गतिविधियों में लिप्त हैं और इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है. उन्होंने इस पर गहरा अफसोस जाहिर किया था कि उन्होंने संदिग्ध आचरण वाले कुछ मंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह सोचकर दी थी कि उनपर कार्रवाई होगी और वे मंत्रिमंडल से बाहर निकाले जाएंगे. लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया. इस पर अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों ने जोरदार तालियां बजा कर सपा अध्यक्ष के प्रति अपना समर्थन जताया था. लेकिन राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें रास नहीं आईं. उन्होंने मुलायम पर ही समानांतर प्रहार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के गद्दारों को संरक्षण देते हैं. हालांकि प्रो. रामगोपाल की भाषा बहुत संतुलित थी. उन्होंने कहा कि पार्टी के अस्सी–पच्चासी गद्दारों की सूची उन्होंने मुलायम सिंह को दी थी, लेकिन उन्होंने उन गद्दारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के बजाय उन्हें यह कहते हुए सुधरने की सलाह दी कि रामगोपाल उन्हें पार्टी से निकालना चाहते हैं. रामगोपाल की इन बातों पर वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने उनपर कटाक्ष भी किया कि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गुटबाजी करते हैं और जो उनकी पसंद का नहीं होता उन्हें गद्दार या असंतुष्ट बता देते हैं. समाजवादी पार्टी का अधिवेशन तो समाप्त हो गया. मुलायम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन भी कर दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से सपा की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी मुहर लगा दी.

उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई की बात वहीं की वहीं रह गई, लेकिन गद्दारों को ठिकाने लगाने की बात बाकायदा अपना असर भी दिखाने लगी है. यानी, आने वाले दिनों में पार्टी में ताकतवर कौन है, इसका संकेत

लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में खूब घमासान मचा था, पार्टी नेतृत्व ने भी बड़े ही मजाकिया तरीके से प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें बार-बार बदला, गुटबाजी और पक्षवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया और पार्टी की सार्वजनिक रूप से छवि खराब की, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हारे तो उसका ठीकरा अपने सिर फोड़ने के बजाय वरिष्ठ निरंकुश नेताओं ने तथाकथित गद्दारों और पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वालों का एक हौव्वा खड़ा किया और उनके मत्थे सारा ठीकरा फोड़ दिया.

और संदेश जहां–जहां पहुंचना चाहिए, वहां–वहां पहुंचने लगा है. पार्टी दफ्तर ने राम गोपाल के निर्देशों पर इतनी तेज़ी से काम करना शुरू किया कि 26 जिलों में पार्टी के कार्यों की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षकों को निर्धारित तिथियों से पहले ही रवाना कर दिया गया. राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने निर्देश दिया था कि नामित पर्यवेक्षक सम्बद्ध जिलों में क्रमशः 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को रवाना होंगे. लेकिन पार्टी दफ्तर ने 25 अक्टूबर को ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह बता दिया कि पर्यवेक्षक उन तारीखों में रवाना हो गये हैं. दफ्तर ने तारीखों का जिक्र भी किया, लेकिन यह ध्यान ही नहीं रखा कि उन्हें दरअसल रवाना कब होना था.

राष्ट्रीय महासचिव ने अपने दूतों को आजमगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, संत रविदास नगर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, कानपुर देहात, संत कबीरनगर, खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, बाराबंकी, कौशाम्बी, चंदौली, उन्नाव, मऊ, वाराणसी, अंबेडकर नगर, लखनऊ, गाज़ीपुर और बलिया जिलों में भेजा है. पर्यवेक्षक संगठन और पार्टी की ज़मीनी हक़ीकत की रिपोर्ट सौंप देंगे. इन रिपोर्टों से यह साफ हो जाएगा कि इन जिलों के किन–किन नेताओं और कार्यकर्ताओं का पत्ता साफ होने वाला है. पर्यवेक्षकों से साफ तौर पर कहा गया है कि गुटबंदी करने वाले या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों की वे रिपोर्ट करेंगे. इस निर्देश के निहितार्थ आसानी से समझे जा सकते हैं. रामगोपाल अपनी बंदूक अखिलेश के कंधों पर रखे हुए हैं और धांय–धांय फायर कर रहे हैं. पार्टी यह कह रही है कि पार्टी के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक स्तर पर, जनहित में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गंभीर हैं, इसीलिए वह इसकी समीक्षा एवं फेरबदल के कार्य में जुटे हुए हैं.

साफ है कि प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के जन विरोधी कार्यकलापों की राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करने वाले नेता या कार्यकर्ता पार्टी विरोधी कार्यकलापों के आरोपों में पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे. वे लोग भी गद्दार साबित होंगे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे में पक्षवाद, निरंकुशता और धांधली के खिलाफ मुंह खोला था या इन मुद्दों पर असंतोष जाहिर किया. उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में खूब घमासान मचा था. पार्टी नेतृत्व ने भी बड़े ही मजाकिया तरीके से प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें बार–बार बदला. गुटबाजी और पक्षवाद के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया और पार्टी की सार्वजनिक रूप से छवि खराब की. लेकिन जब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हारे तो उसका ठीकरा अपने सिर फोड़ने के बजाय वरिष्ठ निरंकुश नेताओं ने तथाकथित गद्दारों और पार्टी विरोधी गतिविधियां करने वालों का एक हौव्वा खड़ा किया और उनके मत्थे सारा ठीकरा फोड़ दिया. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक समीक्षकों का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव का लोकतांत्रिक दौर समाप्त होने की कगार पर है और सत्ता एवं संगठन पर निरंकुशता और राग–दरबारी का चलन हावी होने वाला है. इसी नई परंपरा के आधार पर अब पार्टी की नई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी और नतमस्तक नेताओं–कार्यकर्ताओं के बूते समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी. ■

सपाई ही बन रहे हैं अखिलेश सरकार के लिए मुसीबत : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही अखिलेश सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव सुधार की कवायद में जुटे हैं, पर प्रदेश की अखिलेश सरकार के इक़बाल को चुनौती सपाई ही दे रहे हैं. सरकार बनने से लेकर नसीहतें देने का जो दौर शुरू हुआ था वह आज भी बदस्तूर जारी है. राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में जिस खाकी पर क़ानून व्यवस्था का दारोमदार है उसकी इज्जत तार-तार करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं. आए दिन सत्तारूढ़ दल के लोग राज्य की क़ानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं. मंत्री से लेकर मंत्री के परिजन तक पुलिस को अपमानित कर रहे हैं. अब तक 15682 से अधिक स्थानांतरण कर चुकी अखिलेश सरकार राज्य में नौकरशाही के लिए काम का माहौल ही नहीं बना पा रही है. भ्रमित सरकार यह भी तय ही नहीं कर पा रही है कि किसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर रखना है किसे पुलिस अधीक्षक के पद पर रखना है. यही कारण है कि तमाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पदों पर पुलिस अधीक्षक पद की अर्हता रखने वाले लोग तैनात हैं. तमाम जगहों पर पद पुलिस अधीक्षक का है किन्तु तैनाती वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अर्हता रखने वाले व्यक्ति की है. राज्य में हालात यह है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश रंगदारी और बेतहाशा कब्जों से दहल रहा है. जो लोग इन कामों में लिप्त हैं, कहीं न कहीं उन्हें सत्तारूढ़ दल के नेताओं का संरक्षण मिल रहा है.

नए संसदीय बोर्ड के कर्णधार

समाजवादी पार्टी के नवगठित संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के अलावा अन्य सात सदस्य मनोनीत किए गए हैं. इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. संसदीय बोर्ड के सचिव प्रो. रामगोपाल यादव ही होंगे. मोहम्मद आज़म खान, शिवपाल यादव, किरनमय नंदा, रवि प्रकाश वर्मा और जो. एंटोनी को संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा और शिवसेना के विरोधी सुर

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपना कट्टर सुर मद्धम करती जा रही है. लेकिन भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना अपनी भाषा में उतनी ही तल्खी लाती जा रही है. भाजपा मुस्लिमों को लुभाने या उन्हें न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है तो शिव सेना कट्टर हिंदूवादी तेवर अख्तियार कर एक विरोधाभासी राजनीतिक माहौल बना रही है. कुछ तटस्थ विश्लेषक इसे नूरा-कुश्ती भी बता रहे हैं. उत्तर प्रदेश में भाजपा यह संदेश दे रही है कि सांप्रदायिक एकता के संदेश को लेकर आगे बढ़ें तो देश और खुशहाल हो सकता है और तरक्की कर सकता है. दूसरी तरफ शिवसेना ने तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के प्रति चिंता जताते हुए हिंदुओं से अपनी आबादी बढ़ाने का आह्वान किया है और यह घोषणा की है कि 10 बच्चों वाले परिवार को शिवसेना आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेगी. अभी यह योजना उत्तर प्रदेश के लिए लागू की जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे इसे देशभर में लागू किया जाएगा.

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रोचक वाकया हुआ. प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक हिंदू-मुस्लिम एकता के पुरातन कसीदे पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ शिव सेना 10 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू परिवारों के लिए पुरस्कार की घोषणा कर रही थी. यूपी के राज्यपाल बना कर भेजे गए भाजपा के दूत राम नाइक ने मोहर्रम के मौके पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोहर्रम के महीने में हम इमाम हुसैन को याद करते हैं. यह दुख का क्षण होता है. मुस्लिमों के अलावा हिन्दू और ईसाई धर्म में भी दुःख के क्षण हैं, जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना और भगवान राम को युवराज होते हुए भी वनवास पर भेजा जाना. नाइक ने कहा कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुःख बाटने से कम होता है. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए और कहा कि लखनऊ में हिन्दू राजा झाऊलाल ने इमामबाड़ा बनवाया तो मुस्लिम नवाबों ने मंदिरों के लिए धन और स्थान दिए. यह एकता का संदेश महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यदि हम सांप्रदायिक एकता के संदेश को लेकर आगे बढ़ें तो हमारा देश आगे और प्रगति कर सकता है. उन्होंने अपील भी की कि धार्मिक एकता और सौहार्द का संदेश देने वाले आयोजन अधिक से अधिक किए जाएं. राज्यपाल ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने में लगे आदित्य कुमार को और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए मनीष तिवारी को निशान-ए-इमाम हुसैन अवार्ड से सम्मानित किया.

दूसरी तरफ शिव सेना यह घोषणा कर रही थी कि किसी हिंदू परिवार की एक इकाई में यदि 10 बच्चे हों तो उस परिवार को 21 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का मुक़ाबला करने के लिए शिवसेना ने यह आह्वान किया है. शिवसेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल शाह ने कहा कि उनकी पार्टी परिवार नियोजन के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है. इसके तहत पहली खेप में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होंगे. उसके बाद आंदोलन को और जुझारू किया जाएगा. आंदोलन में पार्टी कार्यकर्ता राज्यभर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराएंगे. शिव सेना का आरोप है कि सिर्फ हिंदू पुरुष और महिलाएं ही नसबंदी करा रहे हैं जबकि दूसरे समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और नसबंदी से बच रहे हैं. शिवसेना नेता सुरेंद्र शर्मा ने हिंदुओं से अपील की कि वे कम से कम दस बच्चे जरूर पैदा करें. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे. इस आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा. शिवसेना की प्रदेश इकाई ने उन हिंदू दंपतियों को 21 हजार रुपये नगद का पुरस्कार देने का फैसला किया है, जिनके 10 या उससे अधिक बच्चे हैं. ऐसे दंपतियों को नकद राशि के साथ-साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें हिंदू हित में आबादी बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की जाएगी. इसके लिए नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित होंगे. पार्टी की सभी जिला इकाइयों को 10 बच्चों वाले परिवारों की पहचान करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. शिव सेना ने सात साल पहले भी लखनऊ में इस तरह का कार्यक्रम चलाया था. उस समय उन 10 या उससे ज्यादा बच्चों वाले हिंदू दंपतियों को 11 हजार रुपये दिये गए थे. ■

> पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रोचक वाकया हुआ. प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक हिंदू-मुस्लिम एकता के पुरातन कसीदे पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ शिव सेना 10 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू परिवारों के लिए पुरस्कार की घोषणा कर रही थी. यूपी के राज्यपाल बना कर भेजे गए भाजपा के दूत राम नाइक ने मोहर्रम के मौके पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोहर्रम के महीने में हम इमाम हुसैन को याद करते हैं.

आबादी बढ़ी प्रतिनिधित्व घटा

साल 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होने से मुस्लिम मतदाता पहले से चिंतित हैं. तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तमाम तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का हश्र वह देख चुके हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों ने प्रदेश में 99 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन इनमें से केवल सात उम्मीदवार ही संसद पहुंचने में सफल हो सके . लेकिन 2014 में मुस्लिम सांसदों की संख्या शून्य पर पहुंच गई. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है. कुछ लोकसभा क्षेत्र में तो मुस्लिम आबादी कुल मतदाताओं में 17 से 18 फीसदी तक है, जबकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20 फीसदी के करीब है. प्रदेश की मुज़फ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बदायूं, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, ग़ाजीपुर, फतेहपुर सीकरी, बलरामपुर, जौनपुर, संभल, शाहाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं की लगभग 25 फीसदी से भी ज्यादा है. लेकिन इन क्षेत्रों से भी मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है. बीते कुछ चुनावों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाताओं पर भी राजनीतिक दलों के मुस्लिम कार्ड बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं परिणामस्वरुप इन मुस्लिम आबादी बहुल सीटों पर भी दूसरे समुदाय के लोग जीत दर्ज करने में सफल हो रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में साल 1999 के लोकसभा चुनावों के समय मुस्लिम आबादी कुल आबादी की 14 फीसदी थी. इसमें लगातार इजाफा हुआ है.

2004 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम आबादी 17 फीसदी से ज्यादा हो गई. प्रदेश की तमाम सीटों पर मुस्लिम आबादी 2009 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20 फीसदी से ज्यादा हो गई, लेकिन जनसंख्या के साथ इनकी जीत के ग्राफ में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई. ■

अपने ही घर में बेगानी नायाब शख्सियतें

राकेश कुमार यादव

फ़ैज़ाबाद के लोगों ने कृतघ्नता की हद पार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. फैज़ाबाद जनपद में जन्मी विश्व विख्यात मल्लिका-ए-तरन्नुम बेग़म अख्तर को ही नहीं बल्कि समाजवाद के पुरोधा आचार्य नरेन्द्र देव को भी यहां के लोगों ने भुला दिया है. बेग़म अख्तर और आचार्य नरेन्द्र देव की ऐतिहासिक कोठियां स्मारक बनाए जाने के बजाय धनाढ्यों के हाथों बेच डाली गईं. जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय नेता डॉ. निर्मल खत्री, आचार्य नरेन्द्र देव को अपना नाना बता-बता राजनीतिक सीढ़ियां तय करते रहे. जनता की मांग पर फैज़ाबाद नगर पालिका ने बेगम अख्तर मार्ग के नाम से एक मार्ग का नामकरण कर उन्हें नए सिरे से याद करने की कवायद शुरू की है, लेकिन बेगम अख्तर और आचार्य नरेन्द्र देव की कोठी स्मारक में तब्दील होगी या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता. वैसे, भारत सरकार ने 1994 में बेगम अख्तर पर डाक टिकट जारी कर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी. केन्द्र की मौजूदा भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयत्नों से बेगम अख्तर के नाम पर 100 रुपये का सिक्का जारी कर केंद्र सरकार ने विभूतियों के प्रति आस्था व्यक्त की है.

सुना करो मेरी जान उनसे उनके अफसाने, सब अजनबी हैं यहां, कौन किसको पहचाने, मशहूर गजल के ये बोल मल्लिका-ए-तरन्नुम बेगम अख्तर पर सटीक बैठते हैं. यह गजल गाते समय बेगम अख्तर ने कभी सोचा भी न होगा कि जिस मिट्टी में वह पैदा हुईं, पली-बढ़ीं और गाय की परवान चढ़ी, वही जगह उन्हें भुला बैठेगी. फैज़ाबाद जिले के भदरसा कस्बे में जहां वह पैदा हुईं वहां और शहर के रीडगंज मोहल्ले में जिस कोठी में उनकी गायकी परवान चढ़ी, लोगों ने उसे बिसार दिया है. भदरसा में उनके वालिद का मकान जमींदोज हो चुका है, परंतु रीडगंज की कोठी अभी भी बेगम अख्तर की याद ताजा कर देती है. बेगम अख्तर के फैज़ाबाद छोड़ने और उनके इंतकाल के बाद कई बार यह आलीशान कोठी बिकी और हर बार लोगों ने इसमें बेग़म अख्तर स्मारक बनाए जाने की वकालत की. शायद इसी मांग की वजह से जिसने भी कोठी खरीदी उसने बार-बार इसे बेच डाला.

अख्तरी बाई फैज़ाबादी, बेगम अख्तर के नाम से मशहूर यह शख्सियत कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनकी मां मुश्करी बाई अपने जमाने की मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका थीं. उनके पिता असगर हुसैन पेशे से वकील थे, परंतु इनके चाचा उस्ताद इमदाद खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे. मां और चाचा का असर बेगम अख्तर पर बचपन से ही पड़ने लगा था. इनकी दो बहनें जोहरा और बीबी थीं. संगीत समारोहों में इनकी वालिदा और चाचा का कलकत्ता सहित देश के विभिन्न शहरों में आना जाना लगा रहता था. 15 साल की उम्र में ही 1930 में बिहार में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन की मुख्य अतिथि सरोजनी नायडू थीं. बेगम अख्तर की गायकी को सुनकर सरोजनी नायडू इतनी प्रभावित हुईं थीं कि उन्होंने अख्तरी बाई फैज़ाबादी को एक साड़ी भेंट की थी. इस कार्यक्रम में अख्तरी बाई ने तूने बूटे हरजाई कुछ ऐसी अदा पाई, ताकता तेरी सूरत हरेक तमाशाई और दादरा सुंदर साड़ी मोरी मायके मैलाई गयी, गजल सुनाई सुनाई थी. 1945 में लखनऊ में जब उन्होंने दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, गजल सुनाई तो बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी उन पर इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने उनसे निकाह ही कर डाला. इसी के साथ उनको नया नाम बेगम अख्तर मिला. ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, उनकी सबसे मशहूर गजल थी. 1930 और 1940 के बीच उन्होंने हिन्दी फिल्म एक दिन की बादशाहत, नल दमयंती, अमीना, मुमताज बेगम, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर आदि फिल्मों में अभिनय भी किया. 1942 में बनी महबूब खान की फिल्म रोटी उनकी प्रसिद्ध फिल्म थी. इस फिल्म में उन्होंने 6 गीत गाए थे. संगीत और अदाकारी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी आवार्ड 1972, पदमश्री 1968 में मिला. 30 अक्टूबर 1974 को अपनी मखमली आवाज लोगों को उपहार देकर वह इस दुनिया से विदा हो गईं. भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत 1975 में पद्मभूषण सम्मान से नवाजा. संगीत और फिल्म की दुनिया में अपनी अहम शख्सियत दर्ज करने वाली बहू बेगम की रूह आज फैज़ाबाद के बाशिन्दों की बेवफाई पर आंसू बहा रही है. गुलदस्ता प्रोडक्शन के संस्थापक/रंगकर्मी मंजर मेंहदी का कहना है कि चूंकि बेगम अख्तर की कोठी बिक चुकी है इसलिए उसे स्मारक बनाने की मांग करना अब कोई मायने नहीं रखता. यही वजह है कि हम प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि फैज़ाबाद में मल्लिका-ए-गजल बेग़म अख्तर संगीत विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे शास्त्रीय संगीत, ग़जल व ठुमरी गायकी को सीखने का मौका नवोदित गायकों को मिलें. हमारी यह भी मांग है कि इस संगीत विद्यालय में एक संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें बेगम अख्तर की दुर्लभ गजलें, ठुमरी, दादरा के आडियो, वीडियो तथा फिल्मों के फुटेज रखे जाएं.

बेगम अख्तर की कोठी की ही तरह समाजवादी आंदोलन के पुरोधा आचार्य नरेन्द्र देव की कोठी को भी उनके वारिसों ने बेच डाली. गुलाबबाड़ी मकबरा के ठीक पीछे बनी आचार्य नरेन्द्र देव की ऑलीशान कोठी अपनी भव्यता का परिचय आज भी दे रही है. इस कोठी के नये मालिक ने इसमें विद्यालय स्थापित कर रखा है. हां इतना जरूर है कि यह विद्यालय आचार्य नरेन्द्र देव के नाम से ही संचालित है. आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था. अपने जमाने के चर्चित विद्वान नरेंद्र देव ने महात्मा गांधी के आन्दोलन में हिस्सा लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया. फैज़ाबाद जनपद से उनका विशेष लगाव रहा क्योंकि उनके परिवार के तमाम लोग इस शहर के वाशिंदे थे. 1923 में जब उन्होंने परास्नातक की डिग्री हासिल की तो परिवारीजनों के दबाव में न चाहते हुए भी उन्होंने वकालत की शिक्षा हासिल की और फैज़ाबाद में आकर 1915 से 1920 तक वकालत की. वकालत के दौरान ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया और डॉ. लोहिया के समकक्ष फैज़ाबाद के नेताओं में उनकी गणना होने लगी. आचार्य नरेन्द्र देव हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पाली, प्राकृत और बांग्ला आदि भाषाओं के जानकार थे. उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक उल्लेखनीय पुस्तकों की रचना की जिनमें राष्ट्रीयता और समाजवाद, समाजवादः लक्ष्य तथा साधना, समाजवाद का बिगुल, भारतीय संस्कृति का इतिहास, समाजवाद, बोधचर्या तथा महायान और अविधर्म कोष पुस्तकें चर्चा की विषय बनीं. उन्होंने जनवाणी, संघर्ष, जनता, समाज आदि पत्रिकाओं का संपादन-प्रकाशन भी किया. उन्होंने इतिहास, राजनीति, समाज शास्त्र आदि विषयों पर भी लेखन किया परंतु उनका लेखन साहित्यिक तत्वों से परे नहीं था. हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही. 1913 में मर्यादा पत्रिका में उन्होंने हमारा हिन्दी के प्रति कर्तव्य लेख लिखा. इस लेख में उन्होंने कहा कि हिन्दी प्रेमी भाषा को देशव्यापी बनाने के लिए देशी भाषाओं के समान हिन्दी साहित्य के भंडार को भी समृद्ध करें.

देश की आजादी के आंदोलन में आचार्य नरेन्द्र देव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 1930 के नमक सत्याग्रह में, 1932 के राष्ट्रीय आंदोलन, 1931 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ीं. कांग्रेस की नीतियों से जब वह 1934 में असंतुष्ट हुए तो उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की. आचार्य नरेन्द्र देव मार्क्सवादी-समाजवादी थे. उनका कहना था कि युग की दो मुख्य प्रेरणाएं राष्ट्रीयता और समाजवाद हैं. किसानों के हित के वह प्रबल पक्षधर थे. काशी विद्यापीठ में उन्होंने आचार्य और कुलपति की हैसियत से भी कार्य किया. इन सबके बावजूद आचार्य नरेन्द्र देव का जुड़ाव फैज़ाबाद से रहा और वह समय-समय पर फैज़ाबाद आकर राष्ट्रीय आंदोलनों को गतिशील करते रहे. उनका निधन 19 फरवरी 1956 को हो गया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मल खत्री यह तो कहते रहे कि आचार्य नरेन्द्र देव उनके नाना हैं. परंतु उन्होंने फैज़ाबाद में उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने का प्रयत्न नहीं किया. आचार्य नरेंद्र देव के पुत्र हर्षवर्धन ने फैजाबाद स्थित उनकी ऐतिहासिक कोठी भी बेच डाली. इस पर भी डॉ. निर्मल खत्री ने कोई आपत्ति नहीं की. आज स्थिति यह है कि फैजाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृतियों को संजोने और उनकी रचित पुस्तकों का अवलोकन करने के लिए कोई संग्रहालय नहीं है. ■

लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना पर ग्रहण लगा

रेनु शर्मा

उत्तराखंड में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध अब भी जारी है. नई दिल्ली में नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से चल रही लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना को नए सिरे से शुरू करने का मुद्दा उठा. लेकिन दिल्ली दरबार ने इसे कोई तव्वजो नहीं दी. यहां तक कि कुछ पर्यावरणविदों ने इसका तीखा विरोध किया. इससे पहले कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक माह पहले हुई आला अधिकारियों की बैठक में लोहारीनाग पाला को संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाने पर सहमति बन चुकी थी. यह परियोजना एनटीपीसी की थी, जिसे पर्यावरणविदों के विरोध के बाद वर्ष 2010 में रद्द कर दिया गया था.

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि इस बार बैठक अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने की चर्चा थी और केंद्रीय पर्यावरण व ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इसी आशय की सूचना राज्य सरकार को भेजी गई थी. इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही थी कि ईको सेंसिटिव जोन से बाहर प्रस्तावित अथवा पूर्व में रद्द की गई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. खासकर 600 मेगावाट क्षमता की लोहारीनाग पाला परियोजना को नए सिरे से हरी झंडी मिलने की उम्मीद थी. एक महीने पहले नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि लोहारीनाग पाला परियोजना पर एनटीपीसी के साथ उत्तराखंड जल विद्युत निगम भी काम करे. परियोजना को संयुक्त उपक्रम के तौर पर तैयार किया जा सकता है. इसी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक में शामिल हुए. ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में लोहारीनाग पाला सहित अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का मुद्दा उठा, लेकिन दिल्ली के पर्यावरणविदें के विरोध के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी. विरोध करने वालों में वही लोग शामिल थे, जो पूर्व में बड़ी परियोजनाओं के विरोध में राज्य में प्रदर्शन कर चुके हैं.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि ईको सेंसिटिव जोन में 25 मेगावाट क्षमता तक के हाइड्रो प्रोजेक्टों की स्वीकृति का अधिकार मिलने के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा. रही बात बड़ी परियोजनाओं की तो राज्य सरकार निरंतर प्रयास करेगी कि केंद्र सरकार प्रतिबंधों में शिथिलता दे. चूंकि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता से ही पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लग सकेंगे और मैदानी क्षेत्रों में उद्योगों का तेजी से विस्तार होगा. ■

गांव की पीड़ा जानने पैदल निकला एक कर्मयोगी

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत गांवों का देश है, किसान हम सबके अन्नदाता हैं, नर ही नारायण है, गरीबों में ही भगवान बसता है. संत सीताराम केदियाल की पीड़ा यही है कि हम यह सब कहते तो हैं लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित कोई समाज है तो वह है किसान और वह समाज जो गांवों में रहता है. गांवों में रहने वाला समाज आज सबसे अधिक उपेक्षित है, जबकि वही हमें पालता है. भारत के गांवों में रहने वाले उपेक्षित समाज की पीड़ा और उनकी वास्तविक दिक्कतें को समझने के लिए दक्षिण के एक संत निकले हैं. जो गांव-गांव जाकर लोगों के दर्द को साझा करते हैं और देश को समझने की कोशिश करते हैं, उनके संरक्षण, संवर्धन एवं स्वालंबन के लिए कुछ सोचते हैं यह संत मां भारती की पदयात्रा पर निकले हैं. संत सीताराम केदियाल कर्नाटक के रहने वाले हैं.

एक आदर्श गांव कैसा हो इसे देखने-समझने के इरादे से केदियाल ने छह अगस्त 2012 को कन्याकुमारी से अपनी पदयात्रा प्रारम्भ की थी. विभिन्न राज्यों और चारों धाम एवं प्रमुख धार्मिक केन्द्रों से होते हुए वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी भी आए. उनकी यात्रा नैमिशारण्य, चित्रकूट होते हुए पिछले दिनों तीर्थराज प्रयाग के जफरा पहुंची. वे प्रयाग क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कर काशी होते हुए गोरक्षपीठ और काठमांडू जाएंगे और वहां से बिहार में प्रवेश करेंगे. संत केदियाल की यात्रा का लक्ष्य है गांवों में जन-जागरण करना. वे मानते हैं कि भारत गांवों का देश है लेकिन समाज की मानसिकता के कारण गांवों का जीवन संकट में है. अपनी विभिन्न संपदाओं, जन, भू, जीव, जल, वन, गौ, ग्राम, ऊर्जा, जैव जैसी धरोहरों के साथ भारत के गांव अब अपनी सांस्कृतिक विरासत भी खोते जा रहे हैं. केदियाल कहते हैं कि अपनी सारी विरासत छोड़कर गांवों के लोग शहर की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं. ग्राम रचना पुनः स्थापित हो, ग्रामीण संस्कार, संस्कृति, रीति-रिवाज, बोली-भाषा का जागरण करते हुए उसके संरक्षण व संवर्धन के साथ अपने गांव जीवंत इकाई के रूप में फिर से दिखाई दें, इस यात्रा का यही प्रमुख उद्देश्य है.

संत केदियाल अपनी यात्रा में रोजाना 12 किलो मीटर चलते हैं. इस दौरान मार्ग में जन-जागरण के विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है. अभी तक उन्होंने नौ हजार किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है. अभी इन्हें 12 हजार किलोमीटर और चलना है. इनकी पदयात्रा शुरूआत से अब तक रुकी नहीं है. यात्रा के दरम्यान संत केदियाल केवल दलित के घर में ही रात्रि भोजन करते हैं. जिन्हें आम तौर पर गांवों में अछूत माना जाता है, उनके घर में ही भोजन करना जन-जागरण के उद्देश्य का हिस्सा है. पदयात्रा के दौरान जहां रात हो जाती है, वहीं इनका विश्राम होता है. यात्रा शुरु करने के पहले संत केदियाल गाय का दूध पीते हैं और 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं. कर्नाटक के पुत्तूर जिले में पैदा हुए सीताराम केदियाल उच्च शिक्षा ग्रहण करने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए. प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक रहते हुए उन्होंने सेवा का खूब काम किया. 63 साल की उम्र में उन्होंने संघ प्रमुख डॉ. मोहन मधुकर राव भागवत से अनुमति लेकर भारत परिक्रमा पदयात्रा शुरू की. वे पिछले ढाई साल से पदयात्रा पर हैं. ■

उत्तराखंड

शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुर्की वारंट जारी

राजकुमार शर्मा

पीडीएफ के कोटे से प्रदेश में मंत्री बने शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी अब तक अदालत को ठेंगा दिखाते रहे हैं. बलवा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अदालत में पेश न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत ने शिक्षामंत्री नैथानी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया है. हाल ही में पुलिस ने मंत्री के आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था. मंत्री जी को इतना अहंकार है कि वह सरकार में रहकर भी सरकार, पुलिस एंव अदालतों को धत्ता बताते रहते हैं. सरकार चलाने की मजबूरी का लाभ उठाकर मंत्री पद पाने के बाद जिस विभाग के भी मंत्री बने हैं उस विभाग में जम कर लूट की है. सरकारी सुरक्षा, सरकारी आवास का हर सुख भोगने वाले मंत्री के मामले में सरकार और प्रशासन अब तक आंखों पर पट्टी बांधे हुए है.

गौरतलब है कि विकल्पधारी शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजने सहित कई मांगों के समर्थन में प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने मंत्री प्रसाद के नेतृत्व में दस अप्रैल 2001 को विधानसभा की ओर कूच किया था. उन पर आरोप है कि रिस्पना पुल के पास जुलूस को रोकने पर बेरोजगारों ने पुलिस पथराव कर दिया था और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी. जिसमें सरकारी संपत्ति को लाखों की क्षति हुई थी. थाना डालनवाला पुलिस ने मंत्री सहित 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था. सरकारी संपत्ति का नाश करने वाले को मंत्री पद मिला है तब भी वह क़ानून का आदर नहीं कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यसभा चुनाव

कांग्रेस को भितरघात से बचना होगा

प्रदेश में राज्यसभा सांसद के लिए होने वाले चुनाव में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा खाली हो रही सीट इस बार पूरी तरह कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है. राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव इस बार पूरी तरह एकतरफा नज़र आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा में भाजपा का संख्याबल पहले से भी कम हो गया है. और भाजपा बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है. माना जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव में ज्यादा उछल कूद भी नहीं मचाएगी. बावजूद इसके भाजपा के बड़बोले नेता अपने बयानों से ही राजनीति को गरम रखना चाहते है. नवंबर माह में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना निश्चित है. नंबर गेम में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे होने के कारण उत्साहित दिख रही है. कांग्रेस में तो बस इस बात की लड़ाई है कि कौन उम्मीदवार बने. भाजपा के लिए यह चुनाव हुंकार भरने लायक भी नहीं रहा. मुख्यमंत्री हरीष रावत ने साफ कहा है कि पार्टी हाईकमान जिसे प्रत्याषी घोषित कर देगा, उसका सांसद बनना तय है. कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर एक राय बनाना मुश्किलों भरा है. विजय बहुगुणा अपनी उम्मीदवारी को लेकर फिर सक्रिय हो गए हैं. मुख्यमंत्री पद अपने पुत्र साकेत के दलाली से उपजी बदनामी के कारण छोड़ने के बाद से बहुगुणा सितारगंज विधानसभा से इस्तीफा दे राज्यसभा की उम्मीदवारी चाह रहे हैं. हरीश किसी भी हालत में नहीं चाहते कि बहुगुणा विधायक का पद छोड़ें और राज्य में फिर चुनाव हों. इसी कारण हरीश रावत का खेमा शुरू से ही उनकी दलील को खारिज कर उन्हें सितारगंज विधानसभा सीट नहीं छोड़ने दे रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हाल ही में दलित और अल्पसंख्यक उम्मीदवार की बात उठाकर बहुगुणा की राह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में भी सरफुड़ौवल कम नहीं है. अंबिका सोनी,कपिल सिब्बल,राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद की दावेदारी के समक्ष विजय बहुगुणा की दावेदारी कहीं नहीं टिक रही है. लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल काम है. कार्पोरेट के सहयोग से विजय को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनवाने वाली डॉ. रीता बहुगुणा जोशी की सक्रियता कुछ भी गुल खिला सकती है. जीत के लिए जरूरी संख्या बल नहीं होने के कारण भाजपा को तमाशबीन ही बना रहना पड़ेगा. समीकरण इस समय कांग्रेस के पक्ष में है. फिर भी सतपाल महराज खेमा के कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थामने के बाद विधायकों का एक दल जिसे आज भी महराज समर्थक माना जाता है जिसमें इनकी धर्मपत्नी अमृता रावत भी शामिल हैं महाराज के इशारे पर खेल कर सकती हैं. पीडीएफ का मजबूत साथ हरीश का हौसला बढ़ा रहा है. राजनीति के जानकार मानते हैं कि हर तरह से कांग्रेस और हरीश का ही पलड़ा भारी है. इस बार के राज्यसभा चुनाव की स्थिति भाजपा के लिए पिछले चुनाव से भी कमजोर साबित होगी. विधानसभा की तीन सीटों पर हुए उप-चुनाव में भाजपा ने अपनी डोईवाला व सोमेश्वर सीट भी खो दी. कांग्रेस ने पीडीएफ के साथ ही उप-चुनाव में तीन सीट जीतकर 35 संख्याबल पा लिया है. भाजपा विधायकों की संख्या मात्र 28 रह गई है. एक तरफा होने वाले संभावित इस चुनाव में भाजपा नेता बल एंव छल द्वारा हरीश को नीचा दिखाने के लिए कोई भी खेल, खेल सकते हैं. राजनीति के सुजान मोदी को चुनौती देने में माहिर हरीश हर हाल में कांग्रेस की गोट लाल करना चाहते हैं, पार्टी को जीत के लिये केवल भितरघात से बचना होगा. ■

-राजकुमार शर्मा

खाली होने लगे हैं नीति घाटी के सीमांत गांव

तिब्बत सीमा से सटी नीति घाटी के जनजातीय परिवार अब ठंड बढ़ जाने से अपने सीमावर्ती मूल गांवों से शीतकालीन प्रवास के लिए घाटियों वाले स्थानों में लौटने लगे हैं. अगले कुछ दिनों बाद माणा घाटी के जनजातीय परिवार भी छह माह के ग्रीष्मकालीन प्रवास के बाद शीतकालीन प्रवासों में लौट आएंगे. तिब्बत सीमा से सटी नीति और माणा के जनजातीय परिवार शीतकाल में इन गांवों के बर्फ से आच्छादित होने और हाड़ कंपकपाती ठंड के कारण निचले अथवा घाटी वाले स्थानों में प्रवास करते हैं. ग्रीष्मकाल के छह माह जनजातीय लोग अपने मूल गांवों में निवास कर खेती करते हैं. शीत काल में इन स्थानों पर भारी बर्फबारी होती है इस वजह से यहां रहने वाले लोगों को आज भी घुमक्कड़ों जैसा जीवन यापन करना पड़ता है. चमोली जिले में नीति और माणा घाटियों में ही भोटिया जनजाति के लोगों के खेत और मकान स्थित हैं.

शीतकाल शुरू हो गया है और तिब्बत सीमा से सटी नीति घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है तो इन गांवों के लोग निचले और घाटी वाले (गंगाड़) क्षेत्रों की ओर लौटने लगे हैं. इस कारण अब धीरे-धीरे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में सन्नाटा भी पसरने लगा है. नीती व माणा घाटी में शीतकाल में भी आईटीबीपी तथा सेना के जवान ही सरहद की रक्षा में तैनात रहते हैं, अब जबकि जनजाति परिवारों के लोग निचले क्षेत्रों को रूख करते हैं तो इनके मकान और सामानों की सुरक्षा भी एक तरह से सेना व आईटीबीपी के जवान ही करते हैं. यह सेना और स्थानीय लोगों के बीच परस्पर मैत्री पूर्ण संबंधों का ही परिणाम है कि द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में जानी जाने वाली जनजातियां आज भी सरहदों की रखवाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. वैसे वर्षा काल में भी इन घाटियों में रह रहे जनजाति परिवार मस्त रहते हैं. इस दौर में इन घाटियों में सांस्कृतिक व धार्मिक चहल-पहल देखने को मिलती है. नई पीढ़ी के लोग नौकरियों में होने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपने मूल गांवों में कदम रखने से हिचकिचा रहे हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी मिट्टी से मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में प्रवास कर वे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में भी मददगार साबित हो रहे हैं. वर्ष 1962 के चीन युद्ध के बाद चमोली के लोगों की सेकेंड डिफेंस लाइन की भूमिका को देखते हुए इन्हें गुरिल्ला प्रशिक्षण के साथ ही बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी. महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी को दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार किया जाता था. यह अलग बात है कि बाद को परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इस तरह का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया. इस सबके बावजूद आज भी सरहद पर सटी आवादी सीमा प्रहरी के रूप में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज किए हुए है. 1962 से पूर्व नीति और माणा घाटियों में बसे भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित कर जीवन यापन और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते थे, इस युद्ध के बाद व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के चलते अब लोग कारोबारी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं. इसके बावजूद सीमांत क्षेत्रों में रह कर वे अपनी खेती बाड़ी, भेड़ पालन के साथ ही ऊन के कारोबार के जरिए वे अपनी आजीविका संचालित कर रहे हैं. यही नहीं सरहदों पर तैनात सेना और अर्धसैन्य बलों की हौसला-अफजाई भी वे कर रहे हैं, अब जबकि ज्यादातर परिवार घाटियों अथवा निचले स्थानों को लौटने लगे हैं तो इन क्षेत्रों में शीतकाल में खासी रौनक लौटने की संभावना भी बढ़ गई है. ■

-रेनु शर्मा

रायबरेली जनपदवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
डॉ संजय रस्तोगी
(एम.बी.बी.एस.),
(डी.ओ.एम.एस.), (डी.एन.बी.)
नेत्र रोग विशेषज्ञ एंव फैको सर्जन
अध्यक्ष
प्राइवेट डाक्टर्स एसोसिएशन रायबरेली
पूर्व अध्यक्ष
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली
प्रतिष्ठान
श्री कृष्णा नर्सिंग होम
जेल गार्डेन रोड रायबरेली
फोन. 0535-220556

रायबरेली जनपदवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
आकाश सेलेक्शन
हाउस ऑफ हाई क्वालिटी
स्कूल प्रोडक्ट्स
घंटाघर कोतवाली रोड
रायबरेली
मोबाइल नं- 09956587414
09161534545
■ स्कूल ड्रेसेस
■ स्कूल शूज
■ स्कूल बैग्स
■ फंक्शन ड्रेसेस

कार्यालय नगर पंचायत
महराजगंज-रायबरेली
पत्रांक : /न.पं.मह/विज्ञापन /2014-15 दिनांक : 20 अक्टूबर 2014
दीपावली के शुभ अवसर पर नगर पंचायत महराजगंज आप सभी नगरवासियों तथा क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करती है। तथा आप सभी से निम्न अपेक्षाएं करती है।
1. यह नगर आपका है इसे स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
2. अपने समस्त बकाया करों का समय से भुगतान करें।
3. किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के न करें।
4. किसी प्रकार की सार्वजनिक भूमि, मार्ग, नाला, नाली पर अतिक्रमण न करें।
5. जन्म-मृत्यु का पंजीकरण समय से दर्ज करायें।
(सुरेश कुमार मौर्य) अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत महराजगंज रायबरेली
समस्त सदस्यगण नगर पंचायत महराजगंज रायबरेली
सरला साहू अध्यक्ष नगर पंचायत महराजगंज रायबरेली